ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

दाल गल गई क्या?

भारतीयों को दालें बहुत पसंद हैं। भारतीय परिवार रोजाना दाल बनाते हैं। दालों को लेकर मुहावरे भी काफी लोकप्रिय हैं। दे दाल में पानी, जूतियों में दाल बंटना, दाल में काला या दाल गल गई आदि मुहावरे आज बोलचाल में काफी प्रचलित हैं। दाल अब गरीबों का ही खाना नहीं, बल्कि अमीरी के अमृत्व को भी प्राप्त कर चुकी है। दाल जो निभे नाल, यह सच है कि दाल आम आदमी की पसंद है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील में अमेरिका ने चुपचाप फैक्ट शीट यानि तथ्य पक्ष में कई बिन्दु बदल दिए हैं। खासतौर पर दालों को टैरिफ की सूची से हटा दिया गया है। 500 अरब डॉलर की खरीद को लेकर पक्का वादा जैसी भाषा को नरम बनाया है और डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने का दावा भी वापिस ले लिया है। फैक्ट शीट का नया वर्जन जारी होने के बाद यह साफ है कि भारतीय दालें संरक्षित रहेंगी और यह भी नहीं कि 500 अरब डॉलर का आयात भारत द्वारा किया ही जाएगा। विपक्ष और ट्रेड डील के आलोचक इस बात को लेकर शोर मचा रहे थे कि भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया है जिससे हमारा कृषि क्षेत्र और किसान प्रभावित होंगे और 500 अरब डॉलर की खरीद की प्रतिबद्धता को लेकर भी हमारा व्यापार घाटा बढ़ जाएगा।

केन्द्र सरकार लगातार स्पष्ट कर रही है कि भारत के कृषि क्षेत्र को पूरी तरह संरक्षण दिया गया है और कृषि उत्पादों को ट्रेड डील से बाहर रखा गया है। अमेरिकी रुख में नरमी से अब भारतीय किसानों को अमेरिकी दालों के साथ प्रतिस्पर्धा से कोई खतरा नहीं होगा। दालों की खेती से लाखों किसान जुड़े हुए हैं इसलिए यह बदलाव बड़ी राहत की खबर है। पहले कहा गया था कि भारत अमेरिका से हर वर्ष 9 लाख करोड़ का आयात करेगा लेकिन अब कहा गया है कि भारत ऐसा करने का इरादा रखता है। पहले यह एक पक्का सौदा जैसा लग रहा था, अब यह सम्भावित योजना जैसा लग रहा है। अब भारत पर शर्तों का दबाव कम हो गया है। अब यह खरीद विमान, तकनीकी समान, ऊर्जा, कीमती धातुएं और कोयले जैसे क्षेत्रों से जुड़ी बताई गई है। संशोधित फैक्ट शीट से यह स्पष्ट है कि ट्रेड वार्ता में कुछ पेंच अभी भी बरकरार हैं और भारत ने वार्ता में अपनी रणनीतिक मजबूती बरकरार रखी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका में दाल पूरी तरह से गल गई है यानि बात पूरी तरह से बन गई है या अभी कुछ बिन्दु बाकी हैं। क्या ट्रम्प भारत पर मेहरबानी कर रहे हैं? या वह भारत के महत्व को समझते हैं। ट्रम्प जैसे अस्थिर मानसिकता वाले राजनीतिज्ञों पर कितना भरोसा किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार लगातार स्पष्ट कर रही है कि भारत के कृषि क्षेत्र को पूरी तरह संरक्षण दिया गया है और कृषि उत्पादों को ट्रेड डील से बाहर रखा गया है। अमेरिकी रुख में नरमी से अब भारतीय किसानों को अमेरिकी दालों के साथ प्रतिस्पर्धा से कोई खतरा नहीं होगा। दालों की खेती से लाखों किसान जुड़े हुए हैं इसलिए यह बदलाव बड़ी राहत की खबर है। पहले कहा गया था कि भारत अमेरिका से हर वर्ष 9 लाख करोड़ का आयात करेगा लेकिन अब कहा गया है कि भारत ऐसा करने का इरादा रखता है। पहले यह एक पक्का सौदा जैसा लग रहा था, अब यह सम्भावित योजना जैसा लग रहा है। अब भारत पर शर्तों का दबाव कम हो गया है। अब यह खरीद विमान, तकनीकी समान, ऊर्जा, कीमती धातुएं और कोयले जैसे क्षेत्रों से जुड़ी बताई गई है।

भारत पर ट्रम्प की मेहरबानी की बड़ी वजह है कि वो भारत के साथ डील को फाइनल करना चाहते हैं। रूसी तेल की खरीद पर जो गाड़ी अटकी हुई है, वो उस पर भारत को मनाना चाहते हैं। अमेरिका एग्रीकल्चर सेक्टर, 500 अरब डॉलर के बाजार, डिजिटल सर्विस टैक्स आदि पर भारत की शर्तों को मान रहा है। भारत के पक्ष में इन फैसलों को मानकर अमेरिका तेल के लिए भारत पर दवाब बना सकता है। अमेरिका की चाहत है कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पूरी तरह से बंद हो जाए, जिसके लिए वो सालभर से कोशिशें कर रहा है। कभी टैरिफ लगाकर, कभी धमकी देकर तो कभी रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर ट्रेड डील में भी उसने रूसी तेल की खरीद बंद रखने की शर्त रखी है। हालांकि भारत ने साफ किया है कि उसे जहां से सस्ता तेल मिलेगा, वो वहां से खरीदेगा। सरकार ने गत दिनों एक संसदीय समिति को साफ किया है कि भारत उन देशों से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा, जहां से उसे सस्ता और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला तेल मिलता रहेगा। सरकार ने साफ किया है कि भारतीय तेल कंपनियां भू-राजनीतिक स्थिति और गैर-प्रतिबंधित स्रोतों को देखते हुए तेल की खरीदारी जारी रखेगी। इसका अर्थ यही है कि व्यापार वार्ता में रूस से तेल की खरीदारी को लेकर भी मामला अभी फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प की सियासत हमेशा डीलबाजी पर टिकी रही है। पहले कड़े बयान, फिर नरम रुख और फिर नया दबाव। कहा यह भी जा रहा है कि फैक्ट शीट में संशोधन अमेरिका की आंतरिक राजनीति का परिणाम है। अमेरिका के किसान उद्योग और टैक उद्यमी भी भारत से जल्द डील का दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका ने अभी कुछ धार कम की है लेकिन तलवार पूरी तरह से हटाई नहीं।

सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या अमेरिका भविष्य में कृषि क्षेत्र के लिए कोई और रास्ता ढूंढेगा और दबाव डालकर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। वैश्विक उद्योग और व्यापार अनिश्चितता से भरा हुआ है। अमेरिका अपने घरेलू उपकरणों के लिए बाजार चाहता है और भारत अपनी स्वतंत्र नीति को बनाए रखना चाहता है। अमेरिका की चाल यह दिखाई देती है कि कृषि पर भारत की बातों को मानकर रूस से तेल की खरीदारी को पूरी तरह से रोकने की अपनी शर्त मनवा ले। वह चाहता है कि भारत अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीदारी करे। भारत और यूरोपीय संघ की ट्रेड डील से अमेरिका भी दबाव में है। भारत अपने परखे हुए मित्र रूस को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहेगा।

भारत जैसे बड़े बाजार को छोड़ना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा। अमेरिका भारत के साथ ऐसी मनमानी नहीं कर सकता जैसा कि उसने अन्य देशों के साथ किया है। फिलहाल भारत के लिए साकारात्मक संकेत तो है लेकिन भारत को अमेरिका की फैक्ट शीट और व्यापार वार्ता से जुड़े बयानों के हर शब्द, हर पंक्ति और हर संशोधन पर पैनी नजर रखनी होगी। ट्रेड डील केवल व्यापार नहीं बल्कि सम्प्रभुत्ता का सवाल है। व्यापार वार्ता पर मार्च में अंतिम हस्ताक्षर होने हैं। तब तक भारत को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा।

प्रेम की वास्तविक परिभाषा

गीता पाढा

"प्यार का यह सप्ताह प्यार से मनाओ,
खुलकर दिल की बात बताओ,
झूठे अहम को न रिश्ते के बीच में लाओ,
और सामने वाले की ना को भी उतनी ही सहजता से अपनाओ,
किसी को हासिल करने की न जिद बनाओ,
प्रेम की वास्तविक परिभाषा पर तुम उतर कर दिखाओ...।"

भाजपा : एक नया जोश

कलम-दवात
कुमकुम चड्ढा

राष्ट्रीय जनभावना उल्लास और आक्रोश के बीच झूल रही है, साथ ही शोक भी व्याप्त है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज़ हैं। वह चुनाव आयोग से टकराव की स्थिति में हैं और उसे "भाजपा के एजेंट" करार देते हुए कहती हैं, "वे ऐसे बात करते हैं मानो वे ज़मींदार हों और हम उनके नौकर।"

बैठक के बाद बनर्जी, जो अपने दल के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही थीं, ने चुनाव आयोग को "झूठा और अहंकारी" बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर मुद्दे पर जब वह उनके कार्यालय गईं तो उन्होंने उनका "अपमान, अनादर और तिरस्कार" किया। बनर्जी ने कहा, "मैंने ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। वह बहुत अहंकारी हैं। उन्होंने हमारे साथ बेहद खराब व्यवहार किया।"

दूसरी ओर आयोग ने आरोप लगाया कि टीएमसी विधायकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ "अपमानजनक और धमकी भरी भाषा" का प्रयोग किया। सूत्रों के अनुसार, "उन्होंने दुर्व्यवहार किया, मेज़ थपथपाई और चली गईं।" बनर्जी के त्वरित क्रोध और उग्र स्वभाव को देखते हुए यह आरोप संगत प्रतीत होता है।

पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र राज्य में एक अलग तरह की राजनीति सामने आ रही है, शोक की राजनीति। विडंबना यह है कि वही राजनीति उस त्रासदी और शोक को भी पृष्ठभूमि में धकेल रही है। 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु हो गई। यह घटना अचानक और स्तब्ध कर देने वाली थी। उनकी पत्नी सुनेत्रा की शुरुआती तस्वीरें, जिनमें अजित की चचेरी बहन सुप्रिया सुले उनका हाथ थामे दिखाई दे रही थीं, टेलीविजन स्क्रीन पर प्रसारित हुईं। अजित के निधन के बाद वह सुनेत्रा के साथ मज़बूती से खड़ी दिखीं और उस भावनात्मक सहारे का संबल बनीं जिसकी किसी भी विधवा को ऐसी त्रासदी के समय आवश्यकता होती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि शोक ने उस परिवार को एकजुट कर दिया जो अजित के जीवनकाल में अलग-थलग था। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि सुले ने हमेशा राजनीति से ऊपर परिवार को रखा। यहां तक कि उस संकट के समय भी, जब अजित ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ राजनीतिक कदम उठाया था, वह संयमित और गरिमामय ही दिखाई दीं। उनका स्पष्ट रुख रहा, वह मेरे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी भी अपने चचेरे भाई को नीचा दिखाने वाली कोई टिप्पणी नहीं की।

निस्संदेह यह आंशिक रूप से दिखावे की राजनीति थी किंतु सुप्रिया ने कभी मर्यादा नहीं लांघी, यहां तक कि तब भी नहीं जब अजित ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी सुनेत्रा को उनके खिलाफ मैदान में उतारा था। पर अब वह अतीत की बात है। वर्तमान पर आएं तो पति के अंतिम संस्कार के कुछ ही घंटों के भीतर सुनेत्रा ने उनका राजनीतिक दायित्व संभाल लिया। उन्हें राज्य की उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, वही पद, जिस पर उनके दिवंगत पति अचानक निधन तक आसीन थे। इस अप्रत्याशित चयन से इतर कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान खींचती हैं, समय, शपथ ग्रहण की जल्दबाज़ी और निर्णय के चारों ओर बनी गोपनीयता।

वास्तव में शरद पवार स्वयं सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि सुनेत्रा को पदासीन करने के निर्णय पर उनसे न तो परामर्श किया गया और न ही उन्हें इसकी सूचना दी गई। यह स्थिति भाजपा के लिए अनुकूल कही जा सकती है, क्योंकि अजित के जीवनकाल में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की बातचीत आगे बढ़ रही थी। इस दृष्टि से उनका असामयिक निधन शरद पवार के लिए व्यक्तिगत के साथ-साथ राजनीतिक आघात भी है और प्राथमिकता क्रम में राजनीतिक अधिक। अपने जीवनकाल में अजित पवार ने एनसीपी को क्षति पहुंचाई और अपने चाचा व मार्गदर्शक शरद पवार की सर्वोच्चता को चुनौती दी। उनका आक्रोश इस बात को लेकर था कि वरिष्ठ पवार अपनी पुत्री को आगे बढ़ा रहे थे और उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे।

उनकी मृत्यु के बाद परिवार भले एकजुट दिखाई दिया किंतु सुनेत्रा के शपथ ग्रहण के साथ ही दरारें उभर आईं, क्योंकि शरद पवार गुट से न तो परामर्श किया गया और न ही उसे विश्वास में लिया गया। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं कि शरद पवार, उनकी पुत्री सुप्रिया अथवा उनके गुट का कोई भी सदस्य

शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हुआ। यह कि सुनेत्रा एक अप्रत्याशित चयन थीं, इसमें कोई संदेह नहीं किंतु आलोचक इस निर्णय की विवेकशीलता पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। पहला कारण यह है कि वह राजनीति में अभी अप्रशिक्षित मानी जाती हैं, उनकी राजनीतिक शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से हुई थी, जिसमें उन्हें सुप्रिया सुले से पराजय का सामना करना पड़ा। बाद में सुनेत्रा राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद पहुंचीं किंतु अब विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण वह सीट रिक्त होने वाली है। सुनेत्रा की नियुक्ति ने राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया है, क्योंकि बदले हुए हालात में विलय की बातचीत अब दूर की कौड़ी प्रतीत होती है और इससे स्पष्ट रूप से भाजपा को लाभ मिलता दिख रहा है। राज्य स्तरीय राजनीति से इतर राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग-अलग पटकथाएं लिखी और बदली गईं जिनमें केंद्रीय बजट की प्रस्तुति, भारत-यूरोपीय संघ समझौता और भारत-अमेरिका व्यापार समझौता प्रमुख रहे।

जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने लगातार नौवीं बार बजट पेश कर एक प्रकार का इतिहास रचा। यह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के दस बजट के रिकॉर्ड से मात्र एक कम है, हालांकि उनके बजट अलग-अलग अवधियों में थे, छह बजट 1959 से 1964 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए और चार 1967 से 1969 के बीच। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम भी नौ बार बजट पेश कर चुके हैं किंतु लगातार नहीं।

जब वह बजट पढ़ रही थीं, तब सत्ता पक्ष की बेंचों से मेज़ थपथपाकर उत्साह प्रकट किया गया, संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से बजट को भारत की "रिफॉर्म एक्सप्रेस" और "असीम अवसरों का राजमार्ग" बताया।

विपक्ष का मत इससे भिन्न रहा उनके अनुसार यह "ढाक के तीन पात" जैसा था। तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय के शब्दों में, बजट "रंगहीन और गंधहीन" था।

हालांकि, बजट इस पूरी कहानी का केवल एक हिस्सा है। भाजपा के पास प्रस्तुत करने के लिए और भी उपलब्धियां हैं, दो ऐसे समझौते, जिन्हें सभी समझौतों का "माता और पिता" कहा जा रहा है, क्रमशः यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते।

जब दोनों पक्षों ने भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए तो इसे "सभी समझौतों की जननी" बताया गया। यह केवल समझौते के आकार का प्रश्न नहीं था, बल्कि अमेरिका से व्यापारिक निर्भरता कम करने के अवसर का संकेत भी था अर्थात वैश्विक व्यापारिक समीकरणों में संभावित बदलाव। यह यूरोपीय संघ की लचीलेपन और 'लेन-देन की भावना' को भी दर्शाता है जो भारत के संदर्भ में अमेरिका के कथित 'लो या छोड़ो' रुख से भिन्न माना जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी देर नहीं की और भारत–ईयू समझौते के कुछ ही दिनों के भीतर दोनों देशों ने एक व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय निर्यात पर शुल्क 50 प्रतिशत की दंडात्मक दर से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया जो प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में सबसे कम दरों में गिना जा रहा है।

अपेक्षानुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दबाज़ी दिखाते हुए भारत से पहले ही सोशल मीडिया पर इस समझौते की घोषणा कर दी। इस बार इस समझौते को राज्यसभा के नामित सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला के शब्दों में "सभी समझौतों के पिता" की संज्ञा दी गई। जहां केंद्रीय बजट के बाद शेयर बाज़ार में गिरावट आई थी, वहीं भारत–अमेरिका समझौते के बाद न केवल उसमें सुधार हुआ, बल्कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह "आठ महीनों में सबसे अच्छा दिन" साबित हुआ।

महत्वपूर्ण यह है कि दोनों समझौते केवल बारीक शर्तों या इस प्रश्न तक सीमित नहीं हैं कि किसे अधिक लाभ मिला और किसे कम; बल्कि उनका असली महत्व धारणा और समय-निर्धारण में निहित है। भारत–ईयू समझौते के तुरंत बाद अमेरिकी संधि का होना भाजपा के लिए यह संकेत देने का अवसर बना कि ट्रंप को झुकना पड़ा।

तथ्यों से परे, प्रधानमंत्री मोदी के मज़बूत स्थिति से काम करने की छवि और अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ साझेदारी में उनकी "दूरदर्शिता" ऐसा विषय है जिसे भाजपा और सरकार राजनीतिक लाभ के लिए प्रमुखता से उभारने की कोशिश करेंगी।

व्यापार समझौतों, शुल्क, कर और वित्तीय चर्चाओं के शोर तथा महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाओं के बीच फिलहाल स्थिति भाजपा के लिए लाभकारी प्रतीत होती है। अतः यह कहना कि भाजपा उत्साह के शिखर पर है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दो बड़े व्यापार समझौतों की सफलता और महाराष्ट्र में घटनाक्रम का अनुकूल दिशा में बढ़ना, उसके लिए किसी अप्रत्याशित वरदान से कम नहीं।

इन सब कारकों को मिलाकर देखें तो निकट भविष्य में भाजपा के लिए राजनीतिक सफर अपेक्षाकृत सुगम दिखाई देता है।

'कूटनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए भारत को तकनीक में बड़ी छलांग लगानी होगी'

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): एक लेख के अनुसार, भारत को कूटनीतिक स्तर पर अपनी ताकत (दूसरे देशों पर प्रभाव) बढ़ाने के लिए नई और उन्नत तकनीकों में बड़ी प्रगति करनी होगी।

खास तौर पर दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ) प्रोसेसिंग, उन्नत दवाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सस्ती सैटेलाइट लॉन्च सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी मॉडल से सीख लेते हुए भारत को अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए। इससे भारत ऐसी रणनीतिक निर्भरता पैदा कर सकेगा, जिसका इस्तेमाल वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपने हितों के लिए कर सकता है। 'इंडिया नैरेटिव' में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि रक्षा और आईटी जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में अमेरिका की पकड़ और उसकी मजबूत वित्तीय व्यवस्था ने उसे वैश्विक कूटनीति में प्रभावशाली बनाया है। इसी ताकत के दम पर अमेरिका अन्य देशों के साथ अपने हितों के अनुसार संबंधों को संचालित कर पाता है। श्रिजीत फडके द्वारा लिखे गए इस लेख में कहा गया है कि अमेरिका की सफलता का कारण यह है कि उसने ऐसे क्षेत्रों में पकड़ बनाई, जहां दुनिया उसके बिना काम नहीं कर सकती। भारत को भी बिना अपने मूल्यों से समझौता किए लगातार नवाचार करना होगा, साझा लक्ष्यों की दिशा में समन्वित प्रयास करने होंगे और ऐसी क्षमताएं विकसित करनी होंगी, जिन पर दुनिया निर्भर हो जाए। लेख में सुझाव दिया गया है कि भारत को कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, सस्ती दवाएं और उन्नत बायोलॉजिक्स, उभरते देशों के लिए ओपन-सोर्स एआई, सस्ती सैटेलाइट और लॉन्च सेवाएं और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे यूपीआई को दुनिया में फैलाना)। अगर दुनिया भारत की इन सेवाओं पर निर्भर होगी, तो भारत अपनी कूटनीतिक ताकत बढ़ा सकेगा। लेख में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में केवल सद्भावना से प्रभाव नहीं बनाया जा सकता। अमेरिका ने समय-समय पर टैरिफ, आर्थिक प्रतिबंध, तकनीकी मानक, वित्तीय प्रणाली और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे कई साधनों का इस्तेमाल कर अपने हित साधे हैं। असली ताकत उसी के पास होती है, जिसके पास ऐसी विशेष क्षमता हो जिसका विकल्प आसानी से उपलब्ध न हो। साथ ही लेख में यह भी कहा गया है कि भारत को अमेरिका की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके मूल सिद्धांत को अपने तरीके से अपनाना चाहिए। भारत को चुनिंदा क्षेत्रों, तकनीकों और सेवाओं को इतना महत्वपूर्ण बनाना होगा कि वे दुनिया के लिए अनिवार्य (जरूरी) हो जाएं। लेख में सुझाव दिया गया है कि भारत को आईटी, सॉफ्टवेयर, एआई, फिनटेक और बायोटेक जैसे उच्च मूल्य वाले सेवा क्षेत्रों में तेजी से विस्तार करना चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उत्पादन में भी मजबूती बनाए रखनी चाहिए। एआई, क्वांटम सुरक्षा तकनीक और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, लेख में शिक्षा और शोध प्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया है। पाठ्यक्रम में रटने की बजाय गहन और मौलिक शोध को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नए और साहसिक विचारों को प्रोत्साहन दिया जाए, जो वैश्विक स्तर पर एकाधिकार जैसी स्थिति बना सकें। 'सच्चे नवाचार' के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कड़े मानक तय किए जाने चाहिए, ताकि ऐसे परिणाम सामने आएं जो देश को रणनीतिक बढ़त दिला सकें।

खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा

आकाश चोपड़ा

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान में नौ मिलियन से अधिक भारतीयों के निवास के साथ यह क्षेत्र रोजगार की तलाश में भारतीय प्रवासियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ है। भारत विश्व स्तर पर प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, जिसका अधिकांश भाग जीसीसी से आता है। प्रारंभ में भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से निर्माण, घरेलू सेवाओं और रखरखाव सहित नीले-कॉलर क्षेत्रों में कार्यरत थे। हालांकि, हाल के वर्षों में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, वित्त, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सफेद-कॉलर नौकरियों में भारतीयों की बढ़ती संख्या देखी जा रही है

आर्थिक लाभों के बावजूद, जीसीसी देशों में प्रवासन का अनुभव चुनौतियों से भरा है। सभी छह देशों में राजशाही शासन प्रणाली है, जिसमें श्रम अधिकार सीमित हैं, जिसके कारण मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें आती रहती हैं, खासकर कम आय वाले प्रवासी श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण चिंता विवादास्पद कफाला (प्रायोजन) प्रणाली है, जिसके तहत एक स्थानीय नियोक्ता (कफील) प्रवासी के कानूनी और रोजगार संबंधी स्थिति पर व्यापक नियंत्रण रखता है जिससे अक्सर शोषण और दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि श्रमिक अपने प्रायोजक की अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते या देश नहीं छोड़ सकते। जीसीसी देशों ने अपने श्रम कानूनों में सुधार करना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ ने श्रमिक सुरक्षा बढ़ाने और महामारी के बाद के श्रम बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने के लिए कफाला प्रणाली के कुछ पहलुओं को संशोधित या समाप्त कर दिया।

भारत से विदेशों में नौकरी करने गए कई युवाओं की दर्दभरी दास्तानें सामने आती रही हैं। अनेक कहानियां सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं। दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियर अमन भोला अप्रैल 2023 में कुवैत बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर गए थे। शुरुआत में नौकरी का अवसर अच्छा दिखाया गया था लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। अमन को इंटरव्यू में सामान्य कार्य घंटे, सही ओवरटाइम भुगतान और सम्मानजनक कामकाजी माहौल का भरोसा दिया गया था। कंपनी में मजदूरों से रोज़ लगभग 16 घंटे तक काम कराया जाता था। कानून के अनुसार अधिकतम कार्य सीमा और 125 प्रतिशत ओवरटाइम भुगतान का प्रावधान है लेकिन अमन के अनुसार मजदूरों को केवल लगभग 65 प्रतिशत भुगतान मिलता था। इसी को लेकर मजदूरों की शिकायतें लगातार सामने आने लगीं। अमन ने बताया कि अधिकतर शिकायतें कंपनी की एचआर टीम के खिलाफ थीं। काम के घंटे, वेतन और सुविधाओं को लेकर बार-बार सवाल उठाने पर उन्हें दबाने की कोशिश की गई। जब

अमन ने मजदूरों की समस्याएं प्रबंधन तक पहुंचाईं तो उन्हें इंजीनियर से फोरमैन बना दिया गया। बाद में मैनेजर और कंपनी मालिक से अनुरोध के बाद उन्हें फिर से इंजीनियर पद पर बहाल किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आवाज़ उठाने वालों पर दबाव बनाने के लिए पद और पोस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अमन ने कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर में श्रम कानून उल्लंघन का मामला दर्ज कराया तो उनके साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हुआ और मारपीट की गई। वह एक वर्ष तक बिना नौकरी के न्याय के लिए लड़ते रहे। बाद में उन पर पुलिस में झूठा मामला दर्ज कराकर भारत निर्वासित कर दिया गया।

ऐसी ही कहानी विश्वकर्मा की भी है। उसने अच्छी नौकरी के नाम पर एजेंट को भारी रकम दी और अपनी दुकान तक बेच दी लेकिन विदेश पहुंचने के बाद उनसे जबरन निर्माण कार्य कराया गया। उत्तराखंड के विशाल, रंजीत, लल्लन और जुगेश को पानी की बोतलों की पैकिंग का काम बताया गया था लेकिन दुबई पहुंचकर उनसे भीषण गर्मी में भारी मजदूरी कराई गई। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर मदद मांगी।

उत्तर प्रदेश के मोहम्मद ड्राइवर की नौकरी के नाम पर सऊदी अरब भेजे गए, मोहम्मद से वहां बकरियों और ऊंटों की देखभाल कराई गई। मजबूर होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील की। सऊदी अरब, जो भारत से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है, विदेशी श्रमिकों के प्रति अपने व्यवहार के लिए बार-बार आलोचनाओं का सामना करता रहा है। मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों और वकालत समूहों की रिपोर्टों ने श्रम अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन को उजागर किया है, जिसके कारण हजारों भारतीय श्रमिक असुरक्षित और क्रूर परिस्थितियों में फंसे रह जाते हैं। सबसे जघन्य उल्लंघनों में वेतन रोकना शामिल है, जहां नियोक्ता अक्सर भुगतान में देरी करते हैं या भुगतान से इन्कार कर देते हैं जिससे कामगार घोर गरीबी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नियोक्ता कामगारों के पासपोर्ट भी जब्त कर लेते हैं जिससे वे देश छोड़कर न जा सकें या मदद न मांग सकें। कई मजदूर पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना जानलेवा वातावरण में काम करते हैं जिससे गंभीर चोटें लगती हैं, यहां तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ कामगार, विशेषकर घरेलू कामगार, मारपीट, यौन हिंसा और उत्पीड़न का शिकार होने की शिकायत करते हैं।

इसी प्रकार, घरेलू कामगारों, जिनमें से कई भारत की महिलाएं हैं, ने अत्यधिक हिंसा और यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट की है। इनमें से काफी संख्या में महिलाओं को उनके मालिकों द्वारा शारीरिक हमले का सामना करना पड़ता है और कानूनी सुरक्षा या नौकरी छोड़ने की क्षमता के अभाव में वे असहाय और सदमे में रह जाती हैं।

खाड़ी देशों में अपने नागरिकों की पीड़ा के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए भारतीय सरकार की आलोचना की गई है। सऊदी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए राजनयिक प्रयास किए गए हैं लेकिन प्रवर्तन और जवाबदेही की कमी के कारण ये पहलें अक्सर विफल हो जाती हैं। इसके अलावा, भारत में भर्ती एजेंसियां और बिचौलिए श्रमिकों की तस्करी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अक्सर अत्यधिक शुल्क वसूलते हैं और नौकरी चाहने वालों को सऊदी अरब में काम करने की वास्तविकताओं के बारे में गुमराह करते हैं। सऊदी अरब में भारतीय कामगारों की दुर्दशा आधुनिक गुलामी की भयावह मिसाल है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों और मानवाधिकार समझौतों के बावजूद आज भी कायम है। जब तक व्यवस्थागत सुधार लागू नहीं होते, हजारों भारतीय कामगार शोषण के दुष्चक्र में फंसे रहेंगे और बेहतर जीवन के उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। अब कार्रवाई का समय आ गया है—सरकारों, कार्यकर्ताओं और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को एकजुट होकर इस दमनकारी व्यवस्था को समाप्त करना होगा और सभी प्रवासी कामगारों के लिए सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना होगा।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

फरवरी में बदला मौसम का मिजाज रातें गर्म, हवा बहुत खराब श्रेणी में

15 से 17 फरवरी के बीच 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राजधानी दिल्ली में इस बार फरवरी का मौसम सामान्य से अलग रुख दिखा रहा है। महीने के मध्य में ही रात के तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 1.2 डिग्री से तीन डिग्री अधिक है। पिछले दो वर्षों में फरवरी के पहले 11 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री को पार नहीं कर पाया था, ऐसे में इस बार की बढ़ोतरी असामान्य मानी जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 15 से 17 फरवरी के बीच न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आमतौर पर फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही ऐसा तापमान दर्ज होता है। 2017 एक अपवाद रहा था, जब महीने के शुरुआत में पारा 15.5 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग ने बताया कि हवाएं दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलीं और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं की कमी के कारण रातें अपेक्षाकृत गर्म हो रही हैं। हवाएं दक्षिण-पश्चिम दिशा से चली और उनकी गति 8 किमी प्रति घंटा तक सीमित रही, जिससे ठंडक में कमी आई।

घने कोहरे की अब संभावना नहीं... आने वाले दिनों (13-19 फरवरी) में देश के किसी भी हिस्से में कोल्ड वेव और घने कोहरे की संभावना नहीं है। दिल्ली में अगले सात दिनों में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम तापमान नॉर्मल से ज्यादा रहने की संभावना है। 13 से 16 फरवरी के बीच एक के बाद एक दो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है, जिससे आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं या आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।

वायु गुणवत्ता में भी गिरावट दर्ज की गई

इस बीच वायु गुणवत्ता में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी का एक्यूआई 305 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। मंगलवार को यह 271 था। आईआईटीएम के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रह सकती है। आईएमडी ने स्पष्ट किया है कि 13 से 19 फरवरी के बीच देश में कहीं भी कोल्ड वेव या घने कोहरे की संभावना नहीं है। अगले सात दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। 13 से 16 फरवरी के बीच दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं, जिससे आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और रात के तापमान में और वृद्धि हो सकती है।

शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट नहीं चलने से गेस्ट टीचर्स की बढ़ी टेंशन

पोर्टल बंद होने से सैलरी मिलने में हो रही परेशानी नहीं लग रही अटेंडेंस

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट दिसंबर 2025 से बंद है। 12 फरवरी 2026 तक वेबसाइट ठीक नहीं हुई। इसका सीधा असर दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम करने वाले हजारों गेस्ट टीचर्स पर पड़ा है। उनकी अटेंडेंस और काम के दिनों का हिसाब वेबसाइट से ही लगाया जाता है, जो सैलरी देने का आधार है। पोर्टल बंद होने की वजह से उनकी जनवरी की सैलरी जारी नहीं हुई है। गेस्ट टीचरों का कहना है कि वे पढ़ाने के लिए समय पर स्कूल आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम में अटेंडेंस अपडेट न हो पाने की वजह से उनकी मेहनत रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। इससे न सिर्फ उनकी सैलरी में देरी हुई है, बल्कि भविष्य में पेमेंट को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। कई टीचरों ने बताया कि वे पूरी तरह से अपनी महीने की सैलरी पर निर्भर हैं और पेमेंट में देरी से उन्हें घर के खर्च, किराया और दूसरी जरूरी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। वेबसाइट बंद होने से स्कूलों का प्रशासनिक कामकाज पर भी बुरा असर पड़ा है। ट्रांसफर अपडेट, लॉगिन-बेस्ड रिपोर्टिंग, स्टाफ प्रोफाइल अपडेट, स्टूडेंट डेटा अपलोड और डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड समय पर रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। कई मामलों में स्कूलों को जरूरी रिपोर्ट तैयार करने में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे डिपार्टमेंट का काम धीमा हो रहा है। टीचर और स्टाफ को एक्स्ट्रा पेपरवर्क का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस से काम रुक रहा है।

टीचर संगठनों ने इस स्थिति को गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही बताया है। उनका कहना है कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है, तो डिपार्टमेंट को दूसरा इंतजाम करना चाहिए था। गेस्ट टीचरों ने मांग की है कि जब तक वेबसाइट पूरी तरह से चालू नहीं हो जाती, तब तक उनकी सैलरी मैनुअल अटेंडेंस और स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर जारी की जाए। साथ ही, भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए पोर्टल के टेक्निकल सिस्टम को मजबूत किया जाए। वहीं जब शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी से वेबसाइट के ठीक होने की स्थिति के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

दिल्ली की हलचल

महर्षि दयानंद की 201वीं जयंती पर हुई संगोष्ठी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): महर्षि दयानंद सरस्वती की 201वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुरली मनोहर पाठक ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इस मौके पर प्रो. पाठक ने कहा कि महर्षि दयानंद का जन्म प्राणी मात्र के कल्याण और वेद ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए हुआ था। मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रो. रामप्रकाश दीन दयाल उपाध्याय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि महर्षि दयानंद युग दृष्टा थे, उन्होंने समाज के अंदर अनेक बुराइयों का निराकरण किया। संचालन डॉ. रमेश कुमार ने किया। इस मौके पर प्रो. भारत भूषण, आचार्य योगेश, प्रो. मारकण्डेय नाथ तिवारी, डॉ. जय सिंह भढ़िया, डॉ. विजय गुसाई, डॉ. लेखराज सिंह, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. मोहन लाल शर्मा, डॉ. बलबीर सिंह, प्रियंका पाण्डेय, डॉ. योगेश शर्मा मौजूद रहे।

मांगों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के आर्ट्स फैकल्टी परिसर में गुरुवार को वामपंथी समर्थक छात्रों ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 और रोहित एक्ट के क्रियान्वयन की मांग को लेकर आयोजित पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल: समता उत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा किया गया। आयोजकों के अनुसार यह उत्सव विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आधिकारिक लिटरेचर फेस्टिवल के विकल्प के रूप में आयोजित किया गया, जिसे उन्होंने प्रतिगामी प्रचार और सांप्रदायिक विमर्श का मंच बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम को बाधित करने के प्रयास किए गए। इसके बावजूद छात्रों और शिक्षकों की एकजुटता से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र 'समाज और विश्वविद्यालय में जाति' विषय पर आयोजित हुआ, जिसमें इतिहासकार प्रो. एस इरफान हबीब ने देश के इतिहास को पुनर्लेखन के प्रयासों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्ता और उससे जुड़े संगठनों द्वारा भारत की साझा विरासत को विकृत कर एक एकांगी और बहिष्करणवादी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है।

मैत्रेयी कॉलेज में आंतरिक समिति का व्याख्यान

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मैत्रेयी कॉलेज में महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. हरित्मा चोपड़ा के मार्गदर्शन में आंतरिक समिति के तत्वावधान में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित विविध प्रावधानों तथा आंतरिक समिति से संबंधित नियमों एवं व्यवस्थाओं के प्रति संस्थानिक जागरूकता और विधिक समझ को सुदृढ़ करना था। शुभारंभ मंगलाचरण से हुआ। तत्पश्चात् महाविद्यालय की आंतरिक समिति की प्रभारी प्रो. मंजू मेहता ने मुख्य वक्ता को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विधि संकाय की प्राध्यापिका एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति की विधिक सलाहकार डॉ. शिवानी वर्मा उपस्थित रहीं।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार का खुलासा कर 'आप' के दावे को सच साबित किया: सौरभ

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आम आदमी पार्टी ने पानी बिल का निपटारा करने की एवज में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। 'आप' दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई ने पानी बिल योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा कर आम आदमी पार्टी के दावे को सच साबित कर दिया है। हमने बार-बार कहा है कि सरकार यह स्कीम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लाई है और समय सीमा खत्म होने के बाद भी फेल स्कीम को आगे बढ़ा रही है। अभी भी 12 लाख उपभोक्ताओं ने बिल का भुगतान नहीं किया है। अब सरकार जेडआरओ ऑफिस से इन उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने का धमकी दिलाकर बिल जमा करने का दबाव बना रही है।

सौरभ भारद्वाज

गुरुवार को 'आप' मुख्यालय पर विधायक कुलदीप कुमार के साथ प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, तो उसने पहले महीने से ही दावा करना शुरू कर दिया कि दिल्ली जल बोर्ड के बकाया बिलों को लेकर एक बहुत क्रांतिकारी योजना लाने वाली है। कई महीनों तक योजना को लेकर भाजपा ने केवल बहानेबाजी की। बड़ी मुश्किल से अक्टूबर 2025 में एक पुरानी योजना को दोबारा लाया। जो पहले भी बेकार हो चुकी योजना थी जो पहले भी कई बार विफल साबित हो चुकी है। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस योजना का खूब प्रचार किया और मास्टर स्ट्रोक बताया। भाजपा ने कहा कि जल बोर्ड के उपभोक्ताओं के जितने भी बिल बकाया हैं, उनका विलंब शुल्क (एलपीएससी) माफ कर दिया जाएगा, सब वे अपनी मूल राशि का भुगतान कर दें। आम आदमी पार्टी ने तब भी कहा था कि यह एक विफल योजना है। इससे लाखों उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के विवाद का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें विवाद है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब उन्होंने इतना पानी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो बिल क्यों दें? कोरोना काल में पानी इस्तेमाल नहीं किया या घर खाली था और बिल आ गया, तो वह उसका भुगतान क्यों करे?

मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): साल 2016 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल बाद यह कहते हुए बरी कर दिया कि सिर्फ मृत्यू पूर्व कथन के आधार पर किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है।

कोर्ट ने सबूतों की कमी और बयानों में अंतर के कारण आरोपी पति को बरी किया

कोर्ट ने सबूतों की कमी और बयानों में अंतर के कारण आरोपी पति को बरी कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन आरोपी के खिलाफ अपने केस को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया, इसलिए उसे हत्या के आरोप से बरी किया जाता है।

बता दें कि आरोपी पर अपने घर में पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप था। इस मामले में उत्तम नगर थाने में आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। अभियोजन का पूरा केस घटना के दिन कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से दर्ज मृत्युपूर्व बयान पर आधारित था जिसमें मृतका ने आरोप लगाया था कि घरेलू झगड़े के बाद पति ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस बयान को पत्नी की मौत से पहले का बयान माना गया।

जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज, अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (एसएसएस) के छात्रों ने पांच छात्रों के कथित अनुचित निलंबन (रस्टिकेशन) और उन पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में बुधवार से हड़ताल शुरू कर दी है। निलंबित छात्रों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के वर्तमान पदाधिकारी और एक पूर्व अध्यक्ष शामिल हैं।

बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 फरवरी को चार मौजूदा जेएनयूएसयू पदाधिकारियों और एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को दो सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट करने का आदेश जारी किया था। यह कार्रवाई 21 नवंबर 2025 को डॉ. बीआर आंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के बाद की गई प्रॉक्टोरियल जांच के आधार पर की गई।

प्रशासन ने संबंधित छात्रों को तत्काल प्रभाव से कैंपस में प्रवेश से रोक दिया है और प्रत्येक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व जेएनयूएसयू अध्यक्ष नितीश कुमार ने कहा कि छात्रों ने हड़ताल शुरू कर दी है और आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन संवाद के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को कैंपस में प्रवेश से रोकने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन बातचीत के लिए आगे नहीं आता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इसकी कोई तय समय-सीमा नहीं होगी। वामपंथी छात्र संगठनों ने भी रस्टिकेट किए गए पदाधिकारियों के समर्थन में आवाज बुलंद की है।

मसीहा बनी एसएचओ वंदना राव बढ़ाया दिल्ली पुलिस का मान

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दक्षिण दिल्ली जीके-टू क्षेत्र स्थित तिकोना पार्क में एक नवजात शिशु को बचाकर चित्तरंजन पार्क थाने की एसएचओ वंदना राव ने दिल्ली पुलिस का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उनकी तत्परता और संवेदनशीलता से न सिर्फ मासूम की जिंदगी बच गई, बल्कि उसे मरने के लिए पार्क में फेंकने वाली मां भी पकड़ी गई। सूत्रों के मुताबिक युवती घरेलू सहायिका थी, जो झारखंड से दिल्ली आई थी। बिना शादी के मां बनने पर उसने नवजात बच्चे को पार्क में फेंक दिया था। एक तरफ जहां सगी मां ने लोकलाज के डर से बच्चे को ठंड में मरने के लिए पार्क में फेंक दिया था, वहीं एसएचओ वंदना राव ने मां की ममता का परिचय देते हुए मासूम की जिंदगी बचाई है।

जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए एम ब्लॉक स्थित तिकोना पार्क में पहुंचे तो एक कपड़े से बच्चे का हाथ बाहर निकला हुआ देखा। उन्होंने तुरंत थाने में सूचना दी। बच्चे के पार्क में पड़े होने की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर वंदना राव तुरंत पार्क पहुंच गईं। कड़ाके की ठंड की वजह से नवजात शिशु अचेत अवस्था में पड़ा था और शरीर नीला पड़ चुका था। वंदना राव ने बच्चे को गोद में लेकर उसे अपने शरीर की गर्मी दी और उसे अगले चार मिनट में अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने तुरंत उसका उपचार शुरू किया।

शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर डीडीए से जवाब मांगा है। कमेटी ने अपनी याचिका में कहा है कि एक जमीन का मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, फिर भी डीडीए जमीन पर बोर्ड लगाने की कार्रवाई कर रहा है।

कमेटी ने हाईकोर्ट से अपील की कि डीडीए को जमीन पर बोर्ड लगाने से रोका जाए। याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस जसमीत सिंह ने डीडीए को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध करते हुए डीडीए के वकील ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस मामले में अगली तारीख 12 अगस्त है, साथ ही दूसरे जुड़े हुए मामले भी हैं।

वहीं शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के वकील ने कहा कि पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख तक स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि डीडीए के ईदगाह और आसपास की जमीन पर बोर्ड लगाने के बावजूद जमीन का विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। इससे पहले वहां रानी लक्ष्मी बाई की एक मूर्ति भी लगाई गई थी।

पुलिस का 'हुक्का बार' पर छापा मालिक समेत 14 आरोपी दबोचे

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नबी करीम थाना पुलिस ने एक हुक्का बार पर रेड कर मौके से मालिक समेत 14 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने 10 नाबालिगों को भी यहां से निकाला है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान हुक्का बार मालिक मोहम्मद रब्बानी और इसके सहयोगी शाहनवाज, मोहम्मद मेराज, सरफराज, अबू बकर, मोहम्मद रजी, मोहम्मद रेहान, मो. मिराज, अल्तमस, मो. रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद, मो. फैजी, तौसुफ और मो. सज्जाद के रूप में की है। आरोपियों को एसएचओ मुरतुजा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर शिव करण सिंह के नेतृत्व में एसआई विपुल, हेड कांस्टेबल जगसोरेन, महेश और कांस्टेबल महेंद्र, अनिल और विमल की टीम ने पकड़ा है। डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि आरोपियों को स्ट्रीट क्राइम पर रोक लगाने और गैर-कानूनी कामों को रोकने के लिए सभी बीट स्टाफ को सीनियर अधिकारियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करने और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया था। गत आठ फरवरी की रात को टीम को गुप्त सूचना मिली कि नबी करीम के लक्ष्मण पुरी की एक तंग गली में एक गैर-कानूनी हुक्का बार चल रहा है।

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE
SAMVAD R.O. No. 13/2026/40/42964/I/142/7 Dt. 12/02/2026

SR. No.	NAME OF BOARD/CORP./AUTH	NAME OF WORK NOTICE TENDER	OPENING DATE CLOSING DATE (TIME)	AMOUNT / EMD (APPROX.) IN RUPEES	WEBSITE OF THE BOARD CORP./AUTH	NODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/EMAIL
1	THE BALLABGARH COOP. MILK PRODUCERS UNION LIMITED	SUPPLY OF LAB CHEMICALS,GLASSWARE, HI-MEDIA, FILTER PAPER, MBRT TABLET	[illegible] [illegible]	20000/-	www.vitaindia.org.in	[illegible] [illegible]

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE
SAMVAD R.O. No. 13/2026/60/42965/I/142/7 Dt. 12/02/2026

SR. No.	NAME OF BOARD/CORP./AUTH	NAME OF WORK NOTICE TENDER	OPENING DATE CLOSING DATE (TIME)	AMOUNT / EMD (APPROX.) IN RUPEES	WEBSITE OF THE BOARD CORP./AUTH	NODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/EMAIL
1	MUNICIPAL CORPORATION, FARIDABAD	ROUGH COST ESTIMATE FOR PROVIDING AND LAYING SEWER LINE OF 300MM, 250MM AND WATER SUPPLY LINE 100MM, 150MM DI PIPE K-9, CONSTRUCTION OF RCC DRAIN WITH ARMC M-30 ROAD AT VARIOUS STREETS DESCRIBED IN VILLAGE DAULTABAD OF OLD WARD NO.31 (NEW WARD 31) OLD FARIDABAD.	09.02.2026 23.02.2026	3,38,73,242/-	https://etenders.hry.nic.in	9914544004 xenmcf3@gmail.com

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE
SAMVAD R.O. No. 13/2026/60/42962/I/142/7 Dt. 12/02/2026

SR. No.	NAME OF BOARD/CORP./AUTH	NAME OF WORK NOTICE TENDER	OPENING DATE CLOSING DATE (TIME)	AMOUNT / EMD (APPROX.) IN RUPEES	WEBSITE OF THE BOARD CORP./AUTH	NODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/EMAIL
1	MUNICIPAL CORPORATION, GURUGRAM	DOOR-TO-DOOR COLLECTION, SEGREGATION AND OF TRANSPORTATION UPTO PROCESSING SITE IN MUNICIPAL CORPORATION GURUGRAM (MCG), CLUSTER-I (ZONE-I AND II) + 1 OTHER WORK	02.02.2026 23.02.2026	6,30,49,464/-	https://etenders.hry.nic.in	9911209696 ee.sbm@mcg.gov.in

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

राजपाल यादव को नहीं राहत, अब 16 फरवरी को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने राजपाल यादव को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप जेल इसलिए गए क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया।

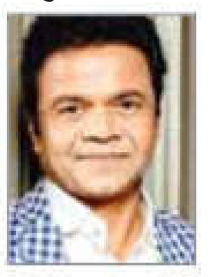

राजपाल यादव

हाईकोर्ट ने राजपाल यादव से पूछा कि वे सजा को रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं। उन्होंने खुद माना था कि उन्होंने पैसा उधार लिया था और उसे लौटाने का वादा किया था। ऐसे में अब सजा पर रोक लगाने की मांग किस आधार पर की जा रही है? इसके जवाब में एक्टर के वकील ने कहा कि उन्होंने (राजपाल) उसी दिन कोर्ट को बताया था कि वे इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। राजपाल यादव ने अपने कहे हुए वादे का पालन करने के लिए सरेंडर किया है। फिल्म में जो 5 करोड़ रुपए लगाए गए थे, उन्हें एक्टर चुकाना चाहते हैं और अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि चुका दी गई है। कोर्ट ने राजपाल यादव को फटकार लगाई और कहा कि समझ नहीं आता यह बहस क्यों हो रही है। आपने याचिका दाखिल की थी और कहा था कि पैसा लौटाएंगे, लेकिन फिर सालों तक भुगतान नहीं किया। पिछले आदेश का पालन न करने की वजह से आपको जेल में सरेंडर करना पड़ा। आपको 25-30 मौके दिए गए। अब आप यह केस दोबारा क्यों खोलना चाहते हैं? आपको यह बताना होगा कि पैसे देने में देरी क्यों हुई। मुझे आपसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना

भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से उप. मुख्य बिजली इन्जिनियर (निर्माण) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के अधीन निम्नलिखित कार्यों के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। **ई-निविदा सूचना: EL/C/JP/PSI/ABR-TRAH/T/08-R/25-26. कार्य का नाम:** नई लाइन कार्य के संबंध में, अजमेर मंडल, एनडब्ल्यूआर के एबीआर-टीआरएएच खंड में 1x25 केवी पीएसआई प्रणाली के रेलवे विद्युतीकरण कार्य का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 16,92,14,412.00 **बयाना राशि जो जमा करनी है:** ₹ 9,96,100.00 **कार्य पूर्ण होने की तिथि:** 12 Months **निविदा प्रपत्र जमा कराने व खुलने की तारीख व समय: 07.03.2026** Upto 15-00 Hrs. 07.03.2026 at 15.30 Hrs. उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये वैबसाइट का पता **www.ireps.gov.in** 225-AR/26

NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE
PRDH R.O. No. 11/2026/240/42976/I/142/7 Dt. 12/02/2026

SR NO.	NAME OF DEPARTMENT	NAME OF WORK NOTICE TENDER	OPENING DATE CLOSING DATE	AMOUNT / EMD (APPROX.) IN RUPEES	WEBSITE OF THE DEPARTMENT	NODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/EMAIL
1	PWD B&R,HISAR	CONSTRUCTION OF 50 BEDDED TO 100 BEDDED HOSPITAL AT NARNAUND IN HISAR DISTRICT. (PDG. HVAC SYSTEM ONLY). (BALANCE WORK)	11.02.2026 18.02.2026	77.11 LACS	https://etenders.hry.nic.in	01662225651 pwd-eeed-hissar@hry.nic.in
2	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT HARYANA, CHARKHI DADRI	REPAIR OF DAMAGED LINING (DUE TO FLOOD WATER) AT VARIOUS K.M. OF KHANPUR DISTY. + 10 WORKS	11.02.2026 19.02.2026	12.95 LACS	https://etenders.hry.nic.in	8059375563 xenmgcckd11@gmail.com
3	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT HARYANA, PANIPAT	ESTIMATE FOR 'PERIODICAL REPAIR AND MAINTENANCE WORK IN SR. TYPE QTR. NO. 3, CANAL COLONY, BINJHOL, PANIPAT. + 2 WORKS	CLOSING DATE 17.02.2026	6.32 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9466159501 xenpwsdiv@yahoo.in
4	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT HARYANA, ROHTAK	SUPPLY ERECTION AND COMMISSIONING OF NEW PUMPS FOR FLOOD PROTECTION WORK IN VILLAGE BARODA IN W.S MECH SUB DIVISION GOHANA	09.02.2026 16.02.2026	28.02 LACS	https://etenders.hry.nic.in	8901388296 rohtakxenmech@yahoo.com
5	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT HARYANA, ROHTAK	LAYING UNDERGROUND RCC NP-3 PIPE LINE 900MM ,1200MM DIA FOR DEWATERING OF LOW-LYING AREAS OF VILLAGE BHAINI SURJAN, BHAINI CHANDERPAL AND SEMAN OUT FALLING AT JUNCTION POINT OF 1800MM DIA PIPE. + 5 WORKS	CLOSING DATE 17.02.2026	1469.04 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9812111077 xenwsdnrtk@gmail.com
6	IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT HARYANA, ROHTAK	RE-CONSTRUCTION OF AQUEDUCT AND ESCAPE AT RD 83000 OF BHALAUT SUB BRANCH (X-ING DDB) OF BHALAUT SUB BRANCH.	CLOSING DATE 02.03.2026	1684.84 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9812111077 xenwsdnrtk@gmail.com
7	PUBLIC HEALTH ENGINEERING, SIRSA	RUPAWAS:- REPLACEMENT OF RCC PIPE INLET CHANNEL, PAINTING, DISTEMPERING AND SNOWCEM, LAYING OF DISTRIBUTION PIPE LINE, SLUICE VALVE HODIES, RESTORED AND NEW TAP CONNECTION AND ALL OTHER WORKS CONTINGENT THERETO AT RUPAWAS.	10.02.2026 05.03.2026	128.55 LACS	https://etenders.hry.nic.in	01666221925 ee2sirsa@phedharyana.gov.in
8	PANCHAYATI RAJ, FARIDABAD	CONSTRUCTION OF DRAINS AND TREATMENT PROCEDURE OF WASTE WATER (GWM) AT VILLAGE LADHIYAPUR BLOCK BALLABGARH DISTRICT FARIDABAD + 4 WORKS	10.02.2026 18.02.2026	181.43 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9467905067 prexeeng.fbd1@gmail.com
9	PANCHAYATI RAJ, KURUKSHETRA	JHANSA CONST. OF E LIBRARY IN VILLAGE -JHANSA BLOCK :- ISMAILABAD DISTT KKR	11.02.2026 17.02.2026	30.87 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9896224357 prexeeng.krk@hry.nic.in
10	PANCHAYATI RAJ, BHIWANI	CONST. OF HALL AND VERANDAH IN BALMIKI DHARMSHALA VILLAGE - SIKANDERPUR BLOCK -BAWANI KHERA HGVY + 6 WORKS	11.02.2026 17.02.2026	217.84 LACS	https://etenders.hry.nic.in	01664243927 prexeeng.bhw@hry.nic.in
11	PANCHAYATI RAJ, BHIWANI	CONSTRUCTION OF COMMUNITY CENTRE IN VILLAGE KOUNT, BHIWANI	11.02.2026 17.02.2026	52.77 LACS	https://etenders.hry.nic.in	01664243927 prexeeng.bhw@hry.nic.in
12	CIVIL SURGEON, JIND	PUBLISHING OF E TENDER NOTICE FOR PURCHASING DENTAL ORTHO AND OTHER ITEMS	11.02.2026 23.02.2026	EMD 30000	https://etenders.hry.nic.in	7015444191 cds.jind@gmail.com

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT www.etenders.hry.nic.in

प्रेरणा

पक्षी की आजादी उसके पंख हैं, मनुष्य की आजादी उसका मन है। - **महात्मा गांधी**

संपादकीय

औपचारिक नौकरियों से समृद्धि का क्या नाता है?

वेतन वाली नौकरियों में दुनिया के औसत के मुकाबले भारत काफी पीछे है और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। वर्ल्ड बैंक, दो सरकारी सर्वे और चेन्नई की एक स्वयंसेवी संस्था के आंकड़ों पर आधारित भास्कर रिसर्च के अनुसार अमेरिका में 94% लोग जॉब्स में हैं। प्रति-व्यक्ति आय में भारत से 30% कम अफ्रीका में भी 83% लोग नौकरियां कर रहे हैं। इसका कारण है यूरोप के नजदीक होने के कारण उत्तरी अफ्रीका का जबरदस्त औद्योगिक विकास, वहीं सब-सहारन अफ्रीका इतनी दयनीय स्थिति में है कि एक ही महाद्वीप के दोनों क्षेत्रों के बीच आय का अंतर चार गुना है। चीन में नौकरी का प्रतिशत भारत से तो दूना है लेकिन वैश्विक औसत के लगभग बराबर है, क्योंकि 80 के दशक के बाद उस देश ने उद्यमिता को उच्च कौशल वाला कुटीर उद्योग बनाया। इसके उलट बिहार में पंजाब के मुकाबले नौ गुना कम प्रति परिवार खेती का रकबा है, फिर भी राज्य में न तो उद्यमिता, न ही कौशल विकसित हुआ। यानी जनता थोड़ी-सी खेती में ही गरीबी से जूझती रही या अन्य राज्यों में मजदूरी करने जाती रही। रिसर्च के आंकड़े यह भी बताते हैं कि शिक्षा और नौकरी का समानुपाती रिश्ता है। कहना न होगा कि भारत का स्व-रोजगार भी चीन जैसी उद्यमिता न होकर शहरों और कस्बों में ठेला चलाना, खोमचा और रेहड़ी लगाना और भवन-निर्माण में ईंट-गारा ढोने तक ही सीमित है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

चरित्र अंतिम प्राथमिकता बना इसलिए लोग देह पर टिक गए

दुनिया में तीन ही समस्याएं हैं। पहली, पैसा होना या न होना। दूसरी, पुरुष के जीवन में स्त्री का होना या न होना। और तीसरी, स्त्री के जीवन में पुरुष का होना या न होना। बाकी समस्याएं इन्हीं तीनों का विस्तार हैं। हमारे यहां जब अष्टलक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो उनका एक रूप गजलक्ष्मी भी है। इसमें लक्ष्मी जी सफेद हाथी पर बैठी हैं और यह सफेद हाथी उड़ भी सकता है। इसका मतलब यही है कि पैसा कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वह समस्या और समाधान, दोनों बन जाता है। दूसरी और तीसरी समस्या में सारा खेल स्त्री-पुरुष का है। चूंकि इन दिनों चरित्र और नैतिकता अंतिम प्राथमिकता बनते जा रहे हैं। इसीलिए लोग देह पर टिक गए। पिछले दिनों सुना कि पांच साल की एक बच्ची से उसी के रिश्ते के भाई, जिसकी उम्र तेरह साल थी- ने दुष्कर्म किया और बच्ची बुरी तरह आहत है। यह घटना अन्य समाचारों की तरह गुजर गई। लेकिन यह चिंता छोड़ गई कि इन तीन समस्याओं में बाकी दो समस्याएं अब और बड़ी होती जाएंगी।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

टु द पीपुल • समाज की मुख्यधारा में पैठा है स्त्रीद्वेष

लम्बी चुप्पी के विरुद्ध स्त्रियों के विद्रोह को सदैव याद रखें

मी-टू

डेरेक ओ ब्रायन
राज्यसभा में टीएमसी के नेता
office@derek.in

यह मेरे द्वारा लिखे गए कठिनतम कॉलमों में से एक है। इसमें सार्वजनिक नीतियों पर बात नहीं की गई है। किसी योजना का विश्लेषण नहीं है। टैरिफ, चुनाव या संसद के किसी सत्र पर टिप्पणी भी नहीं है। यह कॉलम चुप्पी के बारे में है। चुप्पी, जो लंबे समय तक बनी रही थी, जिसे कभी साहस के साथ तोड़ा गया था और जो अब चुपचाप लौटती हुई मालूम होती है।

आठ साल पहले, भारत में महिलाओं ने आवाज उठाई थी। उन्होंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और ताकतवरों के सामने खड़े होकर सच कहा। ये सच इस उम्मीद के साथ बोले गए थे कि वे न केवल भ्रमों को मिटाएंगे, बल्कि उन्हें सम्भव बनाने वाली संरचनाओं को भी ध्वस्त करेंगे। 'मी-टू' आंदोलन महज एक क्षणिक घटना नहीं था, बल्कि आत्ममंथन और जवाबदेही का निर्णायक क्षण था।

वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने 'मी-टू' की लड़ाई कानूनी मोर्चे पर लड़ी थी। उन्होंने मुझसे कहा- मी-टू आंदोलन इस आधार पर खड़ा था कि पीड़िताएं उस चुप्पी को समाप्त करें, जिसने कार्यस्थलों और अन्य जगहों पर सत्ता के नियमित दुरुपयोग को कायम रखा था। लेकिन सच बोलने के लिए अनेक महिलाओं को गंभीर चुनौतियां झेलनी पड़ीं। उन पर मुकदमे तक दायर किए गए। जिन मामलों में पीड़िताएं कानूनी रूप से सफल भी रहीं, उनमें भी पुरुषों को कोई ठोस नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इसके उलट, हमने इन पुरुषों को उनके प्रभाव-क्षेत्रों में फिर से स्थापित होते देखा है। कुछ मामलों में यौन हिंसा की शिकायत के मामले न्यायिक जांच के फॉरेंसिक मानकों पर खरे नहीं उतर सके- जांच में छोड़ी गई खामियों या अयोग्यता के चलते। साथ ही, पीड़िताओं को लगातार सार्वजनिक बदनामी का भी सामना करना पड़ा। ध्यान देने वाली बात है कि पीड़िताओं और आरोपितों के बीच सामाजिक पूंजी और वर्ग-शक्ति का बहुत बड़ा अंतर था।

आलोचक अकसर यह कहकर बचाव में उतर आते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या का भारत ने पहले ही 2013 के पॉश कानून के जरिए समाधान कर लिया है। यह कानून यकीनन अपने समय में प्रगतिशील था- उसने एक औपचारिक नियोक्ता और निश्चित कार्यस्थल की परिकल्पना की थी। लेकिन आज की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से- गिग इकॉनोमी, मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म- संविदा, फ्रीलांस या अनौपचारिक व्यवस्थाओं पर चलते हैं।

कोलकाता उच्च न्यायालय की एक अधिवक्ता ने कहा- हम सबने अपने पेशेवर जीवन में किसी न किसी रूप में इस बुराई का सामना किया है। कानून की दुनिया भी इससे अछूती नहीं है। हम किससे शिकायत करें? शी-बॉक्स का अता-पता नहीं है। पॉश ट्रेनिंग की अनदेखी की जाती है, क्योंकि धारणा बना दी गई है कि इससे महिलाएं कानून का 'दुरुपयोग' करना सीख लेंगी।

भारत में ऐसे कानूनी प्रावधान नहीं हैं, जो सत्ता-संबंधों के संदर्भ में यौन दुराचार के सार्वजनिक खुलासों को संबोधित करते हों। 'मी-टू' के खुलासों पर भी हमने कोई नया कानूनी ढांचा विकसित नहीं किया। इसके बजाय मौजूदा कानून- विशेषकर मानहानि संबंधी प्रावधान- ऐसे मामलों में आगे की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने लगते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी ने वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में कहा है- जो पुरुष मौजूदा सत्ता-व्यवस्था से जुड़े हैं और जिन्होंने वर्तमान तंत्र के भीतर स्वीकार्यता बना ली है, वे चुपचाप अपने जीवन को फिर से स्थापित कर चुके हैं। लेकिन जिन्हें व्यवस्था-विरोधी माना गया, उन्हें अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद भी वापसी करने का अवसर नहीं दिया गया है।

> **भारत में ऐसे कानूनी प्रावधान नहीं हैं, जो सत्ता-संबंधों के संदर्भ में यौन दुराचार के सार्वजनिक खुलासों को संबोधित करते हों। वास्तव में, 'मी-टू' के खुलासों के बाद भी हमने कोई नया कानूनी ढांचा विकसित नहीं किया है।**

गहरे पितृसत्तात्मक संस्कार ही मी-टू आंदोलन के आरोपितों के खिलाफ समाज में वास्तविक आक्रोश के अभाव का कारण हैं। वास्तव में पीड़ा या आक्रोश के बजाय, उलटे एक तरह की व्यंग्यात्मक सहमति दिखाई देती है- आंख दबाकर दी गई स्वीकृति या हल्की मुस्कान के साथ चीजों को टाल देने की प्रवृत्ति, मानो दुराचार की घटनाएं महज 'लॉकर रूम' का मजाक हों।

जब किसी शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति सार्वजनिक रूप से महिला नेताओं का उपहास या उनकी उपेक्षा करता है, तब उसके खिलाफ हमारे नागरिक समाज का प्रतिरोध और स्पष्ट निंदा कहां रहती है? जब महिलाओं के साथ गम्भीर प्रताड़ना के आरोप झेल रहे लोगों को भी साहित्य उत्सवों और संस्कृति समारोहों में अहर्निश आमंत्रित किया जाता रहता है, तब तो हमें इस कठोर सच का सामना करना ही पड़ेगा कि- स्त्रीद्वेष आज समाज में मुख्यधारा का हिस्सा बन चुका है!

(ये लेखक के अपने विचार हैं। लेख की सहायक शोधकर्ता चाहत मंगतानी और वर्णिका मिश्रा हैं)

दूरदृष्टि • यूएस बाजारों में हो रहा है रिकॉर्ड निवेश

ट्रम्प से नाराजगी के बावजूद अमेरिका में खूब पैसा आ रहा

मार्केट

रुचिर शर्मा
ग्लोबल इन्वेस्टर व लेखक
breakoutnations@gmail.com

अमेरिका के मामले में आज दुनिया भर के निवेशकों का रवैया यह है कि दिन भर आलोचना करो, रात भर खरीदारी करो। हाल ही में एशिया, यूरोप और मध्य-पूर्व की यात्रा के दौरान मुझे महसूस हुआ कि ट्रम्प के नेतृत्व वाले अमेरिका को लेकर कितनी शिकायतें हैं। चाहे टैरिफ का मुद्दा हो, ग्रीनलैंड की बात हो या पुरानी विश्व-व्यवस्था के प्रति उदासीनता की- दुनिया भर में अमेरिका के प्रति नकारात्मक धारणा बढ़ रही है। लेकिन जब मैं न्यूयॉर्क लौटा और आंकड़ों पर नजर डाली, तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी।

भले ही अमेरिका के प्रति राय नकारात्मक होती जा रही हो, पैसा पहले से कहीं अधिक मात्रा में अमेरिका की ओर बह रहा है। पिछले वर्ष विदेशियों ने अमेरिकी फाइनेंशियल एसेट्स में 1.6 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया, जिसमें करीब 700 अरब डॉलर तो केवल शेयर बाजार में लगाए गए। ये दोनों ही रिकॉर्ड आंकड़े हैं और बीते वर्षों की तुलना में काफी अधिक हैं। अमेरिकी कॉर्पोरेट बॉन्ड के मामले में भी यही रुझान दिखा, जहां विदेशी खरीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।

तो सवाल यह है कि जिस देश के प्रति सार्वजनिक रूप से नाराजगी बढ़ती जताई जा रही है, उसमें इतनी मात्रा में निवेश क्यों हो रहा है? इसका एक कारण इनर्शिया है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अभी तक अमेरिका का प्रदर्शन दुनिया के अधिकांश देशों से बेहतर रहा है। निवेशक बीते प्रदर्शन का पीछा करते हैं। उन्होंने मान लिया है कि विशाल आकार और लिक्विडिटी के कारण फिलहाल तो अमेरिकी बाजारों में निवेश का कोई विकल्प नहीं है।

दुनिया अब भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका की बढ़त से प्रभावित है। यूरोपीय निवेशक लंबे समय से अमेरिकी टेक शेयरों के उत्साही खरीदार रहे हैं, पर पिछले वर्ष अमेरिकी शेयर बाजार में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत दक्षिण कोरिया रहा है। यह एक ऐसा देश है, जहां अमेरिका या एआई से जुड़े एसेट्स के प्रति आकर्षण बेहद तीव्र है।

भारत में भी यह ट्रेंड दिखता है। 2025 में भारतीयों ने विदेशों में लगभग हर श्रेणी- यात्रा, शिक्षा, उपहार- पर पिछले वर्ष की तुलना में कम खर्च किया, लेकिन पोर्टफोलियो निवेश में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार द्वारा निवेश की सीमाओं में ढील दिए जाने से भारतीयों के लिए विदेशी फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदना आसान हुआ है और इन निवेशों का चौंकाने वाला 99 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका की ओर जा रहा है। इसका भी एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में जाता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा सीधे अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में निवेश होता है- विशेषकर उन बड़ी टेक कंपनियों में, जो एआई क्रांति के केंद्र में हैं।

बाजार के रुझान स्थायी नहीं होते और 'दिन भर आलोचना, रात भर खरीदारी' की आदत भी इससे अलग नहीं। अमेरिका में एआई शेयरों को लेकर जो उन्माद है, वह अस्तित्वगत प्रश्न खड़े कर रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि एआई की दौड़ में कौन-सी कंपनियां विजेता बनेंगी और यह भी निश्चित नहीं कि वे अमेरिकी ही होंगी। चीन ने दिखा दिया है कि वह प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उसके कुछ एआई मॉडल अमेरिकी मॉडलों जैसा ही प्रदर्शन कम ट्रेनिंग-लागत पर दे रहे हैं।

इधर अमेरिकी बाजार की प्रभुत्वशाली स्थिति और उसकी अनिश्चितता के जवाब में अन्य सरकारें भी अपने जोखिमों में विविधता लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। वे ट्रेड डील कर रही हैं, विनियमन में ढील दे रही हैं और रक्षा तथा स्थानीय प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ा रही हैं। पिछले वर्ष अमेरिका में पूंजी के भारी प्रवाह के बावजूद दुनिया के अन्य हिस्सों के बाजारों ने प्रदर्शन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया।

> **विदेशी निवेशक अमेरिका की चाहे जितनी बुराई करें, उनके पास अब 70 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी एसेट्स हैं- जो एक दशक पहले के स्तर के दोगुने हैं। जब तक यह जारी रहेगा, अमेरिकी बाजारों पर असर नहीं पड़ने वाला है।**

अमेरिका के बाहर ग्रोथ में तेजी आने के साथ यह रुझान और मजबूत हो रहा है। इस वर्ष और अगले वर्ष अन्य अर्थव्यवस्थाओं के अमेरिका की तुलना में डेढ़ गुना तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। 2027 तक उभरते बाजारों में औसत या समान कॉर्पोरेट मुनाफा अमेरिका की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ने का अनुमान है, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह वृद्धि दर लगभग 50 प्रतिशत अधिक रहने की संभावना है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक | **zomato** | भारत की बहुराष्ट्रीय फूड टेक कंपनी

6 बार गंभीर संकट में फंसी, 15 साल तक घाटा उठाया, जोमेटो आज देश की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी

वर्ष 2015 की शुरुआत, जोमेटो ने अमेरिका की बड़ी फूड टेक कंपनी 'अर्बनस्पून' को करीब 350 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उस समय यह किसी भारतीय स्टार्टअप द्वारा विदेश में किए गए सबसे बड़े अधिग्रहण में से एक था। कंपनी का यह दांव उस पर भारी पड़ा। वहां के बाजार में पहुंच बनाने के लिए बेहद संघर्ष करना पड़ा। इसके अलावा जोमेटो ने अमेरिका, यूरोप के करीब 23 देशों में एक साथ विस्तार करने की गलती कर दी। नतीजा यह हुआ कि कंपनी का कैश तेजी से बर्न होने लगा। घाटा बढ़ता गया। हालात इतने बिगड़ गए कि 2016 में बैंकिंग और वित्तीय सेवा संगठन एचएसबीसी ने जोमेटो की वैल्युएशन एक अरब डॉलर से घटाकर 50 करोड़ डॉलर कर दी।

इस संकट से निकलने के लिए जोमेटो को अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों से बिजनेस समेटना पड़ा। करीब 300 कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल खुद एक पॉडकॉस्ट में कह चुके हैं कि कंपनी 6 बार गंभीर आर्थिक संकट में फंस चुकी है। 2008 में शुरू हुई कंपनी को 2023 की पहली तिमाही में प्रॉफिट हुआ। गलतियों से सीखने और रणनीतियों में बदलाव करने से यह आज देश की नंबर वन फूड टेक्नोलॉजी कंपनी/एग्रीगेटर बन गई है। ब्रांड से सबक में आज पढ़िए कहानी जोमेटो की।

वर्तमान स्थिति

फूड डिलीवरी बाजार के 58% हिस्से पर कब्जा है

वर्तमान में कंपनी फूड डिलीवरी के अलावा क्विक कॉमर्स, गोइंग-आउट और बी2बी सप्लाई सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी इस समय देश के 800 से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार इसे रोजाना औसतन 40 लाख ऑर्डर मिल रहे हैं। देश के फूड डिलीवरी बाजार में इसकी हिस्सेदारी करीब 58% और क्विक कॉमर्स में करीब 46% है। वर्तमान में इसकी पैरेंट कंपनी इटर्नल का बाजार मूल्य करीब 2.70 लाख करोड़ रुपए है।

सबक क्यों- 2008 में शुरू हुई कंपनी 2023 में पहली बार प्रॉफिट में आई। गलतियों से सबक सीखे, आज देश की शीर्ष फूड टेक कंपनी।

दीपिंदर गोयल (बाएं) और पंकज चड्ढा ने रखी थी नींव

40 लाख ऑर्डर औसतन रोज मिल रहे हैं कंपनी को वर्तमान में।

58 प्रतिशत हिस्सेदारी है इस समय देश के फूड डिलीवरी बाजार में।

800 से अधिक भारतीय शहरों में अभी जोमेटो फूड डिलीवरी से जुड़ी सेवाएं दे रही है।

46 प्रतिशत हिस्सेदारी है क्विक कॉमर्स में उसकी ब्लिंकिट के माध्यम से।

इन कारणों से आया था संकट

1. **अंधाधुंध विस्तार-** शुरुआत में जोमेटो ने खुद को ग्लोबल बनाने के लिए दर्जनों देशों में वहां का बाजार समझे बिना विस्तार किया, जबकि वहां से रेवेन्यू न के बराबर था। इससे 2015-16 में आर्थिक संकट आया।
2. **प्राइस वॉर में भारी डिस्काउंट :** स्विगी से प्राइस वॉर जीतने के चक्कर में 'एक पर एक फ्री' और भारी कैशबैक दिए। इससे बैलेंस शीट बिगड़ती गई।
3. **रेस्तरां पार्टनर्स से टकराव :** जोमेटो गोल्ड प्लेटफॉर्म पर दर्ज रेस्तरां को ज्यादा कमीशन और छूट देने के लिए मजबूर किया। नतीजा 2019 में 'लॉगआउट कैंपेन' के रूप में आया। बड़ी संख्या में रेस्तरां इससे बाहर हो गए।
4. **लगातार बिजनेस मॉडल बदला :** जोमेटो शुरू में सिर्फ 'मेन्यू स्कैन' करने वाली साइट थी, फिर एडवरटाइजिंग मॉडल, फिर फूड डिलीवरी, फिर ग्रॉसरी और फिर सप्लीमेंट्स। इससे संसाधन बर्बाद हुए।

इस तरह हर बार की वापसी

1. **गलतियों को सुधारना-** जब इंटरनेशनल बिजनेस से केवल नुकसान हुआ तो तुरंत कई देशों में काम बंद किया। 'कैशलेस' पेमेंट बिजनेस नहीं चलने पर छोड़ा। भारत के कोर मार्केट पर फोकस किया।
2. **ब्लिंकिट का अधिग्रहण :** जब फूड डिलीवरी की ग्रोथ धीमी हो रही थी, जोमेटो ने ग्रोफर्स को खरीदकर 'ब्लिंकिट'बनाया। यह फैसला गेम-चेंजर साबित हुआ।
3. **आईपीओ और कैश रिजर्व-** 2021 में जोमेटो ने आईपीओ के रूप में बड़ा जुआ खेला, जो सफल रहा। इसने कंपनी को इतना पैसा दिया कि वह ब्लिंकिट जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा कर सके, जिससे उसे स्विगी जैसी प्रतिस्पर्धी से लड़ाई लड़ने में मदद मिली।
4. **प्रॉफिट बढ़ाया :** 2020 के संकट के बाद, कंपनी ने 'ग्रोथ' की जगह 'प्रॉफिट' को चुना। डिलीवरी चार्ज लेना शुरू किया, डिस्काउंट घटाए और प्लेटफॉर्म फीस जैसी चीजें जोड़ीं।

टोमेटो.कॉम डोमेन न मिलने पर जोमेटो रखा गया था नाम

शुरुआत : रेस्तरां खोजने वाली वेबसाइट के रूप में हुई थी शुरू

जोमेटो की शुरुआत 2008 में हुई। एक दिन दीपिंदर और उनके साथी पंकज चड्ढा ने देखा कि ऑफिस कैफेटेरिया में लोग लंच मेन्यू के लिए लंबी लाइन लगाए हैं। उन्होंने मेन्यू को स्कैन करके एक इंट्रानेट वेबसाइट पर डाल दिया। यह हिट हो गया। इसके बाद Foodiebay.com नाम से वेबसाइट शुरू की। शुरुआत में यह सिर्फ रेस्तरां खोजने के लिए थी, खाना डिलीवर करने के लिए नहीं।

गंभीर संकट : 2020 में रेवेन्यू ठप हुआ, सिर्फ 45 दिन का कैश बचा

2020 का कोविड लॉकडाउन कंपनी के लिए सबसे बड़ा संकट लेकर आया। एक पॉडकास्ट में दीपंदर कहते हैं- फूड डिलीवरी रातोंरात बंद हो गई। रेवेन्यू जीरो हो गया, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट यानी की कर्मचारियों का वेतन, किराया, सर्वर की लागत आदि जारी रहे। एक समय कंपनी के पास केवल 45 दिनों का कैश बचा था। कंपनी को 13% स्टाफ की छंटनी करनी पड़ी।

ऐसे पड़ा नाम : शुरुआती नाम 'Foodiebay' था, दीपिंदर 'Tomato.com' डोमेन चाहते थे। बाद में 'T' को 'Z' से बदलकर 'Zomato' कर दिया।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : स्विगी देश में जोमेटो का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, जो फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में सीधी टक्कर देता है।

पीपुल भास्कर | **इमैनुएल मैक्रों** | फ्रांस के राष्ट्रपति

नेपोलियन के बाद फ्रांस के सबसे युवा 'मुखिया', ट्रेंड पियानोवादक हैं, 4 से 5 घंटे ही सोते हैं मैक्रों

साल 2016, फ्रांस की तत्कालीन सरकार में इकोनॉमी मिनिस्टर रहे इमैनुएल मैक्रों ने देश में एक राजनीतिक आंदोलन शुरू किया। इसका नाम था 'एन मार्श', जिसका अर्थ है 'आगे बढ़ो'। इस आंदोलन में सैकड़ों की तादाद में वॉलेंटियर्स जोड़े गए, जिन्होंने लाखों घरों में लोगों से जाकर बात की। 25 हजार से ज्यादा इंटरव्यू किए। आंदोलन इतना सफल रहा है कि फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन के बाद इमैनुएल मैक्रों दूसरे सबसे युवा सर्वोच्च नेता यानी राष्ट्र के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति बने। नेपोलियन 30 साल की उम्र में देश के सर्वोच्च नेता बने थे। मैक्रों 39 की उम्र में राष्ट्रपति बने।

स्वभाव से दार्शनिक मैक्रों बेहतरीन पियानोवादक, नॉवलिस्ट और कलाकार हैं। वे रोज करीब 4 से 5 घंटे की ही नींद लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उनका स्टाफ कई बार कह चुका है कि मैक्रों रात में 2 से 3 बजे के बीच भी टेलीग्राम में मैसेज भेजते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जवाब मिले। हालांकि स्टाफ इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए यह मानता है कि काम के प्रति उनकी ऊर्जा काफी अधिक है।

मैक्रों को खाने में फ्राइड चिकन डिश 'कॉर्डन ब्लू' बहुत पसंद है। उन्हें जानवरों से भी काफी लगाव है। उन्होंने एक डॉग भी गोद लिया है, जिसका नाम 'नीमो' है। यह नाम उन्होंने अपनी पसंदीदा किताब 'ट्वेंटी थाउजेंड लीग्स अंडर द सी' के कैप्टन के नाम पर रखा है। वे फुटबॉल के शौकीन हैं। फुटबॉल को वे फ्रांस की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हैं।

चर्चा में क्यों- 17 फरवरी को वे भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान रक्षा सहित कई मुद्दों पर बड़े समझौतों की उम्मीद है।

मैक्रों फुटबॉल के शौकीन हैं। फ्रांस के मशहूर फुटबॉल क्लब 'ओलिंपिक डी मार्साई' के बड़े प्रशंसक हैं।

2017 में मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति बने। फ्रांसीसी गणतंत्र में 1958 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि चुना गया राष्ट्रपति दो प्रमुख दलों- सोशलिस्ट और सेंटर राइट रिपब्लिकन पार्टी में से नहीं था।

जन्म : 21 दिसंबर 1977, अमीस, फ्रांस।
शिक्षा : पेरिस नांतेयर यूनिवर्सिटी से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर।
संपत्ति : करीब 287 करोड़ रु.
(विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स)

परिवार

पिता न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर, मां डॉक्टर थीं

इमैनुएल मैक्रों के पिता ज्यां-मिशेल न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर थे जबकि मां फ्रांस्वा नोगेस, फिजिशियन थीं। मैक्रों अपनी दादी मैनेट के बहुत करीब थे। मैक्रों कहते हैं उनकी वामपंथी सोच और पढ़ने का शौक उनकी दादी की ही देन है। उनके दो छोटे भाई-बहन हैं और दोनों ही डॉक्टर हैं। मैक्रों परिवार के इकलौते सदस्य हैं, जिन्होंने डॉक्टर बनने की परंपरा तोड़ी है।

विवाह

24 साल बड़ी ड्रामा टीचर से की है शादी

1993 में पंद्रह वर्ष की उम्र में इनकी मुलाकात ब्रिज़िट ऑजिएर से हुई। एक थिएटर में इमैनुएल इनके छात्र थे। ब्रिजिट उम्र में लगभग 24 वर्ष बड़ी थीं। थिएटर वर्कशॉप के दौरान ही दोनों में प्यार हो गया। साल 2007 में उन्होंने शादी कर ली। ब्रिजिट के पहली शादी से तीन बच्चे हैं। मैक्रों की खुद की कोई संतान नहीं है। सौतेले बच्चों से 7 पोते-पोतियां हैं।

करियर

इंस्पेक्टर से राष्ट्रपति भवन तक का सफर

मैक्रों ने फ्रांस के वित्त मंत्रालय में फाइनेंस इंस्पेक्टर के रूप में करियर शुरू किया, लेकिन यह नौकरी रास नहीं आई। 2008 में 'रोथ्सचाइल्ड एंड कंपनी' में बैंकर बन गए। 2012 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार फ्रांस्वा ओलांद के लिए प्रचार किया। उनकी सरकार में 2014 में वित्तमंत्री बने। इसके बाद 2017 में खुद चुनाव लड़ा और सबसे युवा राष्ट्रपति बने।

रोचक : राजनीति में आने से पहले तीन उपन्यास लिख चुके हैं

खास : 10 साल तक शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली है

- मैक्रों ट्रेंड पियानोवादक हैं। उन्होंने 10 साल तक शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली है।
- मूलतः इनका परिवार गैर-धार्मिक है। पर इन्होंने 12 वर्ष की आयु में अपनी इच्छा से रोमन कैथोलिक के रूप में बेप्टीज्म कराया।
- राजनीति में आने से पहले वे 3 उपन्यास लिख चुके हैं। हालांकि उन्हें प्रकाशित नहीं कराया।

उपलब्धि : 15 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर बेरोजगारी

- इमैनुएल मैक्रों के कार्यकाल में फ्रांस की बेरोजगारी 15 वर्षों के सबसे निचले स्तर 7 प्रतिशत पर आ गई है।
- 2024 में उनके नेतृत्व में पेरिस ने ओलिंपिक की सफल मेजबानी की।
- 2002 के बाद वे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने, जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया।

विवाद : 2014 में 'गैड' के कर्मियों को गंवार कहा था

- मुस्लिम धर्म को दुनिया के लिए संकट वाला धर्म कह चुके हैं।
- साल 2014 में मीट प्रोसेसिंग कंपनी Gad SAS के कर्मचारियों को गंवार कह चुके हैं।
- एक बार उन्होंने गरीबी को लेकर लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना था कि लोग खुद गरीबी से बाहर नहीं निकलना चाहते।

भास्कर इन्फो

देश में 101 जीसीसी बने, 1.5 लाख जॉब पैदा हुईं

मुंबई | बीते वर्ष देश के ग्लोबल कैपिब्लिटी सेंटर (जीसीसी) में 1.5 लाख नौकरियां आईं। वहीं 101 नए जीसीसी सेंटर बने।

विवरण	आंकड़े
नई नौकरियां	1,50,000
नए जीसीसी	101
मौजूदा जीसीसी विस्तार	115-120
कुल जीसीसी	1,800+
कुल वर्किंग प्रोफेशनल्स	20 लाख

एआई से वर्कफ्लो री-डिजाइन:
- फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, एनालिटिक्स व कंप्लायंस के वर्कफ्लो री-डिजाइन हो रहे।
- एआई/क्लाउड/डेटा वाले रोल्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।

जीसीसी: 2025 में 6000 कर्मचारियों की छंटनी भी

जीसीसी में छंटनी क्यों हुई:
- टेक्नीकलर ने दिवालिया होने के चलते कर्मियों को निकाला।
- एआई आने से कुछ नौकरियों की जरूरत खत्म हो गई।
- कंपनियों ने प्रोजेक्ट बंद किए।

नया दौर • देश के टॉप-5 आईटी शेयर 2 साल में 32% तक गिरे, रिकवरी अभी दूर

आईटी इंडेक्स 10 माह के निचले स्तर पर, एआई से आय घटने का खतरा बढ़ा

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

देश के आईटी सेक्टर पर दबाव गहरा रहा है। इनके शेयरों में भारी गिरावट इसके साफ संकेत हैं। गुरुवार को सेंसेक्स 559 अंक गिरकर 83,675 पर और निफ्टी 145 अंक टूटकर 25,807 पर बंद हुआ। पर बीएसई का आईटी इंडेक्स 5% गिरकर 10 महीनों के निचले स्तर पर आ गया। यह सिर्फ एक दिन की कमजोरी नहीं है। 2025 में आईटी इंडेक्स 12.6% गिरा था। 2026 में भी अब तक यह 11% टूट चुका है। यानी इस सेक्टर पर दबाव लगातार बढ़ा है।

आईटी शेयरों की भारी गिरावट की मुख्य वजह एआई के गंभीर असर की आशंकाएं हैं। निवेशकों का मानना है कि एआई अब भारत के आईटी सर्विसेज सेक्टर में इंजीनियरों की जगह लेने के लिए तैयार है। इससे बिलेबल घंटे और कर्मचारियों की संख्या में कटौती हो सकती है। वैश्विक बाजारों में कंपनियों के खर्चों में कमी और कमजोर टेक सेंटिमेंट ने इस गिरावट को तेज कर दिया है।

इसलिए टूटे शेयर... एआई वही काम कर रही जो आईटी कंपनियां करती हैं

1 **बिजनेस मॉडल पर सवाल:** निवेशकों को डर है कि एआई-ऑटोमेशन टूल्स 'बिलेबल आवर' मॉडल को चुनौती दे सकते हैं। अगर क्लाइंट कम इंजीनियरों से ज्यादा काम करा पाएंगे तो आय पर असर पड़ेगा।

2 **क्लाउड कोवर्क जैसे टूल्स:** एआई कंपनी एंथ्रॉपिक का क्लाउड कोवर्क टूल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, लीगल टास्क ऑटोमेट कर सकता है। ये वही काम हैं जो अभी आईटी कंपनियां करती हैं। इससे घबराहट बढ़ी।

3 **आय पर संभावित दबाव :** जेफरीज का आकलन है कि एआई के कारण पारंपरिक आईटी कंपनियों की आय के कुछ हिस्से जोखिम में हैं। एआई अब सपोर्ट नहीं, रिप्लेसमेंट की दिशा में बढ़ रहा है।

4 **अमेरिका से अच्छे संकेत नहीं:** अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा नौकरियां बढ़ने के बाद वहां ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद घटी है। इससे टेक और आईटी शेयरों में बिकवाली तेज हुई।

जोखिम: इन आंकड़ों से समझें दबाव कितना है

आईटी इंडेक्स	गिरावट
2025 में	-12.6%
2026 में अब तक	-11%
4 फरवरी से गिरावट	-14%
बीते 2 साल में...	**गिरावट**
टीसीएस के शेयर	-32%
इन्फोसिस के शेयर	-17%
विप्रो के शेयर	-13%

आईटी कंपनियां एआई को अवसर में बदलें तो बात बने

ब्रोकरेज कंपनियों का मानना है कि आईटी कंपनियां यदि एआई को अवसर में बदल पाएं तो मौजूदा गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मौका बन सकती है। पर जब तक ऑर्डर बुक और कमाई में सुधार नहीं आता, एआई शेयरों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

कमजोरी: 2025 से अब तक 23% टूटा इंडेक्स

- 2025 में निफ्टी आईटी इंडेक्स 12.6% गिरा था। 2026 में भी अब तक इसमें 11% गिरावट आ चुकी है। ये गिरावट बढ़ ही रही है।
- 4 फरवरी को जब बिकवाली शुरू हुई थी, तब से घरेलू आईटी शेयरों में करीब 14% गिरावट आ चुकी है। यह बिकवाली जारी है।

बड़ा सवाल: फिलहाल संकेत डिमांड कोलैप्स के नहीं, बल्कि वैल्युएशन री-रेटिंग के हैं। यानी बाजार भविष्य के बदलाव को पहले ही कीमतों में शामिल कर ले रहा है। आईटी कंपनियां भी एआई अपनाने और नई सर्विसेज विकसित करने में जुटी हैं। ये प्रोजेक्ट सफल होने पर आईटी शेयर रिकवरी दिखा सकते हैं।

फूड डिलीवरी सेगमेंट • इस साल के मध्य तक आएगा आईपीओ

जोमैटो-स्विगी की प्लेट पर नजर: 81 हजार करोड़ रु. के बाजार में फ्लिपकार्ट की एंट्री

2030 तक 2.12 लाख करोड़ रु. का होगा बाजार

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट अब जोमैटो और स्विगी के दबदबे वाले 81,000 करोड़ के फूड डिलीवरी बाजार में टक्कर देने की तैयारी में है। कंपनी जून 2026 तक बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है। यह फ्लिपकार्ट को एक 'कंज्यूमर सुपर ऐप' में बदलने की तैयारी है।

दरअसल, फूड डिलीवरी सेगमेंट में घुसकर फ्लिपकार्ट 'हाई-फ्रीक्वेंसी' ट्रांजैक्शन हासिल करना चाहता है। ई-कॉमर्स जहां 'इवेंट-बेस्ड' है, वहीं फूड ऑर्डरिंग ग्राहकों को रोजाना ऐप खोलने पर मजबूर करती है। इससे न केवल यूजर रिटेंशन बढ़ता है, बल्कि कंपनी को लोकेशन और डिमांड पैटर्न का 'फर्स्ट पार्टी डेटा' भी मिलता है, जो एडवरटाइजिंग और पर्सनलाइजेशन में गेम-चेंजर साबित होता है। कंपनी का आईपीओ भी इस साल के मध्य तक आने वाला है। इस योजना से आईपीओ नैरेटिव को भी मजबूती मिलेगी। वहीं, फूड डिलीवरी सेगमेंट का मार्केट 2030 तक 2.12 लाख करोड़ होने का अनुमान है।

गेम बदला: अब इस सेक्टर में 21% तक की ग्रोथ

ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लंबे समय तक नुकसान वाले कारोबार के रूप में देखा गया। लेकिन तस्वीर बदल रही है। बीती तिमाहियों में जोमैटो-स्विगी जैसी कंपनियों ने 20-21% की ग्रोथ दर्ज की है। ऑर्डर वैल्यू बढ़ी है, औसत ऑर्डर साइज सुधरा है। सब्सक्रिप्शन मॉडल से भी आय बढ़ रही है। कंपनियां अब अंधाधुंध डिस्काउंट की बजाय मार्जिन संतुलन पर ध्यान दे रही हैं। विज्ञापन और डिलीवरी फीस जैसे नए स्रोत भी मजबूत हुए हैं। इसके चलते भी फ्लिपकार्ट इस सेगमेंट में उतरने जा रहा है।

अवसर: फूड सेगमेंट में आने से 2 लाख तक नई नौकरियां

फूड सेगमेंट में आने से दो लाख तक जॉब आ सकती हैं। कंपनी क्विक कॉमर्स 'मिनट्स' के 800+ डार्क स्टोर्स व फ्लीट का उपयोग फूड डिलीवरी के लिए करेगी। इस 'ओवरलैप' से कंपनी की यूनिट इकॉनॉमिक्स सुधरेगी व नया कैपेक्स कम लगेगा।

फायदा: ग्राहक और रेस्तरां मालिक दोनों को हो सकेगा

फ्लिपकार्ट सरकारी प्लेटफॉर्म ओएनडीसी के जरिए आता है, तो समीकरण बदलेंगे। जोमैटो-स्विगी 25-30% कमीशन लेते हैं, ओएनडीसी पर यह काफी कम है। ग्राहक-रेस्तरां मालिक दोनों को फायदा होगा। एंट्री के वक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है।

खतरा: फूड डिलीवरी सेगमेंट में ये दिग्गज फेल हो चुके हैं

अमेजन फूड (2022): 2 साल बाद अमेजन फूड में फेल।
उबर ईट्स (2020): भारी घाटे के बाद कारोबार बेचकर बंद।
ओला फूड्स: फूडपांडा को ओला ने खरीदा, असफल।

95% मार्केट पर दो का कब्जा

पैरामीटर	जोमैटो	स्विगी	फ्लिप.
मार्केट शेयर	50%	45%	---
डार्क स्टोर्स	639	580	800+
शहरों में	1000+	580+	---
लॉन्च	2008	2014	---

बिजनेस ब्रीफ

चांदी की कीमतें ₹7,316, सोने की ₹1,672 घटी

मुंबई | देशभर के सराफा बाजारों में गुरुवार को सोने-चांदी के दाम घटे। चांदी की औसत कीमत 7,316 रुपए घटकर 2,59,133 रुपए किलो रह गई। 24-कैरेट सोने की औसत कीमत 1,672 रुपए घटकर 1,55,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। 29 जनवरी को चांदी 3,79,988 रुपए किलो और सोना 1,75,340 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर थे।

जनवरी में शाकाहारी थाली 2%, नॉनवेज 3% सस्ती

मुंबई | जनवरी में घर पर खाना पकाना थोड़ा सस्ता हुआ। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक बीते माह शाकाहारी थाली की लागत दिसंबर-25 के मुकाबले 2% घटकर 28.5 रुपए रह गई। नॉनवेज थाली भी 3% सस्ती होकर 56.4 रुपए की रह गई। दिसंबर-25 में शाकाहारी थाली 29 रुपए और नॉनवेज थाली 58 रुपए की थी।

बिना मंजूरी वॉकी-टॉकी बेचने पर 10 लाख जुर्माना

नई दिल्ली | देश के सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ट्रेडइंडिया पर ₹10 लाख जुर्माना लगाया है। वजह ये रही कि प्लेटफॉर्म पर बिना जरूरी सर्टिफिकेशन वॉकी-टॉकी बेचे जा रहे थे। कई डिवाइस चीन में बने थे। फ्रीक्वेंसी बैंड और लाइसेंस जरूरत की जानकारी नहीं दी गई। जरूरी इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल (ईटीए) मंजूरी का भी खुलासा नहीं था।

स्पाइसजेट: दिसं. तिमाही में 269 करोड़ का घाटा

नई दिल्ली | बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को दिसंबर तिमाही में 269.27 करोड़ रु. का घाटा हुआ है। ज्यादा लागत व नए लेबर कोड के प्रभाव को एयरलाइन को यह नुकसान उठाना पड़ा है। बीते साल इसी तिमाही में कंपनी 24.97 करोड़ के फायदे में थी। दिसंबर तिमाही में कुल आय 7.8% घटकर 1,522 करोड़ रु. रह गई। ईंधन की बढ़ती कीमतों की गिरावट ने मुश्किलें बढ़ाईं।

चुनौती • कोर बिजनेस की रफ्तार अब भी धीमी

एचयूएल का लाभ दोगुना, पर आमदनी आइसक्रीम डिमर्जर से

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

डिटर्जेंट, पेस्ट जैसे रोजाना इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) का अक्टूबर-दिसंबर तिमाही का मुनाफा शानदार नजर आ रहा है। कंपनी ने 6,607 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो सालाना आधार पर 121% ज्यादा है। लेकिन इस उछाल की असली वजह ऑपरेशनल मजबूती नहीं, बल्कि आइसक्रीम बिजनेस क्वालिटी वॉल्स के डिमर्जर से मिला एकमुश्त लाभ है। ये अतिरिक्त आय हटाने पर कंपनी का टैक्स बाद मुनाफा सिर्फ 1% बढ़कर 2,562 करोड़ रह जाता है। यानी कोर बिजनेस की रफ्तार अभी धीमी है। संभवतः यही वजह रही कि मोटे तौर पर शानदार नतीजे के बावजूद बीएसई पर एचयूएल के शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 2,410 रुपए पर बंद हुए।

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों को ऐसे समझें

मानदंड	रिपोर्टेड	वास्तविक
मुनाफा	6,607	2,562
बढ़ोतरी	+121%	+1%
एबिटा	3,788	+3%
मार्जिन	23.3%	स्थिर

वेलबीइंग, हेल्थ बिजनेस मजबूत कर रही कंपनी

- एचयूएल ने बीती तिमाही ओजीवा में 49% हिस्सेदारी 824 करोड़ में खरीदी, जबकि वेलबीइंग न्यूट्रिशन में हिस्सेदारी बेची। इससे हेल्थ एंड वेलबीइंग पोर्टफोलियो मजबूत हुआ
- आइसक्रीम बिजनेस को अलग करने से कंपनी का ढांचा सरल हुआ है। इसके चलते कंपनी के मैनेजमेंट का फोकस मुख्य बिजनेस एफएमसीजी (साबुन, तेल, पेस्ट आदि) पर केंद्रित हुआ है।

आइसक्रीम बिजनेस अलग करने से 4.6 करोड़ एकमुश्त लाभ

एचयूएल ने आइसक्रीम बिजनेस को अलग कंपनी क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर किया है। इसकी लिस्टिंग जल्द होने वाली है। इस डिमर्जर से 4,611 करोड़ का एकमुश्त लाभ मिला, जो फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू के अंतर से आया। यह कंपनी के फोकस को कोर पोर्टफोलियो पर शिफ्ट करने का रणनीतिक कदम था।

सीसीआई की कार्रवाई: इंटेल पर 27.38 करोड़ का जुर्माना

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिग्गज टेक कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन पर 27.38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह कार्रवाई भारत के लिए बनाई गई भेदभावपूर्ण वारंटी नीति और बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल करने पर की है। इंटेल की यह नीति डेस्कटॉप के लिए बॉक्स माइक्रो प्रोसेसर्स (बीएमपी) से जुड़ी थी। सीसीआई ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि इंटेल की भारतीय वारंटी नीति चीन, ऑस्ट्रेलिया और बाकी दुनिया की तुलना में भेदभावपूर्ण थी। इस नीति ने न केवल उपभोक्ताओं के विकल्पों को सीमित किया, बल्कि उन आयातकों के लिए भी मुश्किलें पैदा कीं जो समानांतर तौर पर माल लाते थे। आयोग ने पाया कि यह व्यवस्था करीब 8 साल तक लागू रही, जिसका सीधा नुकसान भारतीय ग्राहकों को उठाना पड़ा। नियामक ने इंटेल को इस विवादित वारंटी नीति को वापस लेने की सूचना व्यापक स्तर पर प्रचारित करने और इसकी अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है।

ऑटोमोबाइल • एसयूवी सेगमेंट में आक्रामक प्रतिस्पर्धा के संकेत

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने लॉन्च की देश की सबसे लंबी, चौड़ी, ऊंची एसयूवी मैजेस्टर, दाम अभी तय नहीं

भास्कर न्यूज़ | गुरुग्राम

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने डी प्लस सेगमेंट की नई एसयूवी 'मैजेस्टर' लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह भारत की सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची एसयूवी है। आकार के मामले में यह टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी बड़ी बताई जा रही है। कंपनी ने गाड़ी को अरावली की मांगर पहाड़ियों के बीच गुरुवार को ऑफ-रोड ट्रैक पर लाइव डेमो दिया। इस दौरान उबड़-खाबड़ रास्तों,कीचड़, पत्थरों के बीच चलाकर इसकी ऑफ-रोडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। जेएसडब्ल्यू एमजी के एमडी अनुराग मेहरोत्रा के अनुसार प्रीमियम एसयूवी ग्राहक स्पेस के साथ शानदार लाइफस्टाइल वाली गाड़ियां पसंद कर रहे हैं। 'मैजेस्टर' की प्री-बुकिंग कंपनी www.mgmotor.co.in पर शुरू हो चुकी है। ग्राहक इसे 41 हजार रुपए देकर रिजर्व कर सकते हैं। कीमत का ऐलान कंपनी अप्रैल में करेगी। शोरूम पर गाड़ियां अप्रैल में पहुंचना शुरू होंगी। उसी समय ग्राहकों को टेस्ट ड्राइव की सुविधा भी मिलेगी। मई से कंपनी ग्राहकों को इसकी डिलीवरी शुरू करेगी।

क्षमता: 4x4 सिस्टम से हर बाधा पार करेगी 'मैजेस्टर'

'मैजेस्टर' को बेहद बोल्ड डिजाइन और दमदार रोड प्रेजेंस के साथ तैयार किया गया है। यह 4x4 सिस्टम से लैस है जो इसे मुश्किल रास्तों का राजा बनाती है। डेमो के दौरान गाड़ी ने बिना रुके पत्थरों और गहरे कीचड़ को आसानी से पार किया। यह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी जो ड्राइविंग को और आसान बनाएगी।

दावा: डी प्लस सेगमेंट में नया बेंचमार्क सेट करेगी मैजेस्टर

कंपनी ने इसे डी प्लस सेगमेंट की पहली गाड़ी बताकर नया बाजार तैयार किया है। जेएसडब्ल्यू एमजी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विनय राणा ने बताया कि यह शहरी सड़कों और पहाड़ों के लिए समान रूप से सक्षम है।

फेरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार

टचस्क्रीन के ट्रेंड पर ब्रेक... स्क्रीन छोड़ बटन पर लौटी फेरारी; आईफोन डिजाइनर ने की है डिजाइन

रोम | फेरारी की इलेक्ट्रिक कार 'लूच' के इंटिरियर ने हैरान कर दिया है। कार का कॉकपिट डिजिटल ट्रेंड से अलग हटकर पुराने दौर में लौटता हुआ दिखता है। इस कार में तीन-लेयर इंस्ट्रूमेंट स्टीयरिंग कॉलम से जुड़ा हुआ है। टचस्क्रीन के बजाय एल्युमिनियम टॉगल, रोटरी नॉब और ग्लास की प्रमुख भूमिका हैं।

- आईफोन-आईमैक के डिजाइनर जॉनी आइव की अगुवाई में तैयार कॉकपिट।
- लॉन्च कंट्रोल के लिए एल्युमिनियम हैंडल। पहली ईवी में 1960 दशक की डिजाइन का असर दिखता है।

राहत • आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी

बैंक रिकवरी एजेंट ग्राहकों को अब धमका नहीं पाएंगे

मुंबई | रिजर्व बैंक कर्ज वसूली में बैंकों के एजेंटों के हिंसक तरीकों पर रोक जा रहा है। नए नियमों के तहत बैंक कर्मचारी या एजेंट ग्राहकों को फोन पर धमकी नहीं दे पाएंगे। उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, गुमनाम नंबरों से बार-बार कॉल करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अब गैर-कानूनी होगा। ड्राफ्ट के अनुसार, एजेंट केवल कर्जदार या गारंटर से ही बात कर सकेंगे। रिश्तेदारों, पड़ोसियों या ऑफिस के सहयोगियों को परेशान करना प्रतिबंधित होगा। आरबीआई ने साफ किया है कि वसूली प्रक्रिया में किसी भी दुर्व्यवहार के लिए सीधे तौर पर बैंक जिम्मेदार होंगे। यह नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। केंद्रीय बैंक ने इस ड्राफ्ट पर जनता से 4 मार्च 2026 तक राय मांगी है। नियमों के लागू होने के बाद बैंकों को वसूली प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी। वसूली के नाम पर अब किसी की निजता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वक्त: सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ही वसूली

आरबीआई ने वसूली के लिए सुबह 8 से शाम 7 बजे का समय तय किया है। बैंक अब अपनी मर्जी से बेवक्त कॉल कर ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। यदि ग्राहक किसी विशेष समय पर बात करने से मना करता है, तो बैंकों को इसका सम्मान करना होगा।

पारदर्शिता: वेबसाइट पर होगी एजेंटों की लिस्ट

बैंकों को अपनी शाखाओं और वेबसाइट पर सक्रिय रिकवरी एजेंटों की अपडेटेड सूची देनी होगी। यदि किसी एजेंट का अनुबंध खत्म होता है, तो उसकी सार्वजनिक सूचना देना जरूरी होगा। इससे ग्राहक केवल अधिकृत व्यक्तियों से ही संपर्क कर पाएंगे।

मर्यादा: शादी-त्योहारों पर घर नहीं आएंगे एजेंट

बैंक, एनबीएफसी के वसूली एजेंटों को घर जाते समय शालीनता और शिष्टाचार का पालन करना होगा। आरबीआई के अनुसार परिवार में मौत, आपात स्थिति, शादी या त्योहारों जैसे मौकों पर वसूली के प्रयास नहीं होंगे। ऐसे समय में एजेंटों का घर आना प्रतिबंधित रहेगा।

रेगुलेटरी खर्च घटाने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाएगा सेबी

मुंबई | बाजार नियामक सेबी ने बाजार इकोसिस्टम में रेगुलेटरी लागत कम करने के लिए कई बड़े उपायों पर विचार शुरू कर दिया है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडेय ने मुंबई में आयोजित छठे एनआईएसएम-सेबी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। पांडेय ने जोर दिया कि उत्पादक क्षेत्रों के लिए केवल वित्त की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि उसकी लागत (कॉस्ट ऑफ कैपिटल) कम होना भी जरूरी है। उन्होंने आगाह किया कि यदि नियमों के पालन में समय और पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी। इसी लागत को नियंत्रित करने के लिए सेबी अपने आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग (डीईपीए) के तहत एक 'सेंटर फॉर रेगुलेटरी स्टडीज' स्थापित करेगा।

बिजनेस एंकर

मुफ्त एआई के बदले विज्ञापन या एड-फ्री अनुभव के लिए भुगतान? अब यही असली दांव

एआई में विज्ञापन आएंगे या नहीं, सुपर बाउल में एंथ्रॉपिक का दांव- क्लॉड एड-फ्री रहेगा, ओपनएआई ने कहा-हम यूजर्स को बेवकूफ नहीं समझते

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

सुपर बाउल की चमकती स्क्रीन पर इस बार सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जंग भी देखी गई। फर्क सिर्फ ये रहा कि पहले की तरह पेप्सी और कोका-कोला नहीं, बल्कि एंथ्रॉपिक और ओपनएआई आमने-सामने थे। मसला था- एआई में विज्ञापन होंगे या नहीं? यही बहस भविष्य में एआई का स्वरुप तय करने वाला है। ओपनएआई ने हाल ही में संकेत दिया कि वह अपने चैटबॉट चैटजीपीटी में विज्ञापन लाने की दिशा में काम कर रहा है। कंपनी का तर्क साफ है, सैकड़ों करोड़ यूजर्स को फ्री सर्विस जारी रखने के लिए एक टिकाऊ मॉडल चाहिए। लेकिन इसी बीच प्रतिद्वंद्वी एंथ्रॉपिक ने बड़ा दांव चल दिया। कंपनी ने सुपर बाउल के लिए मल्टी-मिलियन-डॉलर का विज्ञापन अभियान लॉन्च किया। इसकी टैगलाइन थी 'एआई में अब विज्ञापन आने वाले हैं। लेकिन क्लॉड में नहीं आएंगे।' यह सीधा संदेश था कि उनका एआई असिस्टेंट क्लॉड विज्ञापन-मुक्त रहेगा।

एंथ्रॉपिक के चार विज्ञापनों 'छलावा', 'धोखा', 'उल्लंघन' और 'कपटपूर्ण विश्वासघात' में ऐसे काल्पनिक दृश्य दिखाए गए, जहां एक एआई असिस्टेंट बातचीत के बीच अचानक किसी प्रोडक्ट की सिफारिश करने लगता है। संदेश साफ था- अगर एआई में विज्ञापन आए, तो क्या वह निष्पक्ष रहेगा? इशारा किसकी ओर है, यह समझना मुश्किल नहीं था। इस पर ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ओपनएआई वैसे विज्ञापन कभी नहीं चलाएगा जैसे एंथ्रॉपिक ने दिखाए हैं, क्योंकि यूजर्स उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। ऑल्टमैन ने यह भी आरोप लगाया कि एंथ्रॉपिक कुछ कंपनियों को क्लॉड के इस्तेमाल से रोकता है और यह तय करना चाहता है कि लोग एआई के साथ क्या करें और क्या नहीं। दूसरी तरफ दावा किया कि ओपनएआई विस्तृत और लोकतांत्रिक पहुंच के पक्ष में है। बहरहाल, एंथ्रॉपिक अपनी स्थिति पर कायम है। मतलब क्लॉड विज्ञापन-मुक्त रहेगा। दूसरी ओर ओपनएआई कहती है कि अगर विज्ञापन मॉडल अपनाया गया, तो वह नियंत्रित, पारदर्शी और यूजर-फ्रेंडली होगा। असल में यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस मॉडल की नहीं है। यह इस बात की जंग है कि भविष्य का एआई कैसा होगा- पूरी तरह फ्री और विज्ञापन समर्थित या सब्सक्रिप्शन आधारित और विज्ञापन-मुक्त? जब एआई हमारे सोचने, खोजने और फैसले लेने के तरीके को प्रभावित करने लगा है, तब यह बहस और गंभीर हो जाती है।

बड़ा सवाल...एआई की पारदर्शिता, सीमाएं किस तरीके से तय होंगी

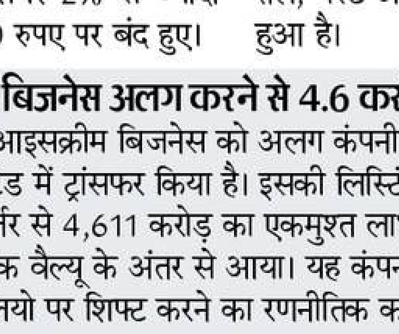

डारियो अमोदेई | सैम ऑल्टमैन

एंथ्रॉपिक और ओपनएआई के बीच टकराव असल में भविष्य के मॉडल को लेकर है। ओपनएआई का कहना है कि विज्ञापन से फ्री एक्सेस बनाए रखा जा सकता है, बशर्ते पारदर्शिता और सीमाएं तय हों। दूसरी तरफ एंथ्रॉपिक का दावा है कि एआई में विज्ञापन आने से निष्पक्षता और भरोसे पर असर पड़ सकता है, इसलिए क्लॉड एड-फ्री रहेगा। लेकिन क्या लोग मुफ्त एआई के बदले विज्ञापन स्वीकार करेंगे, या वे एड-फ्री अनुभव के लिए भुगतान करना पसंद करेंगे? यही इस जंग का असली दांव है।

निवेश • म्यूचुअल फंड 17%, को, शेयर 7% को पसंद

अब 62% युवाओं को निवेश में सोने पर म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा भरोसा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

देश के युवा इन दिनों निवेश के मामले में सोने को सबसे भरोसेमंद विकल्प मान रहे हैं। स्मिपटेन पल्स एआई के सर्वे में 62% जेन-जी और मिलेनियल्स (18 से 39 साल) ने सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना। म्यूचुअल फंड और शेयर जैसे कई विकल्पों की मौजूदगी के बावजूद 62% लोगों ने कहा कि वे 25 हजार रुपए निवेश करने के लिए केवल सोना ही चुनेंगे। वहीं, म्यूचुअल फंड को महज 16.6% वोट मिले, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) को 13% और शेयर बाजार को 6.6% युवाओं ने पसंद किया। क्रिप्टो में महज 1.9% लोग ही रुचि रखते हैं।

प्राथमिकता: पहली सैलरी पर सोना खरीदने का क्रेज, 24% ने खरीदा

देश में पहली सैलरी पर सोना खरीदने का चलन बढ़ा है। 24% युवाओं ने नौकरी शुरू होते ही गोल्ड खरीदा। वहीं 24% ने इसे शुद्ध निवेश माना। अब शादियां सोना खरीदने का एकमात्र कारण नहीं रही हैं।

थोड़ा ही सही... 62 फीसदी ने लिया 5 ग्राम से भी कम सोना, 27% ने 2 ग्राम

अब भारी गहनों के बजाय कम वजन वाले सोने की मांग बढ़ रही है। सर्वे में 61.9 फीसदी युवाओं ने बताया कि उनकी पिछली खरीदारी 5 ग्राम से कम की थी। 27.5% लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 ग्राम से भी कम सोना खरीदा।

पुढारी

संस्थापक - संपादक कै. पद्मश्री डॉ. ग. गो. जाधव,
मुख्य संपादक - डॉ. प्रतापसिंह ग. जाधव (पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित)

माघ कृ. ११, शके १९४७, श्री शिवशक ३५२ | ६
शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी २०२६
• वर्ष : ८८ • अंक : २७९

पाकिस्तानला उपरती!

पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हे पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज शरीफ) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते. २०१३ ते २०१७ या कालावधीत ते संरक्षणमंत्री होते आणि वादग्रस्त वक्तव्ये करण्याबद्दल त्यांची ख्याती आहे. 'भारतावर अणुबॉम्ब टाकू', 'भारताला अद्दल घडवू', अशा पोकळ धमक्या त्यांनी दिल्या होत्या. पहलगाम कांडानंतर भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केल्यावर पाकच्या संसदेत काही खासदार घाबरून रडू लागले आणि आसिफ यांनाही दरदरून घाम फुटला होता. २००२ मध्ये आसिफ यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अटक झाली होती. बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी त्यांना पाच वर्षांपूर्वी तुरुंगवासही घडला होता. अशा या आसिफ यांनी आता अचानकपणे अमेरिकेवर शरसंधान केले आहे. २००१ साली अमेरिकेसाठी तालिबानविरोधात जात पाकिस्तानने पुन्हा चूक केली. अमेरिका बाजूला झाला; परंतु आम्ही आतापर्यंत त्याचे परिणाम भोगत असून, त्याची भरपाई कधीही होऊ शकत नाही, असे उद्गार त्यांनी काढले आहेत. लष्करप्रमुख जनरल झिया-उल-हक आणि परवेझ मुशर्रफ यांच्यावरही त्यांनी हल्लाबोल केला. अफगाणिस्तानात १९८० साली जो विद्रोह झाला, तो अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर केला होता. तत्कालीन पाक सरकारने स्वतःच्या फायद्यासाठी आपल्याच लोकांना त्यात सहभागी करून गंभीर चूक केली, असे आसिफ यांचे मत आहे. थोडक्यात, अमेरिकेने पाकिस्तानचा केवळ टॉयलेट पेपरसारखा वापर करून फेकून दिले. अफगाणिस्तान युद्धात आमचा वापर केला गेला आणि काम झाल्यावर सोडून दिले. तालिबानने जिहादच्या नावाखाली जेव्हा रशियाविरोधात युद्ध पुकारले, तेव्हा पाक युद्धात उतरला; परंतु त्याचे कोणतेही निमित्त नव्हते. कारण, तो 'जिहाद'च नव्हता आणि रशियाने अफगाणिस्तानवर कब्जादेखील केला नव्हता, असा साक्षात्कार आसिफ यांना काही दशकांनंतर झालेला दिसतो. इतके दिवस अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा गुणगौरव करण्यात पाकिस्तान मग्न होता. ट्रम्प यांना शांततेचे नोबेल मिळावे, अशी मागणी करून पाकिस्तानने भाटगिरीची हद्द गाठली होती. लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना ट्रम्प यांनी 'व्हाईट हाऊस'मध्ये भोजनाचे आमंत्रण दिले. त्यामुळे मुनीर यांना स्वर्ग दोन बोटेच उरला होता! पाकने अमेरिकेला अफगाणिस्तान युद्धावेळी आपले हवाई क्षेत्र खुले केले. बंदरे आणि लष्करी तळांचा वापर करू दिला. हवाई इंधनभरतीची सोय करून दिली. परंतु, तरीही अमेरिका फक्त स्वतःच्या भल्याचा विचार करतो, अशी उपरती पाकिस्तानला झालेली दिसते. ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गेल्या महिन्यात इराणला मोठा धक्का दिला. इराणला अमेरिका शत्रुस्थानी मानतो आणि ट्रम्प इराणला अण्वस्त्र केंद्रांवरून धमक्याही देत आहेत. पाकिस्तानने इराणबरोबरची गेल्या अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेली रहदारी प्रणाली बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बलुचिस्तान आणि इराणच्या सीमावर्ती भागात राहणारे लोक कौटुंबिक संबंध, व्यापार आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक कागदपत्रांचा वापर करून सीमा ओलांडत असत. परंतु, आता ही पद्धत रद्द केल्यामुळे या भागातील लोकांना पासपोर्ट व व्हिसाशिवाय सीमा पार करता येणार नाही. आर्थिक संकटात असलेल्या पाकिस्तानला अमेरिका आर्थिक व शस्त्रास्त्रांची मदत करते. 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान युद्धबंदी करारात निर्णायक भूमिका असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. मात्र, भारताने हा दावा साफ फेटाळून लावला. त्यामुळे ट्रम्प नाराज झाले होते. या काळात अमेरिका व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध मजबूत झाले. रशियाकडून तेलखरेदीमुळे अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के शुल्क लादले. पाकिस्तानवरील शुल्क मात्र १९ टक्क्यांवर आणले होते. तेव्हा पाकिस्तान खूश झाला होता. भारतावर जास्त शुल्क लादल्याने त्याला उकळ्या फुटल्या होत्या. परंतु, आता भारत-अमेरिका व्यापार करारास अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले असून, भारतावरील शुल्क अमेरिकेने १८ टक्क्यांवर आणल्यामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत भारताची भूमिका अधिक भक्कम होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानचे माथे भडकले आहे. शिवाय, पाकिस्तानने अमेरिकेसोबत व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करार केलेला नाही.

मुळात पाकिस्तानने भारतविरोधी कारवायांसाठी १९७० ते २००० या काळात अमेरिकेची मदत घेतली होती. परंतु, आता जागतिक तसेच दक्षिण आशियातील समीकरणे बदलली असून, भारत हा जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने प्रवास करत आहे. भारताच्या विशाल बाजारपेठेचे अमेरिकेला आकर्षण आहे. भारतातील कुशल तंत्रज्ञ अमेरिकेला हवे आहेत. भारताबरोबर व्यापारात दोन्ही देशांचा फायदा आहे, हे ट्रम्प जाणतात. उलट पाकिस्तान हा आर्थिकदृष्ट्या मोडकळीस आलेला देश आहे. पाकिस्तानात कारखानदारी क्षेत्र फारसे नाही. तेथील मालाचा दर्जा चांगला नाही. शिवाय, पाकिस्तान हा सातत्याने चीनची तळी उचलत असल्याचे अमेरिकेला ठाऊक आहे. तैवानच्या मुद्द्यावरून अमेरिका व चीनचे संबंध चांगले नाहीत. चीनचा मित्र असलेला उत्तर कोरिया अमेरिकेच्या जवळचा देश नाही आणि एकेकाळी उत्तर कोरियाला पाकने अण्वस्त्र तंत्रज्ञान पुरवले होते, हे अमेरिकेला ठाऊक आहे. मुळात पाकिस्तान हा दहशतवादी व दिवाळखोर देश असून, दहशतवादी कारवायांमुळे तो स्वतःच ग्रस्त झालेला आहे. अफगाणी तालिबान्यांपासून वाचवण्यासाठी अमेरिकेने मदत करावी ही पाकची इच्छा असून, तीही पूर्ण होत नाही. अफगाणिस्तानातील रशियाविरोधी युद्धात पाकिस्तानी मुजाहिदीनांबरोबरच ओसामा बिन लादेनही सहभागी झाला होता. या लादेनला नंतर पाकिस्ताननेच आश्रय दिला होता. लादेनने 'अल कायदा'मार्फत अमेरिकेवर हल्ला केला होता आणि अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून लादेनचा खात्मा केला होता. लादेनसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याला आसरा देणारा पाकिस्तान हा काय लायकीचा देश आहे, हे सर्व जगाला ठाऊक आहे. अमेरिकेला पाकिस्तानचा आता फारसा उपयोग उरलेला नाही. त्यामुळे पाकची अवस्था टॉयलेट पेपरसारखी झाली आहे, या जाणिवेमुळे ख्वाजा आसिफ यांचा भडका उडालेला दिसतो. परंतु, उशिरा झालेल्या या उपरतीमुळे पाकिस्तानला शहाणपण येईल, याची मात्र सूतराम शक्यता नाही!

लक्झरी पाण्याची भरारी

कोट्यवधी भारतीय स्वच्छ पाण्यासाठी झगडत असताना, महानगरांत प्रीमियम आणि आयात केलेल्या बाटलीबंद पाण्याचा 'लक्झरी' बाजार वेगाने वाढतो आहे. पाण्याची चव, मिनरल्स आणि ब्रँड यावर चर्चा होत असताना सामाजिक असमानतेचे वास्तव अधिक ठळक होत आहे.

रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक

देशातील मोठ्या महानगरांत इटली, फ्रान्स आणि अन्य युरोपीय देशांकडून आयात केलेल्या महागड्या पाण्याची मागणी वेगाने वाढत असून, देशात एक नवीन प्रीमियम वॉटर कल्चर विकसित होत आहे. दिल्ली, मुंबई, बंगळूर, गुरुग्राम यासारख्या निवडक शहरांत आलिशान फूड स्टोअर आणि पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये विशेष चवीचे पाणी प्राशन करण्याचे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. यात सहभागी मंडळी जगभरातील नामांकित ब्रँडचे पाणी वाईन, कॉफीप्रमाणे तपासत आहेत. पाण्यातील मिनरल कंटेंट, कार्बोनेशन, खारटपणा आणि चवीबद्दल यात गांभीर्याने चर्चा होते. सध्या ही बाब भारतातील उच्चभ्रूवर्गापुरतीच मर्यादित आहे. परंतु, आगामी काळात त्याची व्याप्ती वाढू शकते.

पाण्याची चव घेण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करणाऱ्यांपैकी एक अवंती मेहता यांनी स्वतःला भारताची सर्वात तरुण 'वॉटर सोमेलिएर' असल्याचे म्हटले आहे. 'सोमेलिएर' म्हणजे पेयतज्ज्ञ. हा शब्द वाईनतज्ज्ञांसाठी वापरला जातो आणि आता पाणी क्षेत्रातही उपयोगात आणला जात आहे. अवंती यांच्या मते, वेगवेगळ्या भौगोलिक स्थितीतून उपसलेल्या पाण्याची चव आणि पोषणमूल्य वेगळे असते. 'रॉयटर्स'च्या अहवालानुसार, या आयोजनात फ्रान्सच्या पर्वतरांगांतील पाणी सादर करणारे 'एबिया', दक्षिण फ्रान्सची 'पेरिये', इटलीची 'सॅन पेलग्रिनो', भारतातील अरावली पर्वताचे पाणी आणणारे 'आवा' मिनरल वॉटर यासारख्या ब्रँडचा समावेश होतो. अवंती यांच्या मते, प्रत्येक ठिकाणच्या पाण्याची चव वेगळी असते, हे लोकांना कळून चुकले आहे. काही ठिकाणी कॅल्शियम अधिक असते, तर काहीत मॅग्नेशियम, तर काही ठिकाणी नैसर्गिक कार्बोनेशन. योग्य प्रकारचे पाणी निवडणे हे शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकते. अवंती यांचे कुटुंबीय आवा मिनरल नावाची कंपनी चालवते आणि ते भारतातील प्रीमियम वॉटर ब्रँडस्‌मध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण करत आहे.

पाणी आता विशेषाधिकार

१.४ अब्ज लोकसंख्येच्या देशात स्वच्छ पाणी हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. संशोधकांच्या मते, देशातील सुमारे ७० टक्के भूजल कोणत्या ना कोणत्या रूपाने दूषित झाले आहे. अनेक शहर आणि वाड्यांवर नळातून येणारे पाणी पिण्याजोगे राहिलेले नाही. डिसेंबर महिन्यात इंदूरमध्ये गलिच्छ पाणी पिल्याने १६ जणांचा मृत्यू झाला. अशावेळी बाटलीबंद पाणी भारतातील काही लोकांसाठी अत्यावश्यक बाब बनली आहे. किराणा दुकानात एक लिटरची पाण्याची बाटली २० रुपयांना मिळते. हे पाणी पेप्सी, कोका कोला, बिसलरी तयार करतात. पिण्याच्या पाण्याच्या उद्योगाची उलाढाल तब्बल पाच अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. यात दरवर्षी २४ टक्क्यांनी वाढ होत असून, भारत या क्षेत्रात वेगाने विकसित होणारी बाजारपेठ आहे.

जागतिक पातळीवर बाटलीबंद पाण्याची उलाढाल ३० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे. चीन आणि अमेरिकेसारख्या देशांत होणारी मागणी ही प्रामुख्याने जीवनशैली अणि सुविधेच्या रूपातून होताना दिसते. तेथे दरवर्षी चार ते पाच टक्के वाढ नोंदली जात आहे. बाजारातील रिसर्च कंपनी 'यूरोमॉनिटर'च्या आकडेवारीनुसार, भारतात प्रीमियम वॉटरची मागणी २०२१ मध्ये केवळ एक टक्के असताना २०२५ पर्यंत ती वाढत ८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. 'युरोमॉनिटर'चे अधिकारी अमूल्य पंडित यांच्या मते, महापालिकेकडून पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्यावरचा लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. केवळ बाटलीबंद पाणीच आरोग्यासाठी उपयोगी असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. जी मंडळी नियमित बाटलीबंद पाणी खरेदी करू शकत नाहीत, ते वॉटर प्युरिफायरची मदत घेतात. मात्र, प्युरिफायरमध्ये पाणी स्वच्छ होताना त्यातील नैसर्गिक तत्त्व निघून जाते, असे निरीक्षण आहे.

स्पार्कलिंग आणि स्प्रिंग वॉटरची मागणी

भारतात स्पार्कलिंग आणि स्प्रिंग वॉटरची मागणीदेखील वाढत आहे. टाटा समूहाने अलीकडेच स्पार्कलिंग वॉटरचा प्लांट सुरू केला आणि कंपनी भविष्यात स्प्रिंग वॉटरच्या उत्पादनातदेखील येण्याची तयारी करत आहे. टाटा अधिकाऱ्यांच्या मते, त्यांच्या पाण्याच्या उद्योगाची उलाढाल दरवर्षी सुमारे ३० टक्के वाढ नोंदवू शकते. भारतात प्रीमियम वॉटर ब्रँड 'आवा' याची विक्री ही मागील वर्षी विक्रमी पातळीवर नऊ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचली होती. कंपनीच्या मते, शहरातील मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत गटातील ग्राहकांत आरोग्य आणि चवीवरून वाढलेली जागरूकता पाहता प्रीमियम वॉटरची मागणी वाढत आहे. त्याचवेळी परकी ब्रँडस्‌देखील भारताकडे मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहत आहेत.

अर्थात, या संपूर्ण ट्रेंडमागे एक कटुसत्यही दडलेले आहे. त्यात देशात कोट्यवधी नागरिक आजही सुरक्षित पाण्यापासून वंचित आहेत. हे चित्र सामाजिक असमानता दाखविणारे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पाण्यासारख्या मूलभूत गरजा केवळ बाजाराच्या भरवशावर सोडणे कितपत योग्य आहे? अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक पाणीपुरवठा प्रणाली सक्षम करण्यावर भर देण्याचा मुद्दा मांडला आहे. पाण्याची गळती थांबवून स्वच्छ आणि आरोग्यपूरक पाणी देणे आवश्यक असताना, लोकांना महागड्या पर्यायाची निवड करण्यास भाग पाडू नये, असेही मत नोंदविले.

पाण्याची चव चाखण्यासंदर्भात आयोजित कार्यक्रमात सहभागींनी काही अनुभव शेअर केले. त्यांच्या मते, पाण्याची चव वेगळी असली तरी त्याची किंमत आटोक्याबाहेरची आहे. याउलट श्रीमंतवर्गात त्याचे प्रस्थ वाढत येत. एकुणात, भारतात बाटलीबंद पाण्याची कहाणी आता केवळ तहान भागविण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या पाण्यावर आरोग्य, चव, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आर्थिक असमानतेचे थर जमा झाले आहेत.

बाटलीबंद पाण्याचा बाजार

भारतात चांगल्या गुणवत्तेच्या पाण्याचा बाजार सुमारे ४०० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो. भारताची लोकसंख्या आणि वाढते शहरीकरण पाहता हा बाजार आगामी काळात आणखी वाढू शकतो. उच्च उत्पन्न गटातील लोक पाणी हे आरोग्याबरोबरच सामाजिक प्रतिष्ठेला जोडत आहेत. भारतात सर्वात महाग आणि विशेष मिनरल असलेल्या बाटलीबंद पाण्याची किंमत एका लिटरसाठी ८० ते १०० रुपये आहे. त्याचवेळी परदेशातून आयात बाटलीची किंमत २५० ते ३०० रुपयांपर्यंत आहे. या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतानाही त्याची मागणी वाढत आहे. पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये भोजनाबरोबरच पाण्याचीदेखील विचारणा केली जात आहे, हे विशेष.

शिरसाटांचे पक्षातील वजन घटले!

एकेकाळी संभाजीनगरात 'वजनदार' मानले जाणारे संजय शिरसाट आज पक्षांतर्गत आव्हानांना सामोरे जात आहेत. मंत्रिपद आणि प्रवक्तेपदामुळे वाढलेली प्रतिमा वादग्रस्त प्रकरणे आणि निवडणूक निकालांनंतर ढासळताना दिसते. तिकीटवाटपातील मतभेद आणि महापालिका निवडणुकीतील पराभवाने त्यांच्या प्रभावातील घट अधोरेखित केली आहे.

मराठवाडा वार्तापत्र

विनोद काकडे

राजकारणात प्रतिमा उभी करायला वर्षानुवर्षे लागतात; पण ती ढासळायला एक क्षण पुरतो. शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे प्रवक्ते, राज्याचे समाजकल्याणमंत्री आणि छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यासंदर्भात सध्या अशीच चर्चा सुरू आहे. एकेकाळी पक्षात 'वजनदार' मानले जाणारे शिरसाट आज पक्षांतर्गत आव्हानांना सामोरे जाताना दिसत आहेत. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत ज्यांच्या शब्दाशिवाय संभाजीनगरात शिवसेनेचे पानही हलत नव्हते, त्या शब्दांची किंमत आज पक्षात घटल्याचे चित्र आहे. जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ यांच्या पदावरून हकालपट्टीचा विषय असो वा उपमहापौरपदासाठी उमेदवारी देताना शिरसाट यांच्या मताकडे झालेले दुर्लक्ष - या घटनांनी त्यांच्या प्रभावातील घसरण अधोरेखित केली आहे.

शिवसेनेतील फुटीनंतर आमदार संजय शिरसाट यांची राजकीय घोडदौड वेगाने सुरू झाली. मंत्रिपद, पालकमंत्रिपद आणि प्रवक्तेपद अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या शिंदे सेनेमध्ये त्यांच्या वाट्याला आल्या. टी.व्ही. स्टुडिओंमध्ये आक्रमकपणे शिंदे शिवसेना पक्षाची बाजू मांडणारा चेहरा म्हणून त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली. विरोधकांवर तिरकस टीका आणि पक्षाच्या भूमिकेचे ठाम समर्थन, यामुळे ते प्रभावी नेते म्हणून पुढे आले. मात्र, प्रवक्तेपद केवळ आक्रमक भाषणांपुरते मर्यादित नसते; ती विश्वासार्हतेची कसोटीही असते.

मुंबईतील आलिशान फ्लॅट, संभाजीनगरातील राजवाड्यासारखा बंगला, एका मोठ्या हॉटेल खरेदीतील कथित अनियमितता, औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड प्रकरण हे सर्व मुद्दे चर्चेत आले तेव्हा पक्षाची प्रतिमा बचावण्याची जबाबदारी असलेल्या शिरसाट यांच्याच बचावासाठी इतर पक्षांतील इतर नेत्यांना पुढे करावे लागले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या कथित व्हिडीओंनी जनतेमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण केले. जनतेला अपेक्षित होते विकासाचे राजकारण; मात्र चर्चेत राहिले ते व्यवहारांचे राजकारण. या प्रतिमेचा फटका शिंदे शिवसेना पक्षालाच बसला आणि तेथूनच त्यांच्या पक्षात त्यांचे वजन घटू लागल्याचे दिसले.

दरम्यान, महानगरपालिका निवडणुकीत तिकीटवाटपावरून शिंदे सेनेतील मतभेद उघडपणे समोर आले. जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ यांनी मनमानीचा आरोप करत बंडखोरीची भूमिका घेतली. सामान्यतः, अशावेळी प्रभावी नेत्याचा शब्द अंतिम मानला जातो; पण येथे चित्र उलटे होते. पक्षाने जंजाळ यांचे पद कायम ठेवलेच; शिवाय त्यांच्या १६ समर्थकांना उमेदवारी दिली. उपमहापौरपदासाठीही शिरसाट यांच्या पसंतीला डावलण्यात आले. या घटनांनी त्यांच्या घटत्या प्रभावावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

निवडणूक निकालांनीही हे चित्र अधिक स्पष्ट केले. सलग तीन दशक भगवा फडकलेल्या संभाजीनगरच्या महानगरपालिकेत शिंदे शिवसेनेला ११५ पैकी केवळ १३ जागांवर समाधान मानावे लागले आणि पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. महापालिका निवडणुकीत आपल्या दोन्ही मुलांना निवडून आणण्यासाठी शिरसाट यांनी जसा जोर लावला, तितकी ऊर्जा त्यांनी पक्षातील इतर उमेदवारांसाठी लावली असती, तर चित्र वेगळे दिसले असते, अशी चर्चा शिवसेना शिंदे गटात आहे. जिल्हा परिषदेतही त्यांच्या मतदारसंघात पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही. पालकमंत्री म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील सत्ता टिकवण्यात अपयश हे त्यांच्या नेतृत्वावर उठलेले गंभीर प्रश्नचिन्ह ठरले आहे.

राजकारणात निष्ठा महत्त्वाची असली, तरी अंतिम मोजमाप निकाल आणि जनाधार यावरच होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास संजय शिरसाट त्यांच्या पाठीशी असला, तरी पक्षाची व्यापक गरज आणि जनतेचा कौल, याकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष करणे कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नसते. शिरसाट यांच्या मताची पक्षात घटत चाललेली किंमत ही त्या वास्तवाचीच परिणती म्हणावी लागेल.

पहिला चहा

आदरणीय... सलमाननीय...

भागवतजी : सलमानजी, आप बहोत अच्छे होने के बावजूद भी एक कडवे और सच्चे इंसान है. लोग सिर्फ आपकी उतरी हुई कमीज की तारीफ और दीदार के लिये तरसते है. आज आप इस सभा मे आये, चार चाँद लग गये. बहुत अच्छा लगा.

भाईजान : कमीज उतरून बोलू का? गर्मी बहुत है. सभेला अजून वेळ आहे...

भागवतजी : (डोक्यावरून हात फिरवत) तुम्ही मराठी बोलता तर मी मराठीतूनच बोलतो. मी तारीफ केली तुमच्या कमीजची; पण कमीच केली. जास्त तारीफ तुमची केली. राहुदे कमीज अंगावरच. छान वाटते.

भाईजान : ओह! ठीक है, ठीक है. आजकाल पोरं लय स्टाईल मारतात. स्टाईलने राहतात. आपण आयकॉन आहोत आजकालच्या पिढीचे.

भागवतजी : ऐकून बरं वाटलं.

भाईजान : माझे काम दिसते ऑडियन्सना.

भागवतजी : या कार्यक्रमात बोलणारी, काम करणारी लोकं लागतात. इथे अभिनयाला थारा नाही. तरीही तुम्ही आलात. देशभक्त आहात खरे.

भाईजान : संघाची विचारशक्ती खूप आहे, असं तुमच्या बोलण्यातून फील झाला. तुम्ही 'दबंग ३' बघितला का? अभिनयाला थारा नाही तरी केला अभिनय. मी लिहिला पूर्ण चित्रपट.

भागवतजी : तुम्हीच बोलला ते बरे केले. अभिनय, लिखाण, संवाद यात वाद होता कामा नये. संघाची एकजूट, विचार आणि कार्यकारिणी यात तफावत नाही. हे शिका तुम्ही संघाकडून. यासाठी वेळात वेळ काढलात आज. खरेच खूप चांगले केलात.

भाईजान : नाही समजला तुमी काय बोलले. एक झूठ बाकी सच ऐसा कुछ था...

भागवतजी : (मनात - अरे देवा, पुन्हा हिंदी) सलमान मैने ऐसा तो नहीं बोला. मैने बोला संघकी एकता की ताकद, विचार और कार्य सब में भेदभाव नहीं है. एक जैसा है. आपके अभिनय की तरह. समझ गये?

भाईजान : हा हा हा. सब समजा. आपने मेरी तारीफ तो नहीं की थी. आपने मुझे ताणे दिये की मेरा लिखना, ॲक्टिंग और संवाद याच्यामदी वाद आहे. समजते मला मराठी. माझी आई मराठी आहे. एकजुटीवर तुम्ही मला सांगता त्यात विसंगत आहे. बराबर बोललो का विसंगत? सोडा. भिन्नभिन्न लोग राहतात दुनियेत. मी इथे आलो तुमच्यामुळे. कोणी तरी बोलले आपल्या संघाने १०० वर्षे पूर्ण केली. आपको ढेर सारी बधाई. मेरी करो बिदाई. गुड डे. शब्बा खैर..!

■ कलंदर

“

तंत्रज्ञान तटस्थ नसते; ते ज्यांच्या हाती असते, त्यांच्या हेतूंनी ते आकार घेत असते.

- नाओमी क्लाईन

काय चाललंय?

नर्गिस मोहम्मदी

चर्चेतील चेहरा

इराण हे इस्लामिक राष्ट्र आहे. तेथे इतर इस्लामिक राष्ट्रांप्रमाणे महिलांवर अनेक निर्बंध आहेत. महिलांना कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नाहीत. सरकारच्या धोरणाविरोधात महिलांनी आवाज उठविला, तर तो दाबून टाकला जातो. अशातच सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजकीय संघर्ष वाढला असताना इराणने नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या नर्गिस मोहम्मदी यांना साडेसात वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे नर्गिस मोहम्मदी पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. इराणी सरकार आणि नर्गिस यांच्यात गेल्या अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे. नर्गिस यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, या नव्या शिक्षेमुळे इराणी अधिकाऱ्यांविरुद्ध सुरू असलेली त्यांची दशकांपासूनची लढाई आणखी तीव्र झाली आहे.

५३ वर्षीय नर्गिस या एक प्रसिद्ध इराणी मानवाधिकार कार्यकर्त्या, लेखिका आणि नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या आहेत. इराणमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात, तसेच राजकीय दडपशाहीविरोधात त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे. याचमुळे त्या इराणी सत्ताधाऱ्यांच्या निशाण्यावर राहिल्या आहेत. त्यांनी सरकारविरोधी निदर्शने केली, देशाच्या विरोधात प्रचार केला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवला, असा आरोप अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे; पण नर्गिस आणि त्यांच्या समर्थकांनी हे सर्व आरोप फेटाळले असून, शांततामय आणि अहिंसक मार्गाने केलेल्या मानवाधिकार चळवळीमुळेच त्यांना शिक्षा दिली जात आहे.

नर्गिस या पेशाने अभियंता असून, त्या एक संवेदनशील लेखिकाही आहेत. त्या मानवाधिकार रक्षक केंद्राच्या (डीएचआरसी) उपाध्यक्ष आहेत. या संस्थेची स्थापना नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या शिरीन एबादी यांनी केली होती. गेल्या दहा वर्षांपैकी बहुतांश काळ नर्गिस यांनी तुरुंगात घालवला आहे. नर्गिस फाऊंडेशनच्या माहितीनुसार, २०२१ पासून त्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आरोपांखाली १३ वर्षांची शिक्षा भोगत आहेत. २०२३ मध्ये इराणमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात लढा दिल्याबद्दल आणि सर्वांसाठी मानवाधिकार व स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केल्याबद्दल त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान केला होता. त्यावेळी नर्गिस या तेहरानमधील तुरुंगात बंद असल्यामुळे हा पुरस्कार त्यांच्या मुलांनी स्वीकारला होता.

१२ डिसेंबर २०२५ रोजी मशहद येथे मानवाधिकार वकील खोसरो अलीकोर्डी यांच्या स्मरणार्थ झालेल्या शोकसभेला उपस्थित राहिल्यामुळे नर्गिस यांना अटक केली. त्यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण करणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या घोषणा देणे आणि सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचे आरोप ठेवले. नर्गिस यांना आतापर्यंत १३ वेळा अटक झाली असून, ५ वेळा दोषी ठरवले गेले आहे. इराणमधील मानवाधिकार परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारा आवाज दाबण्यासाठीच त्यांच्यावर वारंवार खटले दाखल केले जात असल्याचे त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. नर्गिस सध्या केवळ एक व्यक्ती नसून, इराणमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, महिलांचे हक्क आणि मानवी सन्मानासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाचे प्रतीक बनल्या आहेत.

- युवराज इंगवले

तांबे उत्पादनात चिली अव्वल

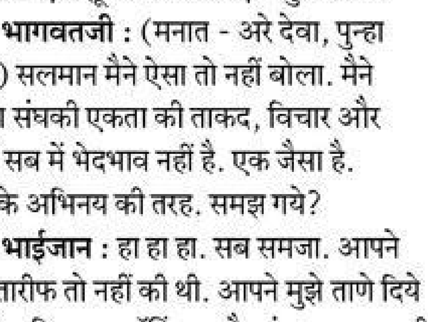

तांबे हा धातू वीजजाळे, इलेक्ट्रिक वाहने आणि नवीकरणीय ऊर्जा यासाठी अत्यावश्यक असल्याने त्याचे धोरणात्मक महत्त्व वाढले आहे. जगात दक्षिण अमेरिकेतील चिली हा देश तांबे उत्पादनात अव्वलस्थानी आहे. तिथे २०२४ मध्ये ५.३ दशलक्ष टन उत्पादन झाले आहे. दुसरीकडे, चीनचे देशांतर्गत उत्पादन तिप्पटपेक्षा अधिक वाढले आहे. सन २०२४ मधील आकडेवारीनुसार, टॉप 10 तांबे उत्पादक देशांविषयी...

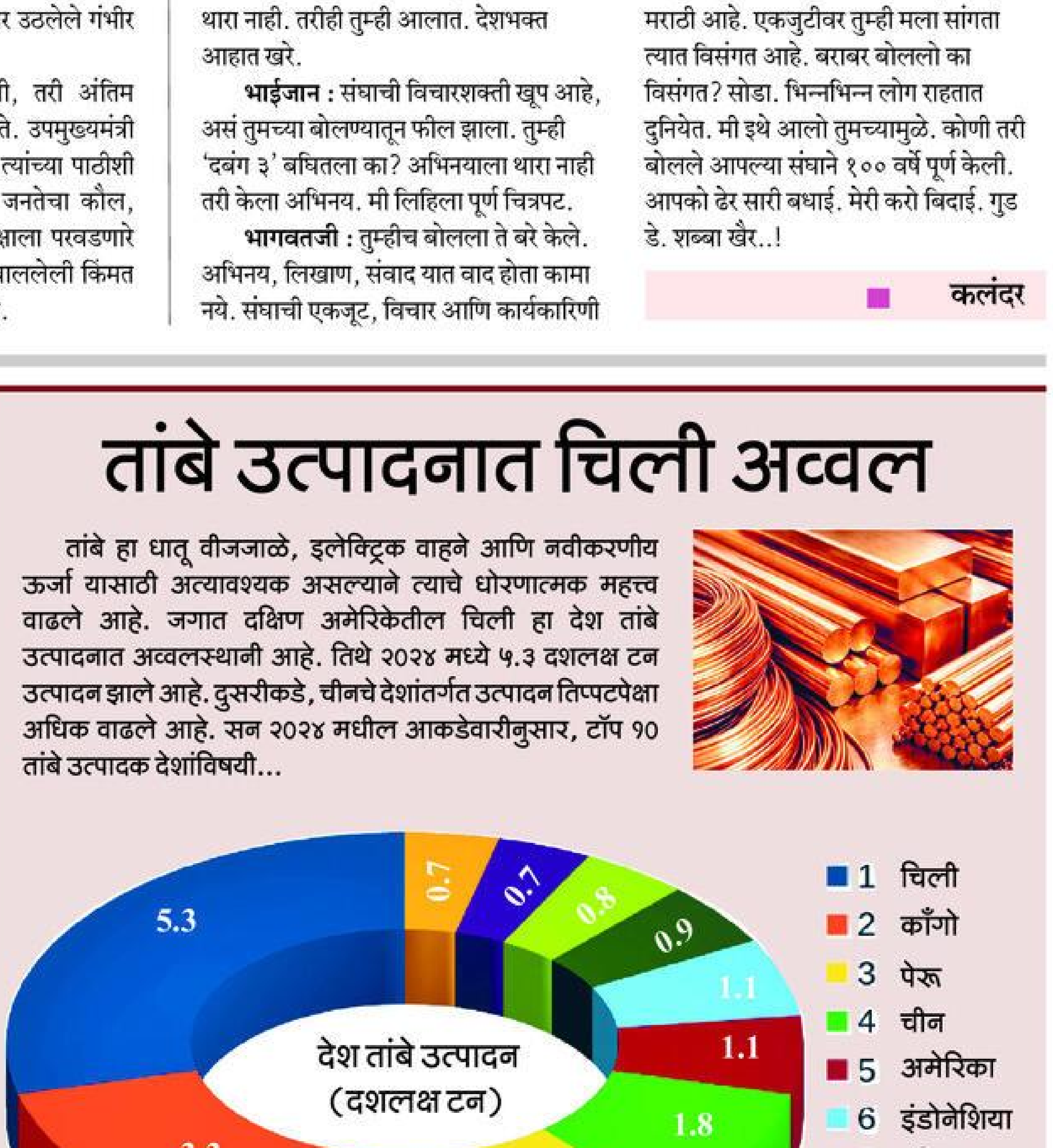

इन्फो वेध

(स्रोत : यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे)

पुढारी® This is Trade mark of Pudhari Publication Pvt. Ltd.

* R. N. I. No. MAHMAR/2009/28047 * — For Pudhari Publication Pvt. Ltd. * Founder Editor Late G. G. Jadhav * Chief Editor Dr. Pratapsinh G. Jadhav * Group Editor, Printer & Publisher - Dr. Yogesh Pratapsinh Jadhav, Printed at - 1) Pudhari Publications Pvt, Ltd., Pudhari Sankul, Plot no. 29 to 32 , 36 & 37, Sector 30, Vashi, Navi Mumbai, Dist - Thane, State - Maharashtra. Phone: 022-62729999. 2) Dangat Media Pvt. Ltd, Plot No. 22, Digha M.I.D.C., the of TTC Industrial Area, Vishnu Nagar, Digha, Navi Mumbai - 400708, State - Maharashtra. Published at - Pudhari Bhavan,26/28, Dr.M.B.Velkar Street, Kalabadevi , Mumbai-400 002 Dist. Mumbai, State-Maharashtra. Phone: 022-22097200 (Note : As per PRB Act, the Editorial responsibility on the Executive Editor Vivek Girdhari only)

कंधार (जि. नांदेड) : श्री शिवाजी कॉलेज केंद्रावर पायाने बारावीचा पेपर लिहिताना दिव्यांग सूरज उबाळे.

दोन्ही हात नसतानाही सूरजने पायाने लिहिला बारावीचा पेपर

नांदेड जिल्ह्यातील नवरंगपुरा येथील श्री शिवाजी कॉलेज केंद्रावर जिद्द अन् चिकाटीचे मूर्तिमंत रूप!

कंधार (जि. नांदेड) : भागवत गोरे

'मनगटात बळ नाही, म्हणून काय झाले, पंखात भरारी घेण्याची जिद्द अजूनही कायम आहे,' याचीच प्रचिती कंधार तालुक्यातील शिवाजी कॉलेज नवरंगपुरा येथे पाहायला मिळाली. बारावी परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी जन्मतः दोन्ही हात नसलेल्या सूरज शिवराज उबाळे या दिव्यांग विद्यार्थ्याने चक्क पायाने इंग्रजीचा पेपर लिहून उपस्थित सर्वांची मने जिंकली.

राज्यभरात बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात झाली आहे. परीक्षेचा पहिलाच दिवस आणि कठीण समजला जाणारा इंग्रजीचा विषय. अनेक धडधाकट विद्यार्थी दडपणाखाली असताना कंधार शहरातील नवरंगपुरा येथील श्री शिवाजी कॉलेज केंद्रावर जिद्द अन् चिकाटीचे मूर्तिमंत रूप पाहायला मिळाले. या विद्यार्थ्याला निसर्गाने दोन्ही हात दिले नाहीत; पण त्याने या उणिवेला कधीही आपले अपयश मानले नाही.

पायांच्या बोटांत धरली लेखणी

वर्गातील इतर विद्यार्थी बाकावर बसून हातानी पेपर लिहीत असताना, सूरज मात्र बाकावर बसून मोठ्या एकाग्रतेने आपल्या पायाच्या अंगठ्यात पेन धरून शब्दांमागून शब्द कागदावर उतरवत होता. त्याच्या चेहऱ्यावरील आत्मविश्वास आणि लिहिण्याचा वेग पाहून परीक्षा केंद्रावरील पर्यवेक्षक, नायब तहसीलदार उर्मिला कुलकर्णी, केंद्र संचालक अशोक वरपडे, प्राचार्य मुरलीधर घोरबांड, आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी थक्क झाले.

परभणीत उबाठाचा मुस्लिम महापौर, काँग्रेसचा हिंदू उपमहापौर

व्हिप, बैठक अन् गणित जुळले; शिवसेनेवर हिंदुत्वाला मूठमाती दिल्याचा भाजपचा आरोप

परभणी : महापालिकेच्या महापौरपदी उद्धव सेनेचे (उबाठा) सय्यद इक्बाल यांची, तर उपमहापौरपदी काँग्रेसच्या गणेश देशमुख यांची निवड झाली. यानंतर परभणीत शिवसेना-काँग्रेस आघाडीकडून जल्लोष सुरू आहे. रस्त्यावर भगवा आणि हिरवा गुलाल, फटाके फोडून आनंद साजरा केला जात असतानाच भाजपने मात्र पुन्हा शिवसेनेवर हिंदुत्वाला मूठमाती दिल्याचा आरोप केला आहे.

सय्यद इक्बाल

गणेश देशमुख

खासदार संजय जाधव, आमदार राहुल पाटील हे हिंदुत्ववादी मतांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडून येत आहेत. शिवसेनेच्या हिंदुत्वाला पसंती देत याच परभणीकरांनी पक्षाला मान्यता आणि चिन्ह मिळवून दिले होते. मात्र, याच परभणीत सत्तेसाठी उद्धव ठाकरेंच्या सेनेने मुस्लिम महापौर करत आम्हाला हिंदुत्वाशी काही देणेघेणे नाही हे कृतीतून दाखवून दिले आहे. भविष्यात परभणीतील हिंदुत्ववादी जनता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षासोबत कधीही जाणार नाही. परभणीत मुस्लिम महापौराची निवड करून उबाठा गटाने पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय की त्यांची शिवसेना आता जनाब सेना झाली आहे. सत्तेसाठी भगवा सोडून हिरवा हाती घेतला, बाळासाहेबांच्या विचारांना मूठमाती दिली, असा आरोप भाजपने केला आहे.

चंद्रपूरचे पडसाद परभणीत...

परभणी महापालिकेत उद्धव सेनेचे २५, तर काँग्रेसचे १२ नगरसेवक निवडून आले होते. बहुमतासह आघाडीने सत्ता मिळवल्यानंतर प्रत्यक्षात महापौर, उपमहापौर पदासाठीची निवडणूक झाली. चंद्रपूर महापालिकेत उद्धव सेनेच्या नगरसेवकांनी भाजपला पाठिंबा देण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला. या जोरावर तिथे भाजपने आपला महापौर केला. याचे पडसाद परभणी महापौरपदाच्या निवडणुकीत उमटेल, असा दावा केला जात होता.

स्वयंसेवी संस्थांच्या भागीदारीतून राज्याचे होणार वेगाने परिवर्तन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; टाटा ट्रस्टसोबत १२ करार

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

महाराष्ट्र विविध क्षेत्रांसह देशाच्या प्रगतीमध्ये वेगळा ठसा उमटवीत आहे. राज्याच्या प्रगतीचा वेग असाच कायम ठेवून राज्य शासनाच्या विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या भागीदारीतून महाराष्ट्राचे वेगाने परिवर्तन होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे टाटा ट्रस्ट व नाम फाऊंडेशन सोबत करण्यात आलेल्या करारावेळी व्यक्त केला. टाटा ट्रस्ट व नाम फाऊंडेशन सोबत झालेल्या करारामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील विकास संपूर्ण महाराष्ट्रभर पोहोचविणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रसंगी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे, तसेच नाम फाऊंडेशनचे संस्थापक नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक कुटुंबासाठी आरोग्य, पोषण, पाणी सुरक्षा आणि उपजीविका सुधारणे याला शासनाचे प्राधान्य आहे. या भागीदारीमुळे विविध कल्याणकारी शासकीय योजना अधिक लोकोपयोगी होण्यास मदत होणार आहे. शासनाच्या योजना लोक चळवळीच्या स्वरूपात पुढे येत आहेत. टाटा ट्रस्टचे सहकार्याने विविध विभागांच्या माध्यमातून सकारात्मक प्रभाव पाडण्यात यशस्वी होऊ. समाजातील सर्व घटकात उत्पन्न वाढून जगण्याचा स्तर उंचावण्यास यामुळे निश्चितच मदत होईल.

कार्यक्रमांमध्ये सुसूत्रता आणणार : नोएल टाटा

टाटा ट्रस्टसचे अध्यक्ष नोएल टाटा म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाशी भागीदारी करून आरोग्य, शिक्षण, पोषण, उपजीविका, पाणी आणि स्वच्छता कार्यक्रमांमध्ये सुसूत्रता आणणार आहे. सर्व सामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. शासनाचे विविध विभाग आणि समुदायांसोबत सकारात्मक परिणाम आणण्याचा हेतू असणार आहे. शासन व टाटा ट्रस्ट्स् यांनी गुरुवारी (दि. १२) राज्याच्या एकात्मिक विकासाला पाठबळ देण्यासाठी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करून धोरणात्मक भागीदारी अधिकृत केली आहे. नाम फाऊंडेशनचे नाना पाटेकर यांनीही शासनासोबत जलसंधारण क्षेत्रात काम करण्यास मदत मिळत असल्याबाबत समाधान व्यक्त केले.

मुंबई : करारावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोएल टाटा, संजय राठोड, नाना पाटेकर आदी.

सामंजस्य करारांची व्याप्ती

1. माता, नवजात बालक, बालक व किशोरवयीन मुलांसाठी आरोग्य सेवा बळकट करणे
2. टेलिमेडिसिनसह इतर माध्यमांतून उपचार सहज देणे, शहरी व दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य सेवा
3. एकात्मिक आपत्कालीन व्यवस्थापन सेवाद्वारे उत्तम आपत्कालीन प्रतिसादास पाठबळ देणे.
4. दोन वर्षांखालील मुलांमधील खुंटलेली वाढ, कमी वजन आणि कुपोषण रोखण्यास मदत करणे
5. गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून 'टेक-होम रेशन' सारख्या योजनांचे वितरण
6. तलावांचे पुनरुज्जीवन, जलकुंभ आणि नद्यांमधील गाळ काढणे, भूजल पुनर्भरण सुधारणे
7. मराठवाडा-विदर्भासह पाणीटंचाईग्रस्त भागांवर भर देऊन मृद व जलसंधारण योजनांची अंमलबजावणी

असे आहेत करार

टाटा ट्रस्टच्या सोबतच्या करारात ग्रामविकास, जलसंधारण, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, गडचिरोली जिल्हा प्रशासन, मुख्यमंत्री सहायता निधी, नागपूर येथील राष्ट्रीय कर्करोग संस्था, अ. भा. आयुर्विज्ञान संस्था, मध्य भारत आयुर्विज्ञान संस्था, केअर हॉस्पिटल, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, मिदास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा समावेश आहे. तसेच नाम फाऊंडेशनचा जलसंधारण विभागासोबत करार करण्यात आला आहे.

देवदर्शनाला निघालेल्या ४ मित्रांचा अपघाती मृत्यू

परभणी जिल्ह्यातील जिंतूरची घटना; कारचा चक्काचूर

परभणी : पुढारी वृत्तसेवा

देवदर्शनासाठी उज्जैनला जाणाऱ्या पाच जिवलग मित्रांच्या कारला जिंतूरजवळ भीषण अपघात झाला. बुधवारी (दि. ११) मध्यरात्री १२.१५ वाजण्याच्या सुमारास भरधाव कार अकोली पुलाच्या कठड्यावर आदळून झालेल्या या अपघातात गंगाखेड येथील चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी आहे. अपघातानंतर कारचा चालक घटनास्थळावरून पसार झाला आहे.

रोहन संजय राठोड (वय २७), कृष्णा गुट्टे (२८), बालाजी आश्रोबा आवटे (२१), बालाप्रसाद उत्तमराव घोरपडे (३०) अशी मृत तरुणांची नावे आहेत. तर गोपाळ गणेश रोकडे (२५) हा गंभीर आहे. सर्व जण कारने उज्जैन येथे महाकालच्या दर्शनासाठी निघाले होते. बुधवारी मध्यरात्री जिंतूर शहरापासून अवघ्या ४ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अकोली पुलाजवळ त्यांची कार आली असता,

चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. सुसाट वेगात असलेली कार पुलाच्या कठड्यावर जाऊन जोरात धडकली. ही धडक इतकी भीषण होती की, गाडीच्या समोरील भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला.

घटनास्थळी रक्ताचा सडा

अपघाताचा आवाज ऐकून स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. जखमींना गाडीतून बाहेर काढून जिंतूरच्या ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती चार तरुणांना मृत घोषित केले. तर गंभीर जखमी असलेल्या गोपाळ गणेश रोकडे (२५) याला प्राथमिक उपचारानंतर परभणी जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे.

भगतसिंग असते तर कोश्यारींना चोपले असते

कोश्यारींच्या वक्तव्यावर संदीप देशपांडे आक्रमक

मुंबई : माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नाशिकमधील कार्यक्रमात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. राज ठाकरे हे नरेंद्र मोदी यांना जास्त घाबरतात, असा दावा कोश्यारींनी केला होता. या विधानानंतर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना कोश्यारींच्या वक्तव्याचा कठोर शब्दांत समाचार घेतला. देशपांडे म्हणाले, आज भगतसिंग असते तर त्या कोश्यारींना खूप चोपला असता. कोश्यारींनी आपले नाव बदलावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. राज ठाकरे यांनी संघाच्या कार्यक्रमात सेलिब्रिटी संदर्भात भाष्य केले होते. त्याला प्रत्युत्तर देताना कोश्यारींनी राज ठाकरे यांच्यावर टीका केली होती. त्याचाच संदर्भ घेत देशपांडेंनी कोश्यारींवर हल्लाबोल केला. कोश्यारींच्या विधानामुळे मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरल्याचेही त्यांनी सूचित केले.

पुढारी इन्फोग्राफिक्स

एसटीत 24 हजारांहून अधिक पदे रिक्त

सोलापूर : आमसिद्ध व्हनकोरे

सार्वजनिक वाहतूक संस्था असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळात वाहकांसह सहाय्यकांची पदे रिक्त आहेत. महामंडळातील रिक्त पदांची संख्या ही चोवीस हजारांहून अधिक आहे. रिक्त असलेल्या चालक, वाहक, सहायक आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याच्या हालचाली महामंडळाकडून सुरू असल्या तरी रिक्त पदांमुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामांचा ताण पडत आहे. तर, प्रवाशांनाही याची झळ बसत आहे.

उत्पन्न वाढीवरही होतोय परिणाम

बस सेवा वेळेत मिळत नसल्याने प्रवाशांमध्ये कायमच एसटीबद्दल असमाधानकारक प्रतिक्रिया उमटतात. त्याचा तिजोरीतील उत्पन्न वाढीवरही परिणाम होताना दिसत आहे. चालक, वाहकांसह सहायकांच्या रिक्त पदांवर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या हालचाली सुरू असून, १७ हजार ४५० चालक व सहायक पदावर कंत्राटी पद्धतीने भरती झाली तरी पूर्ण क्षमतेने बसेस धावणार नाहीत. चालक व वाहकांची वीस हजार, सहायकची चार हजार इतकी पदे रिक्त आहेत.

- बसेसच्या फेऱ्या रद्द व काही वेळा बसेस अवेळी धावतात
- चालक व वाहक कमी असल्याने वेळेवर बसेस मिळत नाहीत.
- कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण
- कर्मचाऱ्याला अधिक कामे करावी लागत असल्याने येणाऱ्या थकव्याने अपघात
- अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे बसेसच्या देखभालीवर परिणाम होतो
- बससेवेची गुणवत्ता घसरली
- मनुष्यबळ कमी असल्याने बसेसची देखभाल व दुरुस्ती वेळेत होत नाही
- उशिरा व अवेळी बसेस धावत असल्याने प्रवासी खासगी वाहतुकीकडे वाढले

सह्याद्रीत व्याघ्र संवर्धनाला गती

चांदोलीत सेनापतीच्या राज्यात चंदा, तर कोयनेतील 'बाजी'च्या राज्यात 'हिरकणी'चा प्रवेश

वारणावती (जि. सांगली) : आष्पाक आत्तार

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात चंदा, तारापाठोपाठ नुकतंच 'हिरकणी' या वाघिणीचं आगमन झालं आहे. त्यामुळे सह्याद्री व्याघ्र संवर्धनाला आणखी बळ मिळाले आहे. नागपूरच्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून -०६ या वाघिणीचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात नुकतेच यशस्वी स्थानांतरण करण्यात आले आहे. पेंचमध्ये 'लाडो' या नावाने ओळखली जाणारी ही वाघीण आता सह्याद्रीत 'हिरकणी' या नावाने ओळखली जात आहे. सात तारखेला सकाळी हिरकणीला कोयना अभयारण्यात निसर्गात मुक्त करण्यात आले.

चार ते पाच वर्षांची ही वाघीण पाच तारखेला सायंकाळी पेंच व्याघ्र प्रकल्पात पकडण्यात आली होती. त्यानंतर नियोजित प्रक्रियेनुसार सात तारखेला सकाळी कोयना अभयारण्यात तिला थेट जंगलात सोडण्यात आले. कोयनेच्या शिवसागर जलाशयातून बोटीने तब्बल साडेचार किलोमीटरचा प्रवास करून हिरकणीला जंगलाच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. या पद्धतीला 'हार्ड रिलीज' असे म्हणतात. या प्रक्रियेत स्थानांतरित प्राण्याला वेगळ्या विलगीकरण कक्षात न ठेवता थेट नैसर्गिक अधिवासात सोडले जाते. यापूर्वी चंदा आणि तारा या दोन्ही वाघिणींना मात्र विलग्नवासात ठेवण्यात आले होते. काही दिवसानंतर त्यांना रिलीज करण्यात आले. पेंच व्याघ्र प्रकल्पात हिरकणीला यापूर्वी एकदा पिले झाली असून, त्यामुळे ती पूर्णतः प्रजननक्षम आहे. गेल्या वर्षभरापासून कोयना खोऱ्यात अधिवास असलेल्या 'बाजी' या नर वाघाच्या हद्दीत तिला सोडण्यात आल्याने हिरकणीच्या रूपाने बाजीला जोडीदार मिळणार आहे. बाजीने आपले हद्दक्षेत्र भैरवगड, बाली-मालदीवपर्यंत निश्चित केले आहे. पाच वर्षांचा बाजी आकाराने भक्कम असून, त्याच्या पाऊलखुणांचा आकार १४ सेंटिमीटर, म्हणजेच माणसाच्या हाताच्या पंजाएवढा आहे. त्याची लांबी सुमारे आठ फूट, तर उंची तीन फूट असल्याने त्याच्या ताकदीचा अंदाज येतो. व्याघ्रस्थानांतरण प्रकल्पांतर्गत पेंच आणि ताडोबा येथून चंदा, तारा आणि हिरकणी या तीन वाघिणींना सह्याद्रीत आणण्यात आले आहे. सह्याद्रीत यापूर्वी सेनापती, सुभेदार आणि बाजी यांचे अस्तित्व सिद्ध झाले आहे. आता सह्याद्रीत तीन नर आणि तीन मादी अशा सहा वाघांचा वावर आहे. ताडोबातून नुकत्याच सह्याद्रीत स्थानांतरित केलेल्या चंदा आणि तारा या वाघिणींनी चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाच्या कोअर क्षेत्रात आपला जम बसवला आहे. चंदासोबत सेनापती हा नर वावरत असून, त्यांचे मिलन झाल्याचेही वन्यजीव विभागाने जाहीर केले आहे. दुसरीकडे धरणापलीकडील वनक्षेत्रात ताराचा अधिवास आहे. त्यामुळे सुभेदार या वाघासंदर्भातही स्वतंत्र बातमी मिळेल, अशी आशा वन्यजीव विभागाने वर्तवली आहे.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये आलेल्या तीन वाघिणींमुळे पर्यटनाची वृद्धी होत आहे. होम स्टेची संख्या वाढत आहे. एकंदर सर्व भागाचा हा आर्थिकदृष्ट्या विकास होत आहे. सह्याद्रीमध्ये तीन वाघ होते, त्यांच्या जोडीलाच आता तीन मादी वाघ आलेले आहेत. यामुळे सह्याद्रीमध्ये प्रजनन होऊन वाघांची संख्या वाढेल आणि पर्यटकांना लवकरच जिप्सीच्या टूरमध्ये वाघाचं दर्शन अनुभवायला मिळेल.

- तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प

संक्षिप्त

राज्य शासनाकडून थकीत कर्ज रकमेची माहिती भरण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत

छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेला वेग दिला जात असून सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची माहिती १५ फेब्रुवारीपर्यंत भरावी, अशा सूचना सर्व राष्ट्रीय व अग्रणी बँकांना दिल्या आहेत. ३० जून २०२५ या तारखेला गृहीत धरून कर्जमाफीच्या हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कर्जमाफी होणार असल्याने शेती कर्ज भरण्यास कोणी पुढाकार घेत नव्हते. साधारणत: ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत शेती कर्ज थकीत असले तरी त्यातील थकीत पीक कर्जाचा आकडा तातडीने सांगता येणार नाही, असे बँक अधिकारी सांगतात.

ज्योतिषाकडून ७२ लाखांचा चुना; शेअर मार्केटमधून मोठ्या परताव्याचे आमिष

नाशिक : शेअर ट्रेडिंगमध्ये भरघोस परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत नाशिकमधील एका ज्योतिषाने गुंतवणूकदाराला तब्बल ७२ लाख रुपयांना गंडा घातला आहे. शरणपूर रोड परिसरात 'अंजनिय ज्योतिष केंद्र' चालवणाऱ्या सचिन देशमुख याच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नाशिक सायबर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. शेअर मार्केटमध्ये योग्य वेळी गुंतवणूक केल्यास मोठा नफा निश्चित मिळतो, असे सांगत ज्योतिषाने गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले.

पुण्यात लॉन्ड्री व्यावसायिकाची एक कोटी १५ लाख रुपयांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने एका लॉन्ड्री व्यावसायिकाची सायबर चोरट्यांनी एक कोटी १५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. गेल्या वर्षी सानिया गोखले असे नाव सांगणाऱ्या महिलेने त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क केला. शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष दाखविले.

राज्यात ९०० दिव्यांग संस्थांची नोंदणी रद्द!

दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचा झटका

नवी मुंबई : राजेंद्र पाटील

राज्यात साधारणत: २ हजारांहून अधिक संस्था दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत होत्या. मात्र यापैकी सुमारे ९०० संस्थांची नोंदणी विविध कारणांमुळे रद्द केली आहे. विशेष म्हणजे सन २०२५ या वर्षातच ३६३ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दै.पुढारीशी बोलताना दिली.

राज्यात दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्क, सक्षमीकरण आणि पुनर्वसनासाठी कार्यरत असलेल्या सर्व संस्थांसाठी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ५० अन्वये आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्याकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. संस्था सोसायटी नोंदणी कायदा,१८६०; बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा,१९५० किंवा कंपनी कायदा (कलम ८) अंतर्गत नोंदणीकृत असल्यानंतरसुद्धा , दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ५० अंतर्गत नोंदणी अनिवार्य आहे. त्यामुळे शासनाचा निधी योग्य संस्थांवर खर्च होईल. ज्या संस्था दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत आहेत किंवा कार्य करू इच्छितात. त्यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा सर्व संस्थानी २८ फेब्रुवारी अखेरपर्यंत संकेतस्थळावर नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न केल्यास संबंधित संस्थांवर अधिनियमातील कलम ९१नुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

संस्थानी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी केल्यामुळे त्यांच्यामार्फत दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व पुनर्वसन करणे शक्य होईल. हे कार्य करताना दिव्यांगांच्या हक्कांचे, अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही व त्यांना न्याय दिला जाईल याबाबतीत दक्षता घेतली जाईल.त्यामुळे सर्व संस्थानी नोंदणी करून , दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार त्याअंतर्गतची नियमावली व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या योजना व धोरणानुसार कार्य करणे अपेक्षित आहे जेणेकरून दिव्यांगांचे पुनर्वसन व सक्षमीकरण साध्य करणे शक्य होईल, असेही मुंढे यांनी सांगितले.

"दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व नागरी समाज संघटनांच्या, संस्थांच्या कामकाजात एकसमानता येण्यासाठी तसेच त्यांची जबाबदारी आणि सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, नागरी समाज संघटनांची, संस्थांची नोंदणी, तपासणी, देखरेख, नूतनीकरण, जबाबदारी व पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी कार्यप्रणाली दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार संस्थांनी शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सुगम्यता तत्त्वे व इतर मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

-श्री. तुकाराम मुंढे सचिव दिव्यांग विभाग

हर कोई अलग सोच रखना चाहता है, लेकिन अकेले खड़ा होना नहीं चाहता। सफल निवेशक बनने के लिए आपको निवेश शैली अपने व्यक्तित्व के अनुसार बनानी होगी।

माइकल बरी, अमरीकी हेज फंड मैनेजर

पत्रिका फाइनेंस

@बिजनेस & वेल्थ

इन्वेस्टमेंट मीटर... *दुनिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड का इन कंपनियों में सबसे ज्यादा निवेश*

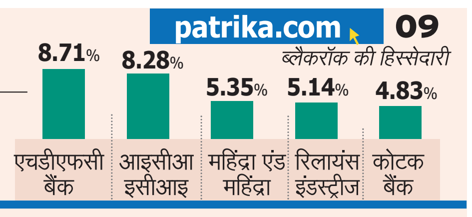

परेशानी खुदरा महंगाई 2.75% बढ़ 8 माह के उच्चतम स्तर पर, सरकार ने महंगाई मापने का पैमाना 'बेस ईयर' बदला

खाने-पीने की चीजों के दाम 6 महीने में पहली बार बढ़े

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. महंगाई फिर से सिर उठा रही है। जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई बढ़ने को लेकर 8 माह के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से सीपीआइ की नई सीरीज के आधार पर तैयार पहली रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में महंगाई दर बढ़कर 2.75% हो गई, जो दिसंबर में 1.33 बढ़ी थी। नए आंकड़े में 2024 को आधार वर्ष माना है। ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई 2.73% और शहरी इलाकों में 2.77% रही। नई सीरीज के तहत खुदरा खाद्य महंगाई 2.13% पर पहुंच गया। 6 महीने में पहली बार देश में खाने-पीने की चीजों की महंगाई निगेटिव से पॉजिटिव जोन में आई है, यानी बढ़ी है। टमाटर की महंगाई 64.8% तक पहुंच गई।

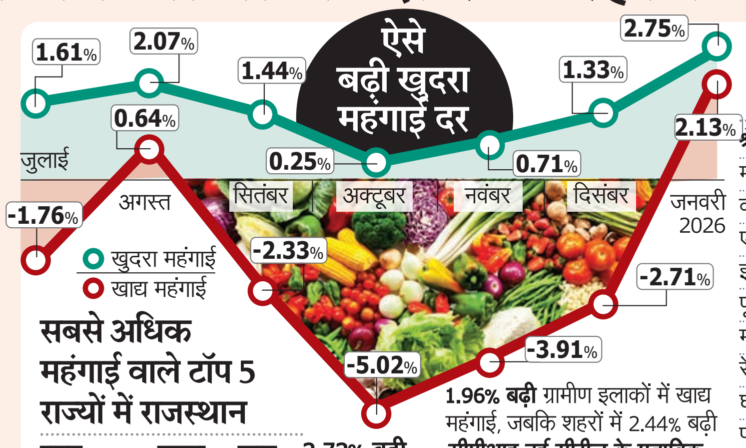

सबसे अधिक महंगाई वाले टॉप 5 राज्यों में राजस्थान

राज्य	खुदरा	खाद्य
तेलंगाना	4.92%	2.74%
केरल	3.67%	7.21%
तमिलनाडु	3.36%	2.33%
राजस्थान	3.17%	1.95%
कर्नाटक	2.99%	2.52%

2.72% बढ़ी मध्यप्रदेश में खुदरा महंगाई, छत्तीसगढ़ में 1.67% बढ़ी, राष्ट्रीय औसत से कम महंगाई

1.96% बढ़ी ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई, जबकि शहरों में 2.44% बढ़ी *सीपीआइ नई सीरीज के मुताबिक*

एक साल में जेब पर बढ़ा बोझ

श्रेणी	महंगाई बढ़ी
मकान-बिजली-ईंधन	1.53%
कपड़े-फुटवियर	2.98%
एजुकेशन	3.35%
इलाज	2.19%
फूड-बेवरेज	2.11%
मनोरंजन-खेल	2.32%
रेस्टोरेंट का खाना	2.87%
घरेलू सामान	1.45%
पर्सनल केयर	19.02%

इनकी कीमतें सबसे ज्यादा घटी सालाना आधार पर

उत्पाद	गिरावट
लहसुन	-53.07%
प्याज	-29.27%
आलू	-28.98%
अरहर	-24.90%
मटर	-15.57%

नए बास्केट में क्या खास?

नई सीपीआइ टोकरी में चीजों का वेटेज लोगों के खर्च करने के तरीकों में आए बदलावों को दिखाता है। अब कंजंप्शन बास्केट के खाने-पीने की चीजों में चावल और गेहूं जैसे अनाज का हिस्सा कम हो गया है। अब ये पहले के मुकाबले आधी रह गई है। वहीं, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मछली और मांस जैसी चीजों पर खर्च काफी बढ़ा है। नई सीरीज में खाने-पीने की चीजों के वेटेज घटा है। पहले खाने-पीने की चीजों का वेटेज 45.9% था, जो घटकर 36.75% रह गया है। फूड का वेटेज 39.1% से घटकर 34.77% हो गया है।

पीयूष गोयल बोले... भारतीय कपड़ों पर लग सकता है जीरो टैरिफ

भारत-यूएस ट्रेड डील से $90 अरब के पार जा सकता है देश का ट्रेड सरप्लस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारत-अमरीका ट्रेड डील निर्यातकों के लिए 'लॉटरी' से कम नहीं है। यह दावा एसबीआइ ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेड डील लागू होने पर भारत का अमरीका से ट्रेड सरप्लस सालाना 90 अरब डॉलर को पार कर सकता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अभी ट्रेड सरप्लस करीब 40 अरब डॉलर है। एसबीआइ ने कहा, अमरीका भेजे जाने वाले टॉप 15 उत्पादों में 97 अरब डॉलर अतिरिक्त निर्यात की क्षमता है। अन्य उत्पादों को जोड़ दें तो आंकड़ा सालाना 100 अरब डॉलर के पार निकल जाएगा। इससे देश की जीडीपी पर 1.1% का सीधा पॉजिटिव असर पड़ सकता है।

भारत को बांग्लादेश जैसी सुविधा मिलेगी!

अमरीका भारत को बांग्लादेश की तरह जीरो-ड्यूटी सुविधा दे सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि अमरीका के साथ डील सहज होने के बाद भारत के टेक्सटाइल और अपैरल निर्यातकों को भी अमरीकी कॉटन से बने कपड़ों पर जीरो-टैरिफ की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' टैरिफ पहले की तरह लागू रहेगा, क्योंकि कटौती जवाबी टैरिफ वाले हिस्से में ही जा रही है। ऐसे में अमरीकी कपास से बने कपड़ों पर कुल प्रभावी टैरिफ घटकर करीब 3% रह जाएगा।

75% कृषि उत्पाद टैरिफ मुक्त एसबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेड डील के बाद भारत से जाने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात में बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि लगभग 75% कृषि उत्पाद अमेरिका में बिना किसी टैक्स (जीरो टैरिफ) के जाएंगे। सबसे अधिक लाभ चावल, मसाले, तिलहन, चाय-कॉफी को मिलेगा। अमरीका के कुल आयातित चावल में भारत की हिस्सेदारी 24% है।

सर्वे रिपोर्ट... @पत्रिका इंफोग्राफिक्स

म्यूचुअल फंड-इक्विटी को छोड़ा पीछे

62% जेन जेड-मिलेनियल्स की पहली पसंद बना सोना

नई दिल्ली@पत्रिका. *म्यूचुअल फंड्स-एसआइपी की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद जेन जेड और मिलेनियल्स के बीच सोने पर भरोसा मजबूत बना हुआ है, लेकिन इसे खरीदने का तरीका धीरे-धीरे बदल रहा है। स्मिटन पल्सएआइ के सर्वे में सामने आया है कि सोने की खरीद अब छोटी रकम और छोटी मात्रा में होने लगी है। 62% जेन जेड-मिलेनियल्स के लिए निवेश की पहली पसंद सोना है।*

₹25,000 आज निवेश करना हो तो कहां लगाएंगे

- 61.9% सोना
- 16.6% म्यूचुअल फंड
- 13% बैंक एफडी
- 6.6% स्टॉक्स
- 1.9% क्रिप्टोकरेंसी

65.7% लोगों ने कहा म्यूचुअल फंड या इक्विटी की तुलना में सोना उन्हें ***सबसे सुरक्षित विकल्प लगता है***

कितना सोना खरीदा *खरीदारों की संख्या प्रतिशत में*

10 ग्राम से ज्यादा	5 से 10 ग्राम	5 ग्राम से कम
12%	26.1%	61.9%

05 ग्राम से कम सोना खरीदने वालों में 34.4% लोगों ने 2 से 5 ग्राम के बीच और ***27.5% लोगों ने 2 ग्राम से कम सोना खरीदा***

42% परिवार समय-समय पर छोटी मात्रा में सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं, ***जबकि 58% अभी भी एकमुश्त और अवसर आधारित खरीद करते हैं***

52.7% लोग अगले 12 से 24 महीनों में सोना खरीदने के लिए संभावनाएं देख रहे, ***31.4% लोगों ने कहा, वे निश्चित रूप से सोने की खरीदारी करेंगे***

कहां से खरीदते हैं सोना

ब्रांडेड ज्वेलरी चेन	स्थानीय ज्वैलर्स	ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
38.3%	34.7%	5.2%

सोना खरीदने को लेकर प्रमुख चिंता

वजह	उत्तरदाता
शुद्धता	49.4%
मेकिंग चार्ज	21%
रीसेल वैल्यू	17%
ऊंची कीमतें	38.9

निवेशक त्रस्त 5.51% की गिरावट निफ्टी आइटी इंडेक्स में गुरुवार को, 10 माह का निचला स्तर

टेक स्टॉक्स में कोहराम, आइटी इंडेक्स में इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी गिरावट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. एंथ्रॉपिक के नए एआइ टूल्स से पहले से ही दबाव में चल रहे आइटी शेयरों पर गुरुवार को दोहरी मार पड़ी। अमरीका में उम्मीद से अधिक रोजगार बढ़ने से यह संकेत मिला कि वहां ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं, इससे ग्लोबल टेक शेयरों के साथ भारतीय आइटी शेयर क्रैश हो गए। सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली देसी कंपनियों का इंडेक्स निफ्टी आइटी 5.51% टूटकर 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी आइटी इंडेक्स 2026 के डेढ़ महीने में ही 12% से ज्यादा गिर चुका है। आइटी शेयरों में बिकवाली से गुरुवार को सेंसेक्स 559 अंक लुढ़ककर 83,675 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 147 अंक टूटकर 25,807 पर बंद हुआ।

टीसीएस सहित सभी प्रमुख आइटी कंपनियों की मार्केट कैप में लगातार गिरावट देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे वैश्विक स्तर पर तकनीकी शेयरों पर बढ़ते दबाव और एआइ से जुड़ी चिंताएं हैं। एआइ कंपनी एंथ्रॉपिक के 11 नए एआइ टूल्स ने भारत सहित दुनियाभर की आइटी-सॉफ्टवेयर कंपनियों (एसएएएस) के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कंपनी के एआइ प्लेटफॉर्म क्लॉड को-वर्क के नए ऑटोमेशन एआइ टूल्स लीगल, सेल्स-मार्केटिंग, डॉक्यूमेंट और कॉन्टैक्ट रिव्यू, कंप्लायंस और डेटा एनालिसिस जैसे दर्जनों प्रोफेशनल कम ऑटोमेट यानी खुद कर सकता है। ये टूल्स आइटी सर्विसेज की मांग को कम कर सकते हैं। इससे पिछले एक सप्ताह से आइटी-सॉफ्टवेयर शेयर क्रैश हो रहे हैं। एएमडी, कॉग्नजेंट, एसेंचर, सेल्सफोर्स जैसी दिग्गज अमरीकी टेक कंपनियों के शेयरों में भी लगातार गिरावट जारी है।

तमाम आइटी स्टॉक्स धराशायी

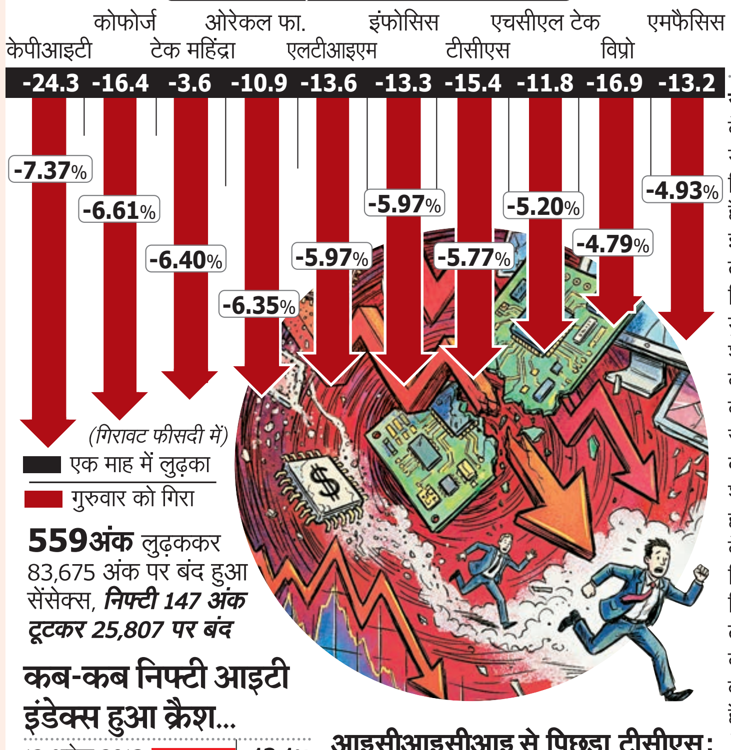

559अंक लुढ़ककर 83,675 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, ***निफ्टी 147 अंक टूटकर 25,807 पर बंद***

कब-कब निफ्टी आइटी इंडेक्स हुआ क्रैश...

तारीख	गिरावट
12 अप्रैल 2013	-12.1%
22 मार्च 2020	-9.6%
19 मई 2022	-6.1%
4 फरवरी 2026	-5.87%
12 फरवरी 2026	-5.51%

आइसीआइसीआइ से पिछड़ा टीसीएस: एसबीआइ के बाद आइसीआइसीआइ बैंक ने भी बाजार पूंजी के मामले में टीसीएस को पीछे छोड़ दिया है। टीसीएस का मार्केट कैप घटकर 9.96 लाख करोड़ रुपए रह गया। आइसीआइसीआइ का मार्केट कैप बढ़ 10.21 लाख करोड़ रुपए हो गया।

क्या करें निवेशक

सॉफ्टवेयर कंपनियों के भविष्य को लेकर मार्केट में डर है। निवेशकों का मानना है कि एआइ अब इंजीनियर्स की जगह लेने को तैयार है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आइटी शेयरों में करेक्शन की वजह फंडामेंटल कमजोरी नहीं बल्कि सेंटिमेंटल है। इस वजह से आइटी शेयरों में बिकवाली हो रही है। बोनांजा के एनालिस्ट डी विठलानी ने कहा, निवेशकों को शॉर्ट टर्म में आइटी शेयरों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी निवेशक 'सेल-ऑन-राइज' स्ट्रेटेजी यानी तेजी आने पर बिकवाली की रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन वजहों से लगातार गिर रहे आइटी शेयर

1. रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा पहले अमरीका जैसे बड़े मार्केट्स में कंपनियों के आइटी पर ज्यादा खर्च न करने का असर आइटी स्टॉक्स पर पड़ा था। ***अब एआइ टूल्स का असर पड़ने की आशंका से आइटी शेयरों में गिरावट आ रही है।***
2. अमरीका में बेरोजगारी दर गिरकर 4.3% पर आ गई। इससे फेडरल रिजर्व को कुछ समय तक महंगाई पर नजर रखते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखने की सहूलियत मिल गई। ***दरों में कटौती में देरी की आशंका से अमरीका टेक शेयरों में गिरावट आई।***
3. इसका असर भारतीय आइटी कंपनियों पर पड़ा, क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अमरीका से आता है। अगर ***वहां ब्याज दरें घटती तो आइटी सर्विसेज पर खर्च बढ़ सकता था, जो पिछले कुछ साल से धीमा पड़ा हुआ है।***

सीकेवाइसी 2.0 इसी माह शुरू होगी सेवा

बार-बार केवाइसी का झंझट खत्म, डिजिलॉकर से जुड़ेगा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े काम के लिए अब आपको बार-बार केवाइसी कराने की झंझट नहीं झेलनी होगी। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार फरवरी के आखिर तक सेंट्रल केवाइसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाइसी 2.0) का नया और बेहतर वर्जन लाने जा रही है। इसे डिजिलॉकर से जोड़ा जाएगा, जिससे आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और जांच तुरंत और सीधे सरकारी डेटाबेस से हो सकेगा। डिजिलॉकर से सीकेवाइसी के जुड़ने से ग्राहकों के लिए समय-समय पर होने वाले केवाइसी अपडेट की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे बैंकों, बीमा कंपनियों, म्युचुअल फंड और अन्य संस्थानों में बार-बार होने वाले वेरिफिकेशन से छुटकारा मिलेगा।

कैसे होगा वेरिफिकेशन?

डिजिलॉकर क्लाउड-आधारित एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, जहां दस्तावेज और सर्टिफिकेट स्टोर और वेरीफाई किए जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि सीकेवाइसी 2.0 के तहत संस्थानों की ओर से अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच सीधे उन अथॉरिटीज से की जाएगी, जिन्होंने वे डॉक्यूमेंट जारी किए है। अपग्रेड होने वाली इस रजिस्ट्री में एआइ का इस्तेमाल करके फोटो मिलान किया जाएगा ताकि दो रेकॉर्ड न बनें। पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार डेटाबेस के जरिए एपीआइ बेस्ड वेरिफिकेशन होगा। सीकेवाइसी से 8,000 और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्ट्री' पर 6,000 संस्थाओं को जोड़ा गया है।

तैयारी एआइ से अनचाही कॉल पर लगाम

... तो शिकायत के बिना बंद होगा स्पैमर का मोबाइल नंबर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. टेलीकॉम नियामक ट्राइ अब एआइ की मदद से स्पैम कॉल करने वालों का नंबर सीधे बंद करने की तैयारी में है। अब कार्रवाई के लिए किसी की शिकायत का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि एआइ का डेटा ही काफी होगा। यह कार्रवाई उन मोबाइल नंबरों पर किया जाएगा जिसे टेलीकॉम कंपनियों के एआइ सिस्टम ने स्पैम के तौर पर चिन्हित किया है। अधिकारियों ने बताया कि ट्राइ संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहा है। प्रस्ताव के तहत एआइ सिस्टम किसी नंबर को लगातार 10 दिन तक 'संभावित स्पैम' के तौर पर दिखाता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। अभी 10 दिन के भीतर 5 अलग-अलग शिकायतें मिलती हैं, तो टेलीकॉम कंपनियां कार्रवाई करती हैं। इसे बदलने की तैयारी है।

यह है खतरा

- **डिलीवरी** एजेंट्स और सेल्स के काम से जुड़े लोगों पर हो सकता है इसका असर।
- **30-40 करोड़** है हर महीने एआइ की ओर से संदिग्ध बताए जाने वाले कॉल्स-मैसेज की संख्या।

अनावरण कंपनी ने शुरू की प्री-बुकिंग

प्रीमियम एसयूवी बाजार में नई एमजी मजेस्टर की एंट्री

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने गुरुवार को मांगर क्रेशपेड साइट पर डी प्लस सेग्मेंट की नई एसयूवी एमजी मजेस्टर का अनावरण किया। मेजेस्टर को इससे पहले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रा ने कहा कि भारत का प्रीमियम एसयूवी बाजार तेजी से बदल रहा है। कस्टमर को अब जगह के साथ ही ऐसा वाहन चाहिए जो उसकी जीवनशैली का हिस्सा बने। एमजी मेजेस्टर के साथ हमने ऐसी एसयूवी तैयार की है जो क्षमता में मजबूत, आराम में परिष्कृत और इंजीनियरिंग में भरोसेमंद है। यह लेवल 2 एडीएएस से लैस है, जो स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और एक्सीलरेशन में ड्राइवर को मदद कर वाहन को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। इसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक (फ्रंट, रियर और सेंटर) और एडवांस 4 डब्ल्यूडी सिस्टम के साथ 10 ऑफ-रोड मोड हैं, जो बर्फीली, रेतीली सहित हर तरह की राह को आसान बनाते हैं। इसके अनावरण के साथ ही इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है।

उत्पादन घटा

पांच महीने के उच्च स्तर पर क्रूड ऑयल

मुंबई@ पत्रिका. कच्चे तेल की कीमतें 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड का भाव 70 के पार निकला गया है। यूएस-ईरान के बढ़ते तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इस साल हर हफ्ते क्रूड ऑयल बढ़ा है। जियोपॉलिटिकल तनाव ने फ्यूचर्स को ऊपर की तरफ धकेल दिया है। एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, यूएस में पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल का स्टॉक 8.5 मिलियन बैरल बढ़कर जून के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। दरअसल कजाकिस्तान, वेनेजुएला और ईरान में नुकसान के बीच पिछले महीने ओपेक देशों का प्रोडक्शन गिरा है। अलायंस के 22 देशों ने जनवरी में एवरेज 42.448 मिलियन बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शन किया, जो दिसंबर की तुलना में 439,000 कम है।

प्रीमियम सेगमेंट चमका एक करोड़ से ऊपर के घर 9% ज्यादा बिके

छोटे शहरों में भी महंगे घरों की डिमांड तेज, किफायती मकानों की बिक्री घटी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. टियर-2 शहरों में भले ही कुल मकानों की बिक्री 10% घटी हो, पर एक करोड़ रुपए से महंगे मकानों की बिक्री में इजाफा हुआ है। प्रॉपइक्विटी की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में शीर्ष 15 टियर-2 शहरों में मकानों की बिक्री का कुल मूल्य 1.48 लाख करोड़ रहा, जबकि बिक्री मात्रा 10% घट 1,56,181 यूनिट रह गई। मकानों की बिक्री अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे बड़े बाजारों में घटी, जबकि मोहाली और लखनऊ जैसे शहरों ने सकारात्मक प्रदर्शन किया। बिक्री में सबसे अधिक गिरावट विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर में दर्ज की गई। जयपुर में 5% गिरावट आई।

शहरवार आवासीय इकाइयों की बिक्री

शहर	2024	2025	बदलाव(%)
अहमदाबाद	55,315	51,148	-8%
सूरत	23,342	19,835	-15%
वडोदरा	17,045	13,798	-19%
नासिक	12,492	11,188	-10%
जयपुर	10,271	9,758	-5%
नागपुर	7,653	6,260	-18%
भुवनेश्वर	6,538	4,885	-25%
लखनऊ	3,812	4,053	6%
भोपाल	3,804	3,599	-5%
विशाखापत्तनम	3,858	2,406	-38%
कोच्चि	2,659	2,214	-17%

लग्जरी मकान खूब बिके: वर्ष 2025 में एक करोड़ रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 15% की गिरावट दर्ज की गई और इनकी हिस्सेदारी 2024 के 77% से घटकर 72% रह गई। वहीं दूसरी ओर 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले मकानों की बिक्री में 9% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल बिक्री में हिस्सेदारी 23% से बढ़कर 28% हो गई।

पेज वन का शेष...

आज से...

अत्याधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट सुरक्षा इंतजाम: सेवा तीर्थ और कर्त्तव्य भवन परिसर अत्याधुनिक तकनीक सहित सभी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों से लैस हैं। इनमें स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, निगरानी नेटवर्क और इमरजेंसी सिस्टम जैसी व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं। 4-स्टार मानकों के अनुसार डिजाइन किए गए इन परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च-प्रदर्शन वाली भवन संरचनाएं शामिल हैं। **कर्त्तव्य भवन 1- 2 से चलेंगी टॉप मिनिस्ट्री:** सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 में गृह, वित्त, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कॉर्पोरेट कार्य, शिक्षा, सूचना एवं प्रसारण , कृषि एवं किसान कल्याण सहित प्रमुख मंत्रालय संचालित होंगे जो अब तक नॉर्थ-साउथ ब्लॉक व अन्य स्थानों से संचालित थे। इनमें कुछ मंत्रालय शिफ्ट होकर काम शुरू कर चुके हैं।

भारत खरीदेगा...

भारत में ही बनाए जाएंगे 96 विमान: इस प्रस्ताव के अनुसार, भारत दसॉल्ट एविएशन से 18 रफाल सीधे खरीदेगा। बाकी 96 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इनमें से 26 विमान दो सीट वाले होंगे, जिनका उपयोग ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। भारत में विमान बनाने के दौरान 60 प्रतिशत तक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। डील में आधुनिक तकनीक भारत को देने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने की बात भी शामिल है। दसॉल्ट एविएशन भारत की निजी कंपनियों के साथ मिलकर निर्माण, असेंबली और रखरखाव का काम कर सकती है। इससे देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था रफाल का इस्तेमाल: रफाल विमानों का इस्तेमाल भारत ने पिछले साल मई में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' में किया था, जिसमें पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे। इन विमानों में स्कैल्प (एससीएएलपी) मिसाइलें लगी हुईं है, जो 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक बहुत सटीक हमला कर सकती है। इसके अलावा यह विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मेटियोर, हैमर, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और आधुनिक रडार से भी लैस है। नए विमानों में भारत की स्वदेशी मिसाइल और अन्य सामग्री लगाए जाने की भी योजना है।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: सरकार के इस फैसले पर एयर मार्शल (रि.) अनिल चौपड़ा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दोनों हमारे लिए चुनौती हैं। ऐसे में यह एक अच्छा फैसला है। हम नई कंपनी से विमान लेते तो प्रोसेस में ही 6-8 साल लग जाते। फ्रांस हमारा विश्वसनीय और पुराना सहयोगी है। भारत में रफाल के बनने की बात है तो पहले से ही इसके फ्यूजलेज बनने की फैक्ट्री की बात हो गई है। इंजन बनाने की भी फैक्ट्री चालू हो रही है। एसेंबली लाइन भी जल्द होगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण है।

200 अड्डे बंद करवाए, डिजिटल अरेस्ट से ठग रहे थे भारतीयों को

एक्शन: कंबोडिया में गांधी-अंबेडकर के फोटो, सीबीआइ-मुंबई पुलिस का 'दफ्तर'!

नोमपेन्ह (कंबोडिया)@ पत्रिका. कंबोडिया में कंपोट प्रांत में महात्मा गांधी-बाबा साहेब आंबेडकर के होर्डिंग, अशोक चक्र के बड़े फोटो के साथ सीबीआइ और मुंबई पुलिस का कार्यालय! दृश्य और बात चौंकाने वाली है लेकिन कंबोडिया में वियतनाम सीमा पर ऐसे अड्डों से भारत में डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से लाखों-करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं। कंबोडिया के धोखाधड़ी विरोधी आयोग ने साइबर ठगों के ऐसे 200 अड्डों को बंद करवाया है। देश के

वरिष्ठ मंत्री और आयोग के अध्यक्ष छाय सिनारिथ के निर्देश पर हुई यह कार्रवाई की गई। आयोग ने माई कैसिनो के नाम से चर्चित इस विस्तृत क्षेत्र का मीडिया को दौरा भी करवाया जहां नकली भारतीय व थाईलैंड के कार्यालयों के अलावा कंप्यूटर टर्मिनलों की कतारें लगी थीं। डॉन की गिरफ्तारी के बाद भाग गए ठग, कम पड़ गई पुलिस

कंपोट प्रांत के पुलिस प्रमुख माओ चानमोथुरिथ ने बताया कि इन ठगी केंद्रों पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। इस पूरे क्षेत्र का कथित डॉन ली कुओंग की गिरफ्तारी के बाद यहां काम करने वाले ठग भाग गए। उस समय यहां पुलिस पहुंची थी तो कम संख्या के कारण एक्शन नहीं ले पाई।

अमरीका: सिएटल सड़क हादसे में तीन साल बाद समझौता

पुलिस की गाड़ी की टक्कर से हुई थी मौत, जाह्नवी के परिवार को मिलेंगे 262 करोड़

वाशिंगटन@ पत्रिका. अमरीका के सिएटल शहर ने 2023 में तेज रफ्तार पुलिस कार की टक्कर से मारी गई 23 वर्षीय भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला के परिवार के साथ 2.9 करोड़ डॉलर (करीब 260 करोड़ रुपए से अधिक) का समझौता किया है।

मूलतः आंध्र प्रदेश की जाह्नवी नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के सिएटल कैंपस में इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर डिग्री कर रही थीं। 23 जनवरी 2023 को वह सड़क पार कर रही थीं, तभी अधिकारी केविन डेव ने 25 मील प्रति घंटे की सीमा वाले क्षेत्र में 74 मील प्रति घंटे (119 किमी प्रति घंटा) की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। वह ड्रग ओवरडोज कॉल पर जा रहे थे, इमरजेंसी लाइट चालू थी और चौराहों पर सायरन बजाया गया था। सिटी अटॉर्नी एरिका इवांस ने कहा, 'जाह्नवी की मौत दिल तोड़ने वाली थी। उनकी जिंदगी मायने रखती थी।' हादसे के बाद एक अन्य अधिकारी के बॉडी कैमरा वीडियो में जाह्नवी की जिंदगी को 'सीमित मूल्य' बताने वाली टिप्पणी सामने आने से भारत और अमरीका में व्यापक आक्रोश फैल गया। नागरिक निगरानी संस्था ने यूनियन लीडर अधिकारी डेनियल ऑडरेर की टिप्पणी को विभाग की छवि के लिए नुकसानदेह माना; उन्हें बर्खास्त किया गया, जिस पर उन्होंने गलत तरीके से बर्खास्तगी के लिए शहर प्रशासन पर मुकदमा किया। समझौते के तहत अब 2 करोड़ डॉलर बीमा से मिलेंगे और शेष राशि शहर प्रशासन देगा।

जो लोग अपने देश से सच्चा प्रेम करते हैं, उनके मन में निष्ठा स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती है। - ह्यूगो एल ब्लैक

पाकिस्तान का पाखंड

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नवीनतम रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को पिछले वर्ष नवंबर में दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक हमले से जोड़ा गया है, ने एक बार फिर पाकिस्तान की पाखंडपूर्ण नीति को बेनकाब किया है। गौरतलब है कि इस हादसे में धीमी गति से चल रही एक कार में हुए भीषण विस्फोट से 15 निर्दोष मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार, एक सदस्य देश ने जानकारी दी है कि जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो साबित करता है कि यह आतंकी संगठन अब भी पूरी तरह से सक्रिय है। इससे पाकिस्तान के उन दावों की पोल भी खुलती है, जिनमें वह जैश जैसे आतंकी संगठनों के पूरी तरह से खत्म होने की डींगे हांकता रहा है। रिपोर्ट यह खुलासा भी करती है कि जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने पिछले वर्ष अक्तूबर में ही अपनी महिला विंग जमात-उल-मुमिनात भी बनाई थी। रिपोर्ट में सदस्य देशों के बीच जैश की स्थिति को लेकर विरोधाभास दिखता है, लेकिन इससे साफ संकेत मिलता है कि यह आतंकी संगठन न केवल सक्रिय है, बल्कि अपने नेटवर्क के विस्तार की योजना भी बना रहा है। दरअसल, पाकिस्तान का पाखंड लंबे समय से जगजाहिर है। वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पर खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, पर हकीकत कुछ और ही है। इससे पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से बाहर किए जाने पर भी सवाल उठते हैं। कनाडा स्थित जियोपॉलिटिकल मॉनिटर की हालिया रिपोर्ट भी कहती है कि पाकिस्तान को इस सूची से हटाना समय से पहले लिया गया निर्णय था, क्योंकि देश में आतंकी गतिविधियां और इनके लिए फंडिंग लगातार जारी है। पाकिस्तान को सिर्फ जैश ही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के मामले में भी तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बीएलए को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र है, जिसे द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने अंजाम

दिया था, जो लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। यह तथ्य ही है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की संरचना, विचारधारा, प्रशिक्षण और फंडिग के स्रोत भी समान हैं, बस अंतरराष्ट्रीय निगरानी से बचने के लिए नाम बदले गए हैं। लिहाजा, यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं बनाया गया, तो यहां आतंकवाद की जड़ें और गहरी होंगी।

उम्मीदें धुंधली ही हैं

कल हुआ राष्ट्रीय मतदान बांग्लादेश के राजनीतिक परिवर्तन की पहली चुनावी परीक्षा जरूर था, पर लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की उम्मीदें अब भी धुंधली ही नजर आ रही हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, पर बांग्लादेश का उदाहरण बताता है कि लोकतंत्र को धीरे-धीरे कैसे चौपट किया जाता है।

डेढ़ साल पहले, बांग्लादेश को देखकर ऐसा लग रहा था, मानो वह लोकतांत्रिक पतन के वैश्विक दौर को चुनौती देने की राह पर है। आर्थिक निराशा से जूझ रही युवा पीढ़ी के नेतृत्व में हुए व्यापक जन-प्रदर्शनों ने पांच अगस्त, 2024 को शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका। यह इस बात का प्रमाण था कि जहां भी लोकतंत्र दबाव में आता है, वहां के नागरिक एकजुट होकर निरंकुश सत्ताओं को उखाड़ फेंक सकते हैं और व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। कल हुआ राष्ट्रीय मतदान बांग्लादेश के राजनीतिक बदलाव की पहली चुनावी परीक्षा जरूर था, पर लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की उम्मीदें अब भी धुंधली ही नजर आ रही हैं।

हसीना की विदाई के बाद देश में लगातार हिंसा, नौकरशाही और औद्योगिक हड़तालों, बाधा उत्पन्न करने वाले प्रदर्शनों और राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया। इसने एक कड़वी हकीकत को उजागर किया कि जब लोकतंत्र को संभालने वाली संस्थाएं खोखली हो जाती हैं, तो लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण आसान नहीं होता। आज बांग्लादेश इसी जटिल सच्चाई का जीवंत उदाहरण बन चुका है।

जाहिद हुसैन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

1990 के दशक के शुरुआती वर्षों से बांग्लादेश की राजनीति दो प्रभावशाली महिलाओं-अवामी लीग की नेता शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की खालिदा जिया की तीखी प्रतिद्वंद्विता के इर्द-गिर्द घूमती रही। दोनों नेताओं और उनकी पार्टियों के बीच चुनावी मैदान में वर्षों तक कड़वी लड़ाई चलती रही। इस कड़वाहट के बावजूद, देश में सत्ता का हस्तांतरण काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। इसका श्रेय उन 'गैर-पक्षपाती अंतरिम प्रशासन' को जाता है, जो चुनाव कराने व सत्ता की बागडोर सौंपने के लिए अस्थायी रूप से कमान संभालते थे। लेकिन 2011 में, जब शेख हसीना का शासन ज्यादा केंद्रीकृत और सत्तावादी स्वरूप लेने लगा, तो इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद चुनावी अनियमितताओं और विवादित जनादेशों का सिलसिला शुरू हुआ। भाई-भतीजावाद व कथित भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती गईं, और सत्ता ने अदालतों, पुलिस और अन्य सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल विरोधियों को डराने-धमकाने के लिए करना शुरू कर दिया।

बांग्लादेशी नागरिकों को उम्मीद थी कि 2024 के जन-आंदोलन से देश में स्थिरता और जवाबदेही की नई सुबह होगी। शुरुआती उम्मीदों की एक बड़ी वजह नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपना था। इससे यह विश्वास जगा कि शायद बांग्लादेश लोकतंत्र, पारदर्शिता और संस्थागत मजबूती की दिशा में नई शुरुआत कर सकेगा। लेकिन यूनुस देश में शांति व अनुशासन बहाल करने के लिए जूझते नजर आए। पुलिस और अदालतों जैसी अहम संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में भी वह सफल नहीं हो सके। उधर, क्रांति के बाद से बढ़ती महंगाई, कमजोर वेतन वृद्धि और अन्य आर्थिक दबावों ने आम परिवारों की कमर तोड़ दी।

चुनाव की साख पर पहले ही सवालिया निशान लग चुके थे। राजनीतिक हिंसा, वोट खरीदने के आरोप, अन्य अनियमितताएं और अवामी लीग की भागीदारी पर लगा प्रतिबंध इसकी निष्पक्षता को संदिग्ध बना रहे हैं। फिर भी, इस चुनावी दौड़ में फिलहाल खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सबसे आगे नजर आ रही है। हालांकि, नतीजों का अंदाजा लगाना अभी बेहद मुश्किल है। इस बार करीब 43 प्रतिशत मतदाता 18 से 37 वर्ष के बीच की उम्र के हैं। यह युवा वर्ग अतीत की दलगत दुश्मनियों से अधिक कानून-व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और निष्पक्ष शासन जैसे व्यावहारिक मुद्दों को लेकर उत्साहित है। ऐसे में, यह पीढ़ी बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

इस पूरी राजनीतिक तस्वीर में इस्लामी ताकतें एक और अप्रत्याशित कारक बनकर उभरी हैं। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में इन ताकतों को लंबे समय तक हाशिये पर रखा गया था। पर इन ताकतों ने मौजूदा राजनीतिक व संस्थागत शून्य का भरपूर फायदा उठाया और वे अब कहीं अधिक मुखर हैं। इसके अलावा, एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार, पहली बार के मतदाताओं (37 प्रतिशत) की योजना जमात-ए-इस्लामी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की थी। इस पार्टी ने अपनी मजबूत संगठनात्मक क्षमता तथा दो प्रमुख दलों की साख गिरने के बीच खुद को विकल्प के रूप में पेश किया है।

चुनाव का एक और अहम पहलू है-नए राष्ट्रीय चार्टर पर जनमत-संग्रह। इसमें निष्पक्ष चुनावों की गारंटी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका की शक्तियों पर स्पष्ट सीमाएं तय करने की प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देने की बात कही गई है। यह मुल्क के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि, इन्हें अमल में लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीएनपी इसके कुछ बुनियादी प्रावधानों का विरोध कर रही है। कई अन्य दलों ने भी आपत्तियां जताई हैं। यदि इसे मंजूरी मिल भी जाती है, तो भी इसे जमीन पर उतारने के लिए नए कानून, संविधान में संशोधन और राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता होगी, जिसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आती है।

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जनविद्रोह के बाद डगमगा गई। नए नेतृत्व को ऐसे वैश्विक माहौल का सामना करना होगा, जिसमें बढ़ता संरक्षणवाद, बिखरती आपूर्ति श्रृंखलाएं और जलवायु संकट जैसी चुनौतियां हैं। इसके अलावा, बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में दरारें साफ देखी जा सकती हैं। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के चलते बांग्लादेश के अंतरिम नेता और प्रदर्शनकारी भड़क गए। जबकि भारत ने हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। इन तनावों का असर अब वीजा निलंबन और व्यापारिक व्यवधानों के रूप में भी सामने आने लगा है।

2010 के दशक की 'अरब स्प्रिंग' से लेकर श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अमेरिका और अन्य जगहों पर हाल में हुए विद्रोहों तक, जनसैलाब ने राजनीतिक बंदिशों को तोड़ने का काम तो किया, पर ये उपलब्धियां या तो फीकी पड़ गईं या फिर बेहद नाजुक दौर में हैं। इसका कारण उन निष्पक्ष संस्थानों का अभाव है, जो लोकतांत्रिक परिवर्तन की इस जटिल प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने में सक्षम हों। यह चुनौती केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है। अमेरिका जैसे देश में भी ट्रंप प्रशासन की कार्रवाइयों ने अदालतों, कानूनी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को पार्टी के झगड़े में घसीटकर तथा चुनावी नतीजों पर सवाल उठाकर लोकतंत्र के स्तंभों को कमजोर करने का खतरा पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि तानाशाहों को सत्ता से उखाड़ फेंका जा सकता है, पर उनके द्वारा किए गए नुकसानों की भरपाई करना किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है।

- साथ में टॉम फेलिक्स जोहंक

©The New York Times 2026

मुद्दा

ताकि जिंदा रहे रेडियो

विस्तृत नेटवर्क के बावजूद पारंपरिक रेडियो की लोकप्रियता घटी है। भारत में प्रासंगिक बने रहने के लिए उसे अमेरिकी और ब्रिटिश प्रसारण मॉडलों से सीख लेनी होगी।

डिजिटल व इंटरनेट के दौर में भी रेडियो न सिर्फ जिंदा है, बल्कि संचार, संवाद और मनोरंजन के माध्यम के तौर पर प्रासंगिक बना हुआ है। हालांकि, इंटरनेट की प्रभावी उपस्थिति से पहले इसका एक स्वर्ण युग भी रहा है। तब पारंपरिक ट्रांजिस्टर सेटों के जरिये वह खेतों-खलिहानों से लेकर नदी में हिलकोरें मारती नावों व पहाड़ों तक इसकी मौजूदगी थी। यह और है कि रील्स के प्रति बढ़ते आकर्षण ने रेडियो के सामने अस्तित्व की चुनौती पेश कर दी है। ऐसे में, सवाल उठता है कि क्या रेडियो अतीत की तरह प्रभावी, प्रासंगिक और उपयोगी बना रह सकता है। विश्व रेडियो दिवस के मौके पर कम से कम भारतीय परिदृश्य में इस पर विचार होना चाहिए।

समय के साथ रेडियो ने खुद को भी बदला है। अब यह सिर्फ पुराने ट्रांजिस्टर सेटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आधुनिक स्मार्ट स्पीकर, मोबाइल एप और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के जरिये भी दुनिया के हर कोने में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। कारों में भी वह 'कार रेडियो' के तौर पर जिंदा है। ड्राइविंग करते समय भारत में रेडियो अब भी सबसे लोकप्रिय माध्यम है। रेडियो की मौजूदगी के लिए स्थानीय विषय वस्तु भी बड़ा माध्यम बनी है। स्थानीय खबरें, मौसम की जानकारी और स्थानीय भाषा में जितने कार्यक्रम सार्वजनिक रेडियो, यानी आकाशवाणी पर है, उतना न तो इंटरनेट पर है और न टीवी में। रेडियो के आधुनिक अस्तित्व को बनाने में सस्ता इंटरनेट पैक सहज भूमिका निभा सकता है। इसके जरिये यह दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से काम कर सकता है। प्राकृतिक आपदा या संकट के समय, जब इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं, तब रेडियो ही संचार का अकेला विश्वसनीय साधन बचा रहता है। रेडियो की महत्ता उसकी पोर्टेबिलिटी भी बढ़ा देती है। स्थानीय समुदायों से जुड़ाव और आधुनिक तकनीक के संग तालमेल इसकी प्रासंगिकता बढ़ाते हैं।

उमेश चतुर्वेदी

भारत में लगभग डेढ़ हजार रेडियो स्टेशन हैं, जिनमें आकाशवाणी के साथ ही निजी और सामुदायिक रेडियो शामिल हैं। जुलाई 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, देश में आकाशवाणी से 585 एफएम स्टेशन और 591 सामान्य स्टेशन काम कर रहे हैं। अकेले आकाशवाणी के ही देश भर में करीब 755 ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं। 231 स्टेशनों पर प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। आकाशवाणी का नेटवर्क देश के करीब 99.2 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंच रखता है। इसके साथ ही, देश के 112 शहरों में 388 निजी एफएम रेडियो स्टेशन सक्रिय हैं। देश में 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के जरिये किसानों, जनजातीय क्षेत्रों और स्थानीय समुदायों के लिए प्रसारण हो रहे हैं। इतना विशाल नेटवर्क होने के बावजूद पारंपरिक रेडियो प्रसारण और उसे सुनने को लेकर दिलचस्पी घटी है, हालांकि एफएम प्रसारणों मे कुछ दिलचस्पी बनी हुई है। अगर रेडियो को भारत में और ज्यादा प्रासंगिक होना है, तो उसे अमेरिकी और ब्रिटिश रेडियो प्रसारण मॉडल से प्रेरणा लेनी होगी। अमेरिका, ब्रिटेन आदि पश्चिमी देशों में रेडियो ट्रैफिक में सुना जाता है, क्योंकि यह अकेला संचार माध्यम है, जिसे ड्राइविंग करते हुए भी सुना जा सकता है।

भारत में भी ट्रैफिक को रेडियो का सबसे बड़ा लक्षित श्रोता बनाने की गुंजाइश है। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, देश में करीब सात करोड़ कारें पंजीकृत हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। देश में करीब दो करोड़ कारें हमेशा सड़कों पर रहती हैं। व्यस्त समय में इस संख्या में कई गुना इजाफा हो जाता है। रेडियो ट्रकों और बसों के ड्राइवरों को भी अपना लक्षित श्रोता बना सकता है। लेकिन इसके लिए विशेष रेडियो कार्यक्रम बनाने होंगे।

edit@amarujala.com

खूबसूरत आजादी का आगाज

वृद्धावस्था वह खूबसूरत आजादी है, जहां आपको दुनिया की परवाह नहीं होती। यह वह दौर है, जब आप अपनी आंखों में एक शरारत भरी चमक लेकर बेबाकी से सच बोल सकते हैं।

अक्सर लोग समझते हैं कि वृद्धावस्था जीवन की ढलान है, पर सच तो यह है कि यह जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े होने जैसा है। इसे उम्र का ढलना नहीं, बल्कि अनुभवों का निखरना कहना चाहिए। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, इन्सान एक पुरानी कीमती मदिरा की तरह और भी गहरा और लाजवाब होता जाता है-एक ऐसी गहराई, जो जवानी के जोश में कभी मिल ही नहीं सकती। चेहरे की झुर्रियां वक्त की मार नहीं होतीं, बल्कि ये तो उस मुस्कुराहट की निशानियां हैं, जो आपने वर्षों तक बांटी हैं। ये निशान ही आपकी जीत और जिंदादिली के सबूत हैं।

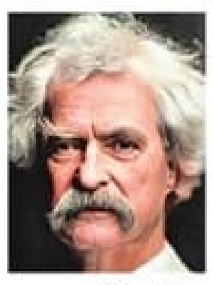

मार्क ट्वेन

बढ़ती उम्र का दुख यह नहीं होता है कि शरीर धीमा हो जाता है, बल्कि असली दुख तब होता है, जब हम अपने भीतर के 'मासूम बालक' को खो देते हैं। जब तक हमारे भीतर जिज्ञासा, हंसी और सीखने की चाह जिंदा है, तब तक हम सचमुच बुजुर्ग नहीं होते। असली ताकत शरीर के जोड़ों में नहीं, बल्कि आपकी उस रूह में होती है, जो आखिरी दम तक मुस्कुराना जानती है। वृद्धावस्था तो वह खूबसूरत आजादी है, जहां आपको दुनिया की परवाह नहीं होती। यह वह दौर है, जब आप अपनी आंखों में एक शरारत भरी चमक लेकर बेबाकी से सच बोल सकते हैं।

मुड़-मुड़ के देख

जरा सोचिए, अगर हम अस्सी साल की उम्र में पैदा होते और धीरे-धीरे जवानी की तरफ बढ़ते, तो दुनिया कितनी हसीन होती! यह इस विश्वास को और पुख्ता करता है कि वृद्धावस्था में हासिल किया गया अनुभव और दृष्टिकोण, जवानी की कच्ची ऊर्जा से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति वह योद्धा होता है, जिसने जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव को पार कर अपनी मर्जी से जीने का हक कमाया है।

वृद्धावस्था कोई मजबूरी नहीं, बल्कि खुद को नए सिरे से गढ़ने की कला है। हमारा शरीर भले ही कुदरत के नियमों से बंधा हो, पर हमारा हुनर, हमारी हंसी और सोच हमेशा आजाद रहती है। बीते हुए वर्षों को अफसोस के साथ नहीं, बल्कि गर्व के साथ याद करें। शरीर भले ही थक जाए, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आपकी जीने की इच्छा कभी कम न होने पाए।

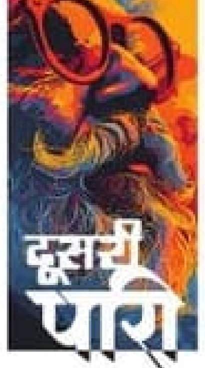

अगर आप भी अपने पोते-पोतियों के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि उनकी उच्च शिक्षा में आने वाली लागत का प्रबंधन सोच-समझकर बेहतर ढंग से करें।

पूरा होगा पोते-पोती की पढ़ाई का सपना

बेनी पाल अपनी पोती के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, पर पढ़ाई के खर्च को लेकर परेशान भी हैं।

65 वर्षीय बेनी पाल सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी हैं, जिनकी जिंदगी पोती रिया के इर्द-गिर्द घूमती है। रिया अभी चार साल की है, पर उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना चमकता है। बेनी बाबू की आखिरी इच्छा है-पोती की उच्च शिक्षा के खर्च का इंतजाम। यह कहानी अकेले बेनी बाबू की नहीं, बल्कि उन लाखों दादा-दादियों की है, जो अपने नौनिहालों के सपनों को साकार करना चाहते हैं...

बच्चों के लिए शिक्षा योजना जरूरी :
शिक्षा की बढ़ती लागत व वित्तीय जागरूकता बढ़ने से अब बुजुर्ग पारंपरिक उपहार, जैसे-नकद या सोना देने के बजाय बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए निवेश करने पर विचार करने लगे हैं। वे अपनी बचत या रिटायरमेंट फंड का कुछ हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च कर परिवार की विरासत को मजबूत कर सकते हैं।

बुजुर्गों के लिए जरूरी तैयारियां :
सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें। अपनी आय (पेंशन, ब्याज, किराया आदि), संपत्ति और नियमित खर्चों की सूची बनाएं। देखें कि कितनी राशि निवेश के लिए उपलब्ध है। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके पास 12 महीने के जरूरी खर्च के बराबर पैसे अलग रखे हों, ताकि अप्रत्याशित खर्च से एजुकेशन फंड प्रभावित न हो।

महंगाई को न करें नजरअंदाज :
उच्च शिक्षा की योजना बनाते समय महंगाई को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ट्यूशन फीस, किताबें, रहने-खाने की लागत सामान्य महंगाई से कहीं तेजी से बढ़ रही है, जिससे उच्च शिक्षा, खासकर विदेश में

पढ़ाई और भी महंगी हो जाती है। इसे ध्यान में न रखने पर पढ़ाई के लिए निवेश किया गया पैसा कम भी पड़ सकता है।

भविष्य का सोचकर योजना बनाएं :
आज मेडिकल की पढ़ाई पर जितना खर्च आ रहा होगा, पांच या 10 साल बाद वह उससे कहीं ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आज एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च एक करोड़ रुपये आ रहा है, तो 17-18 साल की उम्र में जब रिया दाखिला लेगी, तो यह खर्च महंगाई के साथ बढ़ते-बढ़ते करीब 3.45 करोड़ रुपये हो चुका होगा।

किसके नाम पर करें निवेश :
बेनी बाबू के पास पोती के लिए निवेश के दो तरीके हैं। उसके नाम से बैंक खाता खोलें। पैसे ट्रांसफर करके चुने हुए फंड में निवेश करें। 18 साल की उम्र में पूरा अधिकार उसे मिल जाएगा। दूसरा, खुद के नाम से निवेश करें और इसे पोती की पढ़ाई के लिए अलग से चिह्नित करें। बच्ची को नॉमिनी नियुक्त करें, ताकि आपकी अनुपस्थिति में भी उसे पैसे मिल सकें। बाजार की स्थिति को देखते हुए कुछ पैसा आप एकमुश्त और बाकी को एसआईपी के जरिये निवेश कर सकते हैं। 5-7 साल या उससे ज्यादा के लिए इक्विटी फंड, 3-5 साल के लिए हाइब्रिड फंड और छोटी अवधि के लिए डेट फंड या सावधि जमा (एफडी) का रुख कर सकते हैं।

- पवन पांडेय

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं edit@amarujala.com पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

म्यूचुअल फंड या पारंपरिक निवेश?

माईवेल्थग्रोथ डॉट कॉम के सह-संस्थापक हर्षद चेतनवाला बताते हैं कि बेनी पाल जी की पोती के कॉलेज शुरू करने में अभी 13-14 साल का वक्त है। ऐसे में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। इक्विटी से असहज हैं, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड अच्छा विकल्प हो सकता है। 15 साल में उतार-चढ़ाव आएंगे, पर डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने से अच्छा रिटर्न मिलेगा, बशर्ते पूरी अवधि तक निवेशित रहें और उतार-चढ़ाव से घबराएं नहीं।

एसएसवाई कब चुनें?

बच्ची की पढ़ाई और शादी के लिए सरकार समर्थित सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) चर्चित स्कीम है। चेतनवाला कहते हैं कि निवेश पर कम से कम जोखिम लेने वाले इसमें निवेश कर सकते हैं। यह टैक्स के नजरिये से भी बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें रिटर्न पूरी तरह से टैक्स फ्री है। हालांकि, लॉक-इन पीरियड का ध्यान रखना जरूरी है। सुकन्या खाता खुलने के 21 साल बाद मैच्योर होता है। बच्ची के 18 साल के पूरा होने पर पढ़ाई के लिए सिर्फ 50 फीसदी पैसा ही निकाल पाएंगे। पर 25 वर्ष तक उच्च शिक्षा जारी रहने पर बाकी 50 फीसदी हिस्सा काम आ सकता है या परिपक्वता पर विवाह अथवा अन्य कामों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विटी के साथ कुछ पैसा सुरक्षित विकल्प में डालने की सोच रहे लोग भी इसे चुन सकते हैं।

नियमित समीक्षा जरूरी

मुद्रास्फीति, बाजार की स्थिति और खर्चों में बदलाव के आधार पर निवेश की समीक्षा जरूर करें। अगर जरूरी हो, तो निवेश बढ़ाएं या स्विच करें। उदाहरण के लिए, वित्तीय लक्ष्य के करीब होने पर निवेश को इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना। निवेश के लिए वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

वरिष्ठ नागरिकों के काम की संस्थाएं

- *सेवा भारती* में बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। डायलिसिस जैसी बेहद जरूरी चिकित्सा सुविधा भी जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है। जिन बुजुर्गों को सुनने में समस्या होती है, उनके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श की व्यवस्था की जाती है। थैलेसीमिया जैसे गंभीर रक्त रोग संबंधी समस्या के प्रति जागरूकता और उपचार सहायता हेतु समय-समय पर जांच व परामर्श शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट sewabhartidelhi.org या info@sewabhartidelhi.org पर ई-मेल करके संपर्क कर सकते हैं।
- *द सेकंड इनिंग होम* बेसहारा और निराश्रित बुजुर्गों के लिए समर्पित एक सेवा परियोजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें सम्मानित, सुरक्षित और स्नेहपूर्ण जीवन प्रदान करना है। यहां बुजुर्गों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक आवास, पौष्टिक व संतुलित भोजन की नियमित व्यवस्था रहती है। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट durgaoldagehome.com/home-1 या 9999662245 पर संपर्क कर सकते हैं।

अमेरिका के साथ 90 अरब डॉलर के पार पहुंचेगा भारत का व्यापार अधिशेष

एसबीआई की रिपोर्ट...टैरिफ कटौती भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजारों में कब्जा जमाने का सुनहरा मौका

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ में कटौती निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का सुनहरा मौका है। साथ ही, यह व्यापार अधिशेष के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है।

एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, टैरिफ कटौती के बाद निर्यात में तेज वृद्धि और अमेरिकी बाजारों में अधिक आयात से भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) सालाना 90 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है। रिपोर्ट एक दिलचस्प आंकड़े की ओर इशारा कर रही है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले टॉप-15 उत्पादों में सालाना 97 अरब डॉलर के अतिरिक्त निर्यात की क्षमता है। अगर अन्य उत्पादों को जोड़ लिया जाए, तो यह आंकड़ा आसानी से 100 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024-25 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 40.9 अरब डॉलर था, जिसके अब दोगुना से ज्यादा होने की उम्मीद है। इसका भारतीय जीडीपी पर करीब 1.1 फीसदी सकारात्मक असर पड़ सकता है। 2025-26 के पहले नौ माह में व्यापार अधिशेष 26 अरब डॉलर रहा है।

55 अरब डॉलर बढ़ सकता है अमेरिका से आयात

*व्यापार समझौते की घोषणा के तहत भारत ने सभी अमेरिकी औद्योगिक सामान और कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर टैरिफ कम करने या खत्म करने पर सहमति जताई है। **वहीं, कुछ कमोडिटीज को छोड़कर भारत के आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी पहले से ही 20-40 फीसदी के बीच है।** टैरिफ कम होने पर इसके और बढ़ने का अनुमान है। इससे अमेरिका से आयात में 55 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है।*

तीन अरब डॉलर से अधिक बचा सकता है भारत

भारत ने अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदने की सहमति जताई है। कुछ क्षेत्रों में तो अमेरिका पहले से ही हावी है। जैसे... बादाम के मामले में भारत के कुल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 90 फीसदी है। **टैरिफ कम होने से भारत सिर्फ बादाम आयात पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 10-15 करोड़ डॉलर बचा सकता है।**

■ इसके अलावा, अन्य उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ शून्य होने या आयात शुल्क में कमी के चलते भारत विदेशी मुद्रा भंडार में तीन अरब डॉलर की बचत कर सकता है। **आयात सब्स्टिट्यूशन के साथ यह बचत और भी ज्यादा हो सकती है।**

अमेरिका के लिए भी एक बड़ा बाजार है भारत

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अमेरिकी उत्पादों के लिए भी बड़ा बाजार उपलब्ध है। वर्तमान में भारत के कुल आयात में अमेरिका का हिस्सा सिर्फ 7 फीसदी है, जबकि सेवाओं के मामले में यह 15 फीसदी है। **इससे पता चलता है कि भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा पोटेंशियल मार्केट बना हुआ है। यानी अमेरिकी कंपनियों के पास भारत में विस्तार करने का जबरदस्त मौका है।** सेवाओं को छोड़कर अमेरिका हर साल भारत को 50 अरब डॉलर से ज्यादा निर्यात कर सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड : छह वर्षों तक बढ़ सकती है कर्ज अवधि

नई दिल्ली। आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन और एकीकरण के लिए बृहस्पतिवार को मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य कवरेज का विस्तार करना, परिचालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण और कृषि क्षेत्र की उभरती जरूरतों का ध्यान रखना है।

आरबीआई ने केसीसी ऋण की स्वीकृति और पुनर्भुगतान कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए फसल सत्रों की अवधि को मानकीकृत करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत, कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों को 12 महीने के चक्र और लंबी अवधि वाली फसलों को 18 माह के चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है। **लंबी अवधि की फसलों के चक्र के अनुरूप कर्ज अवधि तय करने के लिए केसीसी की कुल अवधि छह वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है।**

आरबीआई ने संशोधित मसौदा किया जारी, हिताधारकों से 6 मार्च तक मांगे गए हैं सुझाव

मसौदे में केसीसी के तहत निकासी सीमा को हर फसल सत्र के लिए फसल की अनुमानित लागत के साथ समायोजित करने का सुझाव दिया गया है, ताकि किसानों को वास्तविक लागत के अनुरूप पर्याप्त ऋण मिल सके। मिट्टी जांच, वास्तविक समय में मौसम पूर्वानुमान और जैविक-उत्तम कृषि पद्धतियों के प्रमाणन जैसे तकनीकी खर्चों को भी शामिल किया गया है। ये खर्च कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए वर्तमान में स्वीकृत 20 फीसदी अतिरिक्त घटक के भीतर रखे जाएंगे। एजेंसी

न्यूज डायरी

केंद्र ने 75,504 करोड़ की प्रतिभूतियां वापस खरीदी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को एक स्विच ऑक्शन के जरिये आरबीआई से 75,504.43 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की वापस खरीदारी की और 69,436.15 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किए। वापस खरीदी गई प्रतिभूतियां अगले वित्त वर्ष 2026-27 में मैच्योर होने वाले शेड्यूल्ड बॉन्ड का हिस्सा थीं। अगले वित्त वर्ष में 5.47 लाख करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड मैच्योर होने वाले हैं। एजेंसी

वैकल्पिक कोषों में 1.14 लाख करोड़ का निवेश

नई दिल्ली। घरेलू निवेशकों ने सितंबर, 2025 तक 18 महीनों में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में 1.14 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह उद्योग के लिए स्थानीय पूंजी आधार में आई मजबूती को दर्शाता है। क्रिसिल और ऑएस्टर ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर, 2025 तक श्रेणी-1 और श्रेणी-2 एआईएफ पूंजी में घरेलू निवेशकों का हिस्सा बढ़कर 55.3 फीसदी हो गया जो मार्च, 2024 में 50.3 फीसदी था। एजेंसी

एचयूएल को 6,603 करोड़ रुपये का मुनाफा

नई दिल्ली। हिंदुस्तान यूनिलीवर लि. (एचयूएल) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ दोगुना होकर 6,603 करोड़ पहुंच गया। कंपनी की सीईओ एवं एमडी प्रिया नायर ने कहा, 2025-26 की दिसंबर तिमाही में आइसक्रीम व्यवसाय को क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) लि. को बेचने से लाभ में यह वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में अन्य राजस्व सहित कंपनी की कुल आय 5.01 फीसदी बढ़कर 16,580 करोड़ रही। एजेंसी

डिजिटल भुगतान में पहली छमाही में भी तेजी

मुंबई। देश में डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ने का सिलसिला पहली छमाही यानी अप्रैल-सितंबर, 2025 में भी जारी रहा। इससे आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर, 2025 में बढ़कर 516.76 पर पहुंच गया, जो सितंबर, 2024 में 465.33 और मार्च, 2025 में 493.22 पर था। देशभर में डिजिटल भुगतान के प्रसार और दायरे को मापने वाला यह सूचकांक जनवरी, 2021 से प्रकाशित हो रहा है। एजेंसी

2,994 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी लेगी इरेडा

नई दिल्ली। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) इक्विटी शेयर जारी कर 2,994 करोड़ जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। यह मंजूरी पात्र संस्थागत खरीदारों समेत अन्य निवेशकों से डाक के जरिये ली जाएगी। नोटिस के अनुसार, इस निर्गम से कंपनी में भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता निर्गम के बाद की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 3.76 फीसदी से अधिक नहीं घटेगी। एजेंसी

सरकार ने जारी किए नई शृंखला के तहत खुदरा महंगाई के आंकड़े, आधार वर्ष में संशोधन

खाद्य वस्तुओं और सोने-चांदी की कीमतों में उछाल से खुदरा महंगाई 2.75 फीसदी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। खाने-पीने की वस्तुओं और सोने-चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में उछाल से नई शृंखला के तहत जारी खुदरा महंगाई जनवरी, 2026 में बढ़कर 2.75 फीसदी पहुंच गई। नई शृंखला में आधार वर्ष को संशोधित कर 2024 किया गया है। जनवरी लगातार 12वां महीना है, जब खुदरा महंगाई आरबीआई के चार फीसदी के लक्ष्य से नीचे रही है।

2012 को आधार वर्ष मानने वाली पुरानी शृंखला के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई जनवरी, 2025 में 4.26 फीसदी और दिसंबर, 2025 में 1.33 फीसदी रही थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई दर यानी खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने 2.13 फीसदी रही। वहीं, आवासीय क्षेत्र में महंगाई की दर 2.05 फीसदी दर्ज की गई। उधर, ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई की दर 2.73 फीसदी रही, जो 2.77 फीसदी के शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में मामूली कम है। पुरानी शृंखला पर आधारित खुदरा महंगाई के अंतिम आंकड़े दिसंबर, 2025 के लिए जारी हुए थे।

इन राज्यों में सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति

तेलंगाना	4.92%
अंडमान-निकोबार	4.27%
केरल	3.67%
तमिलनाडु	3.36%
पुडुचेरी	3.39%

हिमाचल प्रदेश : 2.92%, पंजाब : 2.71%, उत्तर प्रदेश : 2.67%, हरियाणा : 2.55%, चंडीगढ़ : 2.33%, दिल्ली : 2.15%, उत्तराखंड : 2.15%, जम्मू-कश्मीर : 1.34%।

पांच वस्तुओं की दर सबसे कम

आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में जिन पांच खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर सबसे कम रही, उनमें लहसुन, प्याज, आलू, अरहर, तुअर दाल और मटर शामिल हैं।

■ चांदी के आभूषण, सोना, हीरा, प्लैटिनम के आभूषण, टमाटर, नारियल खोपरा व नारियल तेल की महंगाई दर सबसे ज्यादा रही।

नई शृंखला की खास बातें

■ वस्तुओं की संख्या 259 से बढ़ाकर 308 और सेवाओं की 40 से बढ़ाकर 50 की गई है, ताकि मूल्य स्थिति की बेहतर तस्वीर पेश हो।

■ ग्रामीण आवास, ऑनलाइन मीडिया सेवा प्रदाता/स्ट्रीमिंग सेवाएं, मूल्यवर्धित दूध उत्पाद, जौ एवं उत्पाद, पेन-ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अटेंडेंट, बेबीसिटर और व्यायाम उपकरणों को शामिल किया गया है।

■ वीसीआर/वीसीडी/डीवीडी प्लेयर, लोगों को काम पर रखने की लागत, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सेकंड हैंड कपड़े, सीडी/डीवीडी ऑडियो-वीडियो कैसेट और कॉयर को हटा दिया गया है।

■ शहरी इलाकों में बाजारों की संख्या 1,114 से बढ़ाकर 1,407 की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 1,181 से बढ़कर 1,465 पहुंच गई है। शहरों की संख्या भी 310 से 40 फीसदी बढ़ाकर 434 की गई है।

■ आधार को 2012 से 2024 तक घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24 का उपयोग कर संशोधित किया गया है।

खाद्य-पेय पदार्थों की हिस्सेदारी घटी

नई शृंखला में खाद्य एवं पेय पदार्थों की हिस्सेदारी घटकर 36.75 फीसदी रह गई है, जो पुरानी शृंखला में 45.86 फीसदी थी। इसके बावजूद खुदरा महंगाई में इसका भारांश सबसे अधिक है।

■ कपड़ा-फुटवियर की हिस्सेदारी 6.5 फीसदी से घटाकर 6.4 फीसदी की गई है।

■ आवासीय, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन की कुल महंगाई में हिस्सेदारी 16.9 फीसदी से बढ़ाकर 17.7 फीसदी की गई है।

■ स्वास्थ्य, यातायात, मनोरंजन और पर्सनल केयर की भी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है।

आईटी शेयरों में बिकवाली से 559 अंक टूटा सेंसेक्स, 84,000 से नीचे

■ अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद कमजोर पड़ने का असर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर पड़ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संभावित व्यवधान की आशंकाओं के बीच आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के चलते बृहस्पतिवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट में बंद हुए।

सेंसेक्स 558.72 अंक टूटकर 84,000 के नीचे 83,674.92 पर बंद हुआ। दिन में एक समय यह 716.97 अंक गिरकर 83,516.67 तक आ गया था। निफ्टी भी 146.65 अंक लुढ़ककर 25,807.20 पर बंद हुआ। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी 2.50 लाख करोड़ रुपये घटकर 472.48 लाख करोड़ रुपये रह गई।

सेंसेक्स की 30 में से 17 कंपनियों के शेयर गिरावट में रहे। सबसे ज्यादा दबाव आईटी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला। टेक महिंद्रा सर्वाधिक 5.99 फीसदी गिरावट में बंद हुआ। **ट्रेंट, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस समेत 13 शेयर 3.17 फीसदी तक बढ़त में रहे।**

बीएसई मिडकैप सूचकांक में 0.48 फीसदी और स्मॉलकैप में 0.28 फीसदी गिरावट रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 108.42 करोड़ के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 276.85 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की।

आईटी इंडेक्स : 5.40% तक टूटे

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, एआई में ताजा अपडेट से सेवा क्षेत्र में काम करने वाली आईटी कंपनियों के राजस्व और मूल्यांकन पर दबाव बढ़ने की आशंका से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। इससे निफ्टी आईटी इंडेक्स 5 फीसदी से अधिक टूट गए, जो करीब 10 फीसदी का निचले स्तर है।

10 महीने के निचले स्तर पर

सेक्टोरल इंडेक्स में फोकस्ड आईटी सेगमेंट 5.40 फीसदी टूट गया, जबकि आईटी में भी 5.29 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

■ आईटी कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयर बीएसई पर सबसे ज्यादा 5.99 फीसदी टूट गए।

■ **इन्फोसिस** में 5.79 फीसदी, **टीसीएस** में 5.41% और **एचसीएल टेक** में 4.84 फीसदी गिरावट रही।

सख्ती : अब ग्राहकों से दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे कर्ज वसूली एजेंट

आरबीआई ने जारी किया ड्राफ्ट सर्कुलर...वसूली एजेंट और ग्राहक के बीच होने वाली बातचीत की करनी होगी रिकॉर्डिंग

मुंबई। बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य वित्तीय संस्थानों के कर्ज वसूली एजेंस अब ग्राहकों से बदतमीजी या दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने बकाया कर्ज वसूली के लिए एजेंटों का इस्तेमाल करने वाले कर्जदाता वित्तीय संस्थानों पर सख्ती बरतते हुए नियमों का मसौदा जारी किया है। इसका मकसद कर्ज चुकाने में असमर्थ या देरी करने वाले ग्राहकों को अनुचित दबाव से बचाना है। बृहस्पतिवार को जारी मसौदे में कहा गया है कि बकाया चुकाने में देरी करने वाले ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी अनिवार्य रूप से गोपनीय रखनी होगी। साथ ही, कर्जदारों को किए जाने वाले सभी फोन कॉल की अनिवार्य रूप से रिकॉर्डिंग भी करनी होगी। एजेंसी

ग्राहकों की निजता के उल्लंघन से बचें एजेंट

मसौदे में कहा गया है कि वलूसी एजेंट कर्जदारों की निजता का उल्लंघन न करें। शादी, त्योहार और शोक जैसे अनुचित मौकों पर ग्राहकों से मिलने और कॉल करने से बचें। वित्तीय संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि वसूली एजेंट ग्राहकों से कठोर व्यवहार न करें और गाली-गलौज से बचें। वसूली एजेंटों के कर्ज लेने वाले या गारंटर के रिश्तेदारों से भी संपर्क करने पर रोक लगाई गई है।

वित्तीय संस्थानों को वसूली एजेंट की गतिविधियों पर रखनी होगी नजर

आरबीआई ने कहा, बैंक यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली के लिए नियुक्त एजेंसी अपने प्रतिनिधियों या कर्मचारियों की पृष्ठभूमि का सत्यापन नियुक्ति से पहले और बाद में भी तय अंतराल पर करती रहे। उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखे।

प्रशिक्षण भी जरूरी

■ कर्ज बकाया से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में बैंक को अपने कर्मचारी या वसूली एजेंट को मामला सौंपने में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी।

■ आरबीआई इस पर भी विचार कर रहा है कि वसूली एजेंटों के लिए भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान से संचालित ऋण वसूली प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाए।

रोल्स-रॉयस भारत में कारोबार का करेगी विस्तार, 10,000 लोगों को देगी नौकरी

नई दिल्ली। ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनी रोल्स-रॉयस ने भारत में रक्षा, नागरिक उड्डयन और ऊर्जा के क्षेत्र में कारोबार विस्तार करने की घोषणा की है। इससे देश में 10 हजार लोगों को रोजगार और कंपनी की आपूर्ति शृंखला सोर्सिंग में 10 गुना की बढ़ोतरी का अनुमान है। वर्तमान में चार हजार से अधिक भारतीय कंपनी के विभिन्न उपक्रमों में कार्यरत हैं।

रॉल्स-रॉयस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तूफान एर्गिनबिलगिक ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में देश के विकास और आत्मनिर्भरता को समर्थन देने की योजनाओं पर चर्चा हुई।

एर्गिनबिलगिक ने कहा, हम आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। स्थानीय साझेदारी को मजबूत करके कौशल और प्रतिभा विकास में निवेश कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान देंगे। कंपनी भारत में कई पहल शुरू करने पर विचार कर रही है, जिनमें तीनों सेनाओं के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट इंजन का विकास भी शामिल हैं। एजेंसी

अगले सप्ताह जारी होंगे निर्यात प्रोत्साहन मिशन के आठ घटक

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन के आठ घटक अगले सप्ताह पेश कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में 45,000 करोड़ रुपये से अधिक के संयुक्त परिव्यय वाली दो योजनाओं निर्यात प्रोत्साहन मिशन (25,060 करोड़ रुपये) और ऋण गारंटी योजना (20,000 करोड़ रुपये) को मंजूरी दी थी।

अधिकारी ने बताया, अब हम आठ घटकों को शुरू करने पर काम कर रहे हैं। इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। अगले सप्ताह इसकी घोषणा होगी। ये घटक ई-कॉमर्स, वेयरहाउसिंग और फैक्टरिंग सेवाओं जैसे मुद्दों से जुड़े होंगे।

निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) दो एकीकृत उप-योजनाओं निर्यात प्रोत्साहन (वित्तीय सहायक) और निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सहायक) के माध्यम से संचालित होता है। यह मिलकर वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता से जुड़े पहलुओं पर काम करते हैं। सरकार ने दिसंबर 2025 में 4,531 करोड़ रुपये की अंतर्गत बाजार पहुंच सहायता योजना शुरू की थी। एजेंसी

घर में पकाई जाने वाली शाकाहारी थाली के दाम दो फीसदी तक घटे

घर में पकाई जाने वाली शाकाहारी थाली के दाम जनवरी, 2026 में मासिक और सालाना आधार पर दो फीसदी तक घट गए। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रोटी राइस रेट रिपोर्ट के मुताबिक, प्याज, आलू और दालों की कीमतों में नरमी से राहत मिली है। हालांकि, टमाटर में तेज उछाल ने कीमतों में गिरावट को सीमित कर दिया। मांसाहारी थाली 7 फीसदी तक सस्ती हुई है। ब्यूरो

ऐसे घटी कीमत

28.5 रुपये रह गई शाकाहारी थाली की कीमत जनवरी में

29.1 रुपये थी दिसंबर, 2025 में कीमत, जनवरी 2025 में 28.7 रुपये रही थी

■ सालाना आधार पर एक फीसदी व मासिक आधार पर दो फीसदी घटे दाम

इसलिए मिली राहत

27% सस्ता हो गया प्याज एक साल पहले के मुकाबले

अधिक उपलब्धता और कम निर्यात का असर

23% घट गए आलू के दाम उच्च आधार प्रभाव के कारण

14% की गिरावट आई दालों की कीमतों में भंडार बढ़ने से

इन वजहों से कम घटे दाम

50% महंगा हुआ टमाटर एक साल में

04% बढ़ गए खाद्य तेल के दाम कम आपूर्ति के चलते

06% महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलिंडर

39% कम आवक के कारण जनवरी, 2025 के 31 रुपये से बढ़कर 46 रुपये प्रति किलो पहुंच गई कीमत पिछले माह

मांसाहारी थाली

07% घट गई कीमत एक साल पहले के मुकाबले

चिकन 13% सस्ता होने से घटे दाम

50% हिस्सा है चिकन की मांसाहारी थाली की कीमत में

बैंक बीमा, म्यूचुअल फंड और अन्य उत्पाद बेचते वक्त नहीं अपना सकते डार्क पैटर्न

अजीत खरे

नई दिल्ली। बैंक व वित्तीय संस्थाएं बीमा, कर्ज, म्यूचुअल फंड व अन्य उत्पाद बेचते वक्त डार्क पैटर्न नहीं अपना सकते हैं। इसके तहत उत्पाद या सेवा बेचते वक्त ग्राहकों की स्वतंत्र पसंद को प्रभावित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। बैंक व्यावसायिक लाभ के लिए उपभोक्ताओं के मन में डर, शर्म, उपहास या अपराधबोध की भावना उत्पन्न करने वाले विज्ञापन या संदेश अपनी वेबसाइट व एप में नहीं देंगे।

रिजर्व बैंक ने बैंकों से इस पर सख्ती करने के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया गया है। इसमें रिजर्व बैंक ने डार्क पैटर्न की सूची में बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, सब्सक्रिप्शन ट्रैप व फोर्स्ड एक्शन जैसी प्रवृत्तियों को भी कार्रवाई के दायरे में ला दिया है। बास्केट स्नीकिंग के तहत बैंक ग्राहक की ओर से डिफॉल्ट रूप से ऋण आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन धोखाधड़ी सुरक्षा या लोन प्रोटेक्शन बीमा स्वतः जोड़ देते हैं।

ग्राहकों को ऐसे करते है भ्रमित

कन्फर्म शेमिंग में ग्राहक से कहा जाता है कि क्या आप वाकई विशेष ऑफर और अपडेट मिस करना चाहते हैं या बेहतरीन डील्स के बारे में अनजान बने रहने पसंद करते हैं? अगर ग्राहक प्रीमियम अकाउंट में अपग्रेड न करे, तो संदेश भेजा जाता है, नहीं धन्यवाद, मुझे अतिरिक्त सुरक्षा और लाभ नहीं चाहिए। जिससे यह लगे कि ग्राहक गलत निर्णय ले रहा है। फोर्स्ड एक्शन में ग्राहक मोबाइल बैंकिंग में लॉग-इन के बाद एग्जिट बटन दबाने पर भी पर्सनल लोन सेक्शन में पहुंच जाता है।

बचत-निवेश | घरेलू शेयर बाजार के खराब प्रदर्शन के बीच निवेशकों ने बिजनेस साइकिल फंड्स की ओर किया रुख

बिजनेस साइकल फंड्स ने एक साल में दिया 18 फीसदी से ज्यादा रिटर्न

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार के खराब प्रदर्शन के बावजूद पिछले एक साल में बिजनेस साइकल फंडों ने 18 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। इन फंडों ने तीन और पांच साल में भी बीएसई सेंसेक्स और एनएशई निफ्टी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। ये फंड मुख्य रूप से ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होते हैं और व्यावसायिक चक्र पर आधारित निवेश का तरीका अपनाते हैं।

वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बिजनेस साइकल फंड ने एक साल में 18.12 फीसदी और तीन साल में 22.82 फीसदी का रिटर्न दिया है। कोटक के फंड ने 10.48 और 17.80 फीसदी, टाटा की स्कीम ने 6.23 और 17.28 फीसदी और एचडीएफसी की इसी स्कीम ने 8.59 और 14.97 फीसदी का रिटर्न दिया है। बिजनेस साइकल फंड इसने विभिन्न बाजार स्थितियों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। का उद्देश्य व्यावसायिक चक्र के मौजूदा चरण के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में अवसरवादी रूप से निवेश करना है, ताकि दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि हासिल की जा सके। आईप्रू की इस स्कीम को पांच साल पूरे हो गए हैं। उस समय एक लाख का निवेश अब 2.51 लाख रुपये हो गया है। निफ्टी-500 टीआरआई में यही रकम 2.06 लाख रुपये हुई है। ब्यूरो

निवेश पर रिटर्न देने के मामले में भी आगे

एसआईपी के प्रदर्शन की बात करें तो शुरुआत से ही हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करने पर 31 जनवरी, 2026 तक कुल रकम बढ़कर लगभग 9.74 लाख रुपये हो गई है यानी 18.47% की दर से सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न मिला है। वास्तवित निवेश 6.10 लाख रुपये किया गया है। निफ्टी-500 टीआआई में रिटर्न 13.11 फीसदी रहा। यह योजना एक टॉप-डाउन निवेश दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, जो विकास, महंगाई जैसे संकेतकों से निर्देशित है।

आर्थिक सुधार वाले क्षेत्रों में 80 फीसदी निवेश

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के मुख्य निवेश अधिकारी एस. नरेन कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से चक्रीय है। व्यावसायिक चक्र के विकास के साथ इक्विटी नेतृत्व में बदलाव होता रहता है। 31 जनवरी, 2026 तक इस स्कीम का 80 फीसदी निवेश उन क्षेत्रों में हुआ है जिनसे आर्थिक गतिविधियों में सुधार से लाभ होने की उम्मीद है। वित्तीय क्षेत्र मुख्य है जिन्हें ऑटोमोबाइल, निर्माण व चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश का समर्थन प्राप्त है।

चिंतन

लोकतांत्रिक सरकार संबंध सुधारने पर दे सकती है जोर

बांग्लादेश में संपन्न हुए 13वें संसदीय चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया भर नहीं हैं, बल्कि ये दक्षिण एशिया की कूटनीतिक दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव भी हैं। चुनाव परिणामों को लेकर भले ही विभिन्न दलों और पर्यवेक्षकों के बीच मतभेद हों और उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ रहे हों, लेकिन यह निर्विवाद है कि ढाका की सत्ता में बैठने वाली नई सरकार का रुख भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जो दोनों देशों को सुरक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और रणनीतिक दृष्टि से गहराई से जोड़ती है। ऐसे में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता और उसकी विदेश नीति का स्वरूप भारत के राष्ट्रीय हितों से सीधे जुड़ा हुआ है। चुनाव से पहले आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) दोनों ने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों की बात कही थी। यह संकेत आशावादी है। यदि लोकतांत्रिक ढंग से गठित नई सरकार क्षेत्रीय सहयोग और संतुलन की नीति अपनाती है, तो हाल के वर्षों में आई कूटनीतिक दूरी कम हो सकती है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों तथा भारत के साथ रिश्तों में आई ठंडक ने नई दिल्ली की चिंता बढ़ाई थी। ऐसे माहौल में लोकतांत्रिक जनादेश से बनी सरकार यदि संतुलित विदेश नीति अपनाती है, तो यह दोनों देशों के लिए राहत की बात होगी। यह भी ध्यान रखना होगा कि बांग्लादेश में चीन की आर्थिक उपस्थिति लगातार बढ़ी है। बुनियादी ढांचे, बंदरगाह, ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में चीन की सक्रियता ने ढाका को नए विकल्प दिए हैं। पाकिस्तान के साथ भी ऐतिहासिक और राजनीतिक समीकरण समय-समय पर चर्चा में आते रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में भारत के लिए चुनौती यह है कि वह प्रतिस्पर्धा के बजाय विश्वास और विकास साझेदारी के माध्यम से संबंधों को मजबूत करे। भारत को बांग्लादेश के आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और जन-जन के संपर्क को प्राथमिकता देकर रिश्तों को स्थायी आधार देना होगा। भारत की ओर से आई आधिकारिक प्रतिक्रिया परिपक्व और संतुलित रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पहले चुनाव परिणामों का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद जनादेश की प्रकृति को देखते हुए आगे की रणनीति तय होगी। यह बयान केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत पड़ोसी देशों में स्थिर और लोकतांत्रिक शासन को अपने हितों के अनुरूप मानता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते केवल रणनीतिक समीकरण नहीं हैं, वे साझा इतिहास, संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका ने दोनों देशों के बीच विश्वास की मजबूत नींव रखी थी। हाल के वर्षों में व्यापार, ऊर्जा सहयोग, सीमा प्रबंधन, रेल और जलमार्ग संपर्क जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन उपलब्धियों को राजनीतिक उतार-चढ़ाव का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। नई लोकतांत्रिक सरकार के सामने चुनौती होगी कि वह घरेलू राजनीतिक स्थिरता कायम रखते हुए संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति अपनाए। भारत को भी चाहिए कि वह बड़े भाई की छवि से आगे बढ़कर समानता और सम्मान के आधार पर संबंधों को विकसित करे। लोकतंत्र की मजबूती और पड़ोसी सहयोग ही क्षेत्र को स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकते हैं।

मुद्दा
महेन्द्र तिवारी

विवाद की जड़ बनी अप्रकाशित आत्मकथा

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा की पीडीएफ कॉपी के सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रसार को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह मामला किसी अपराध या घोटाले से जुड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मकथा से संबंधित है, जो अभी प्रकाशित भी नहीं हुई और व्यापक रूप से पढ़ी जा रही है। प्रश्न यह नहीं रह गया कि पुस्तक लीक कैसे हुई, बल्कि यह बन गया कि वह अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी। जांच और प्रतिबंध के रास्ते ने न केवल लेखक और प्रकाशक को असमंजस में डाला है, बल्कि पाठकों को भी अधूरी और असंतुलित जानकारी के भरोसे छोड़ दिया है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की पीडीएफ कॉपी के सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रसार को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह मामला किसी अपराध या घोटाले से जुड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मकथा से संबंधित है, जो अभी औपचारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं हुई और फिर भी व्यापक रूप से पढ़ी जा रही है। पूर्व थलसेना प्रमुख नरवणे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की डिजिटल प्रति अचानक विभिन्न संदेश माध्यमों और सामाजिक मंचों पर फैल गई। देखते ही देखते यह रचना केवल सैन्य इतिहास की किताब न रहकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई।

प्रश्न यह नहीं रह गया कि पुस्तक लीक कैसे हुई, बल्कि यह बन गया कि वह अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी। यह आत्मकथा चार दशकों से अधिक लंबे सैन्य जीवन का विवरण देती है। एक युवा अधिकारी के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती से लेकर देश की थलसेना के सर्वोच्च पद तक की यात्रा इसमें दर्ज है। इसमें पूर्वी सीमा पर हुए टकराव, पश्चिमी मोर्चे पर तनाव, पड़ोसी देशों के साथ संघर्षविराम और एक भीषण वैश्विक महामारी के दौरान सेना की भूमिका जैसे प्रसंग शामिल हैं। ऐसे समय में जब देश का सैन्य इतिहास अक्सर आधिकारिक वक्तव्यों और संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित रह जाता है, यह पुस्तक घटनाओं के भीतर झांकने का अवसर देती है। शायद यही कारण है कि इसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। प्रकाशन की प्रक्रिया सामान्य नहीं रही। पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, अग्रिम आदेश भी लिए गए, परंतु अचानक सब कुछ रोक दिया गया। पाठकों को धन वापस कर दिया गया और कहा गया कि आवश्यक स्वीकृतियां लंबित हैं। पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा लिखी जाने वाली स्मृतियों के लिए रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, यह कोई नई बात नहीं है। परंतु जब पुस्तक के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों से यह सामने आया कि उसी अवधि में दर्जनों अन्य पुस्तकों को अनुमति मिल चुकी है और केवल यही एक रचना अटकी हुई है, तो संदेह स्वाभाविक हो जाता है। लेखक स्वयं कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया था और उसे प्रकाशक को सौंप दिया था।

अनुमति प्राप्त करना उनका दायित्व नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुस्तक की सामग्री उनकी अपनी लिखी हुई है और उसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी नहीं है। यही नहीं, पुस्तक के मसौदे को पहले ही कई वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों ने पढ़ा था और उसकी सराहना भी की थी। इन प्रतिक्रियाओं से यह संकेत मिलता है कि सामग्री न तो मनगढ़ंत है और न ही हल्की। इसके बावजूद पुस्तक पर चुप्पी बनी रही। इस बीच कुछ समाचार माध्यमों ने इसके अंशों के आधार पर लेख प्रकाशित किए। उन लेखों में सीमा पर हुए संकटों के दौरान लिए गए राजनीतिक और सैन्य निर्णयों का उल्लेख था। संसद में जब इन संदर्भों का उपयोग करने की कोशिश की गई तो भारी हंगामा हुआ और चर्चा रोक दी गई। इसके तुरंत बाद वही डिजिटल प्रति, जिसे अब तक केवल सीमित लोगों ने देखा था, व्यापक रूप से फैलने लगी। यह एक अजीब स्थिति थी, जिसमें एक पुस्तक आधिकारिक

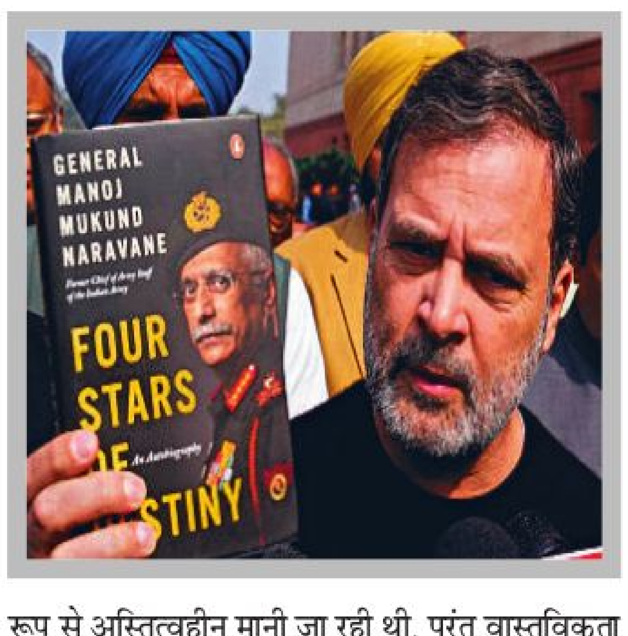

रूप से अस्तित्वहीन मानी जा रही थी, परंतु वास्तविकता में हजारों पाठकों तक पहुंच चुकी थी। अब जांच का केंद्र यह है कि इस अनधिकृत प्रसार के लिए कौन जिम्मेदार है। कानून की दृष्टि से यह कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि अप्रकाशित सामग्री को बिना अनुमति साझा किया गया। यदि यह माना जाए कि पुस्तक में संवेदनशील सैन्य जानकारियां हैं, तो उस पर गोपनीयता से जुड़े कानून भी लागू हो सकते हैं। यहां एक गहरा प्रश्न छिपा है। क्या जांच का उद्देश्य वास्तव में कानून का पालन कराना है या फिर उन तथ्यों को नियंत्रित करना है जो असुविधाजनक साबित हो सकते हैं। इस आत्मकथा में जिन घटनाओं का उल्लेख है, वे हाल के वर्षों की सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय घटनाओं में से हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में हुई झड़पों में देश ने अपने जवान खोए, परंतु उन घटनाओं के बारे में आधिकारिक विवरण सीमित रहा। सरकार की ओर से एक विशेष प्रकार का आख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसमें दृढ़ता और सफलता पर जोर था।

यदि किसी पूर्व थलसेना प्रमुख की पुस्तक उस आख्यान से अलग तस्वीर पेश करती है, तो स्वाभाविक है कि वह राजनीतिक रूप से असहज कर सकती है। क्या असहजता ही किसी रचना को रोकने का पर्याप्त कारण हो सकती है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ केवल सामान्य नागरिकों तक सीमित नहीं है। जिन लोगों ने राज्य की सर्वोच्च जिम्मेदारियां निभाई हैं, उनका अनुभव और दृष्टिकोण भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर विषय है और किसी भी प्रकार की जानकारी का प्रकाशन सावधानी से होना चाहिए, परंतु सुरक्षा और सेंसरशिप के बीच की रेखा बहुत महीन होती है।

जब सुरक्षा के नाम पर हर असुविधाजनक प्रश्न को दबाया जाने लगे, तब यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में न तो लेखक ने अपनी बात से पीछे हटने का प्रयास किया और न ही प्रकाशक ने यह कहा कि सामग्री गलत है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्या सामग्री में नहीं, बल्कि उसके सार्वजनिक होने में है। यही विरोधाभास इस पूरे विवाद को और गहरा बनाता है। डिजिटल युग में किसी रचना को पूरी तरह रोक पाना लगभग असंभव है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि प्रतिबंध और देरी कभी-कभी विपरीत प्रभाव डालते हैं। जिस पुस्तक को कुछ कार्यालयी फाइलों में दबाकर रखा गया था, वह अब कहीं अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है, वह भी बिना किसी आधिकारिक संदर्भ और विमर्श के। इससे गलत व्याख्याओं और अफवाहों की संभावना भी बढ़ जाती है। बेहतर यह होता कि पुस्तक को आवश्यक संपादन और स्पष्ट चेतावनियों के साथ प्रकाशित होने दिया जाता, ताकि पाठक उसे पूरे संदर्भ में समझ सकें। जांच और प्रतिबंध के रास्ते ने न केवल लेखक और प्रकाशक को असमंजस में डाला है, बल्कि पाठकों को भी अधूरी और असंतुलित जानकारी के भरोसे छोड़ दिया है।

यह प्रकरण केवल एक आत्मकथा का नहीं है। यह उस बड़े संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें राज्य की शक्ति और नागरिक समाज की जिज्ञासा आमने-सामने खड़ी होती हैं। इतिहास बताता है कि सत्य को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। वह कभी दस्तावेज के रूप में, कभी स्मृति के रूप में और कभी डिजिटल प्रति के रूप में सामने आ ही जाता है। प्रश्न केवल यह है कि क्या हम उसे खुली बहस और परिपक्व संवाद के साथ स्वीकार करेंगे या डर और नियंत्रण के माध्यम से उसे और रहस्यमय बना देंगे। जनरल नरवणे की आत्मकथा आज भले ही औपचारिक रूप से प्रकाशित न हो, परंतु उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि कहानियां केवल अनुमति से नहीं, आवश्यकता से जीवित रहती हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

विश्व रेडियो दिवस
बाल मुकुन्द ओझा

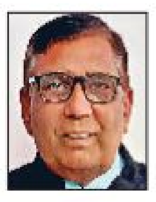

मन की बात ने बढ़ाया रेडियो का मान-सम्मान

विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। कोई माने या न माने, मगर यह बिलकुल सच है कि भारत में अपनी पहचान खोते जा रहे रेडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम ने पुनर्जीवित कर नया जीवनदान दिया है। मोदी के लोकप्रिय शो 'मन की बात' ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ा दी है। एक वक्त था जब रेडियो पर यह आकाशवाणी है, ये शब्द सुनते ही बच्चे से बुजुर्ग तक रेडियो को घेर कर खड़े हो जाते थे। यह हर कोई जानता है कि रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए लाखों-करोड़ों लोगों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत में अपनी पहचान खोते जा रहे रेडियो को अपने नवाचार कार्यक्रम के माध्यम से नयी पहचान और जीवनदान देने का श्रेय निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है।

आठवें दशक तक या यूं कहें कि दूरदर्शन के आगमन तक रेडियो ही शिक्षा, संचार और मनोरंजन के क्षेत्र की सिरमौर था। उस दौरान घर-घर में ही नहीं अपितु हर हाथ में रेडियो था और लोग इससे चिपके रहते थे। हर प्रकार की सूचना का संवाहक था रेडियो। 1980 के बाद संचार के आधुनिक साधनों के प्रादुर्भाव के साथ रेडियो का प्रभाव घटता गया। लोगों ने रेडियो के स्थान पर टीवी को अपनाना शुरू कर दिया। इसी बीच 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 'मन की बात' नामक एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम शुरू हुआ। इसी नवाचार के साथ रेडियो का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। दूरदर्शन के प्रादुर्भाव से पूर्व यानि अस्सी के दशक तक रेडियो पर सुनाई देने वाली यह आवाज संचार के आधुनिक साधनों के बीच गायब सी हो गई थी। पहले भारतीय

प्रसारण सेवा, फिर आल इंडिया रेडियो और इसके बाद आकाशवाणी के रूप में रेडियो अस्तित्व में रहा। दूरदर्शन के बढ़ते प्रभाव ने इसकी उपयोगिता पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया, रही सही कसर निजी चैनलों और मोबाइल ने पूरी कर दी। मगर हाल के वर्षों में जहां लोगों में रेडियो की चाह बढ़ी है, वहीं इसकी बिक्री भी तेज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ा दी है। कह सकते हैं कि इसे नया जीवन मिला है। यह सच है कि रेडियो की साख कमजोर हुई है, मगर आज भी यह अब भी देश में सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच देश की 99.20 प्रतिशत आबादी तक है। देश के 92.6 प्रतिशत भूभाग को यह कवर करता है। ऑल इंडिया रेडियो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से की गई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ।

1957 में इसका नाम बदल कर आकाशवाणी रखा गया। सरकारी प्रसारण संस्थाओं को स्वायत्तता देने के इरादे से 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया, जो देश की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है और इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी को शामिल किया गया है। आकाशवाणी या रेडियो को हिंदी भाषा को जन-जन तक पहुंचाने का श्रेय दिया जा सकता है। आजादी से पूर्व आकाशवाणी अनेकता में एकता का सशक्त माध्यम थी। एक-दूसरे के पास इसी माध्यम से सारी जानकारी पहुंचती थी। आजादी के बाद प्रगति और विकास का एक मात्र सजीव माध्यम बना आकाशवाणी। बड़े-बड़े नेता और महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी बात आकाशवाणी के माध्यम से देशवासियों के समक्ष रखते थे। प्रसारण का एक मात्र साधन होने से देश में इसकी महत्ता और स्वीकार्यता थी। मगर धीरे-धीरे निजी क्षेत्र में प्रसारण माध्यम शुरू हुए। निजी चैनलों से चौबीसों घंटे समाचार और मनोरंजन की सामग्री प्रसारित होने लगी। फलस्वरूप लोगों ने आकाशवाणी से मुंह मोड़ लिया। इससे आकाशवाणी बहुत थोड़े क्षेत्रों में सिमट कर रह गया। मगर जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इसकी सुध-बुध ली, तब से इसका महत्व एक बार फिर बढ़ा। विशेष रूप से प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होना शुरू हुआ तब से एक बार फिर आकाशवाणी लोगों के सिर चढ़ गया। रेडियो अब फिर से आमजन व घरों तक पहुंचने लगा है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सत्य परमात्मा है, सत्य प्रभु से भिन्न नहीं है

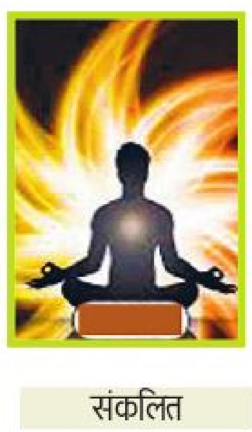

संकलित
दर्शन

सत्य ही सर्वस्व है। सत्य के बिना सदाचार, दान, कीर्ति, धन किसी काम के नहीं। जहां सत्य होगा, वहां ये सभी होंगे। सत्य परमात्मा है। सत्य प्रभु से भिन्न नहीं है। सत्य के द्वारा मनुष्य ईश्वर के निकट जा सकता है। जंगलों, पहाड़ों और वीराने में एकांतवास करना तपस्या नहीं है। जीवन में सच बोलना और सच की राह पर चलना ही सबसे बड़ी तपस्या है। धर्म के चार पद हैं- सत्य, तप, दया और पवित्रता। इन चार चरणों में सत्य सर्वोपरि है। महाभारत में राजा सत्यदेव की कथा आती है। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा कि चंचला लक्ष्मी उनके महल से कुछ समय पश्चात चली जाएगी। एक दिन सुबह जब सत्यदेव उठे, तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को घर से निकलते देखा। राजा ने आश्चर्य से उस स्त्री से पूछा, 'आप कौन हैं?' जवाब मिला, 'मेरा नाम लक्ष्मी है। अब मैं इस घर से जा रही हूं।' राजा ने कहा कि आप जा सकती हैं। लक्ष्मीजी चली गईं। उसके पीछे एक सुंदर पुरुष को बाहर जाते देखकर राजा ने पूछा, 'आप कौन हैं?' उत्तर मिला, 'मेरा नाम दान है। लक्ष्मी के जाने के बाद आप दान नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं आपका घर छोड़ कर जा रहा हूं।' राजा ने कहा कि आप भी जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा सदाचार और चौथा यश, पुरुष के रूप में बाहर आए। राजा के पूछने पर लक्ष्मी तथा दान के साथ जाने की कहने पर राजा ने दोनों को जाने दिया। जब पांचवां पुरुष सत्य जाने लगा, तो राजा ने हाथ जोड़ विनयपूर्वक कहा, 'मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। आप मुझको किसलिए छोड़ रहे हैं?

दुख से मुक्ति ही है असली जीत?

संकलित
प्रेरणा

हमारे जीवन में बहुत अव्यवस्था है। उसे ठीक किए बिना ध्यान का कुछ भी अर्थ नहीं। यदि आप यह सोचकर ध्यान में बैठ जाएं कि इससे व्यवस्था आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपने दैनिक जीवन में सुव्यवस्था स्थापित करें, तब ध्यान की गहराइयों में उतरने का लाभ होगा। सब युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं। इन तैयारियों से विश्व में कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी प्रकार का विस्फोट अवश्य होगा। हम एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्वक कभी भी नहीं रह पाए हैं। शांति के बारे में हम बातें खूब करते हैं। सारे धर्मों ने शांति का ही संदेश दिया है, लेकिन इस धरती पर शांति कभी भी संभव नहीं हो पाई है। यह धरती, जिस पर हम सब रहते हैं, किसी एक देश की नहीं है। यह हम सबकी और हमारी धरती है। इस नफरत का संभवतः एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे हृदय हिंसा से भरे हैं। हम कभी भी शत्रुता के भाव से, प्रतिशोध के भाव से मुक्त नहीं रहे। कभी भी अपने भय, दुख, घावों और प्रतिदिन के जीवन की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाए। हमें कभी शांति नहीं मिली। हम हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं। यह सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हमारे प्रतिदिन के दुखभोग का हिस्सा है। इस प्रेम विरहित दुखभोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य ने कई रास्ते आजमाए हैं। उसने इसका दमन करके देख लिया। किसी श्रेष्ठतर तत्व से अपना तादात्म्य करके देख लिया। किसी आदर्श के लिए, किसी विश्वास के लिए, किसी आस्था के लिए अपने आपको समर्पित कर के देख लिया। फिर भी यह दुख कभी समाप्त नहीं होता। हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

आवारा मवेशियों की समस्या का हल जरूरी

देशभर में आवारा मवेशियों की समस्या दिनोंदिन विकराल होती जा रही है। जहां एक ओर आवारा मवेशी सड़क हादसों का सबब बन रहे हैं, तो दूसरी ओर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज शहर हो या गांव, आवारा मवेशियों के आतंक से कोई अछूता नहीं है। इनके सर्वत्र घूमने से आमजन का अपने घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। सड़क हादसों में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण आवारा मवेशी भी है, जो यातायात व्यवस्था को तो बाधित करते ही हैं साथ ही उनके अचानक बीच सड़क पर आ धमकने से सड़क हादसे भी अंजाम लेते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे घूम रहे हैं आवारा मवेशी और कौन है इनका असली मालिक? साथ ही इनसे होने वाले नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है।

-सूरज कुमार, रायपुर

X ट्रेंड

जयंती पर नमन

स्वराज, स्वदेशी व स्वावलंबन के प्रणेता महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और सामाजिक कुरीतियों के त्याग व स्त्री शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने 'सत्यार्थ प्रकाश' से वैदिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाया। स्वामी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन।

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

वन भूमि पर अतिक्रमण

जो लोग पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा हमें सौंपे गए संकट की भयावहता से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है। 2,676 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है! इसे ठीक करने के लिए भाजपा काम कर रही है!

-हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम, असम

एक हाट में दो दुकान

बात ये नहीं है कि बवाल हुआ, बात ये है कि किसने होने दिया, कहीं ये मामला 'एक म्यान में दो तलवार' या 'एक हाट में दो दुकान' के झगड़े वाला तो नहीं है? अपने गृह-नगर में ही अपना विरोध देखकर उनको भी दुख हुआ, जो दूसरों के दुख दूर करने की बात करते हैं।

- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

बजट निराशाजनक

राजस्थान विस में पेश किया गया बजट न सिर्फ निराशाजनक है, बल्कि प्रदेश की जनता में भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करने वाला है। बजट में कोई घोषणा ऐसी नहीं है जिसे व्यापक जनहित में कहा जा सके।

- अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

सिएटल ने भारतीय छात्रा की मौत के मामले में किया समझौता

अमेरिका के सिएटल शहर ने 2023 में एक पुलिस अधिकारी की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर लगने से जान गंवाने वाली भारत की 23 वर्षीय स्नातकोत्तर छात्रा जाह्नवी कंदुला के परिवार के साथ 2.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर सहमति जताई है। कंदुला को

अधिकारी केविन डेव की गाड़ी ने उस समय टक्कर मारी थी, जब वह मादक पदार्थ संबंधी एक कॉल के बाद कार्रवाई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा वाले क्षेत्र में 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे। उनकी गाड़ी की आपातकालीन लाइट जल रही थीं और चौराहों पर सायरन का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। सिटी अटॉर्नी एरिका इवांस ने बुधवार को जारी बयान में कहा, जाह्नवी कंदुला की मौत हृदयविदारक है और शहर को उम्मीद है कि यह वित्तीय समझौता कंदुला परिवार को कुछ हद तक संतोष प्रदान करेगा। जाह्नवी कंदुला का जीवन महत्वपूर्ण था। यह उनके परिवार, मित्रों और हमारे समुदाय के लिए मायने रखता था। कंदुला सिएटल स्थित नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर में सूचना प्रणाली (इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स) में मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही थीं। कंदुला के परिवार के वकीलों ने तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों पक्षों ने पिछले शुक्रवार को किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में समझौते की सूचना दाखिल की।

ऑफ बीट

कोई भी जीवित जीव 'आदिम' नहीं, फिर भी ऐसी मान्यता क्यों

हम मनुष्य लंबे समय से स्वयं को विकास (इवोल्यूशन) की पराकाष्ठा मानते रहे हैं। अन्य प्रजातियों को अक्सर आदिम या प्राचीन कहा जाता है और उच्च एवं निम्न जीव जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है।

मानव-केंद्रित इस दृष्टिकोण को 1866 में और बल मिला, जब जर्मन वैज्ञानिक अर्न्स्ट हैकेल ने जीवन-वृक्ष (ट्री ऑफ लाइफ) का एक प्रारंभिक चित्र बनाया, जिसमें मनुष्य को स्पष्ट रूप से शीर्ष पर दिखाया गया। इस चित्रण ने यह धारणा लोकप्रिय बनाई कि विकास का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हैं। आधुनिक विकासवादी जीवविज्ञान इस सोच को नकारते हैं। उनके अनुसार विकास में कोई पदानुक्रम नहीं है। आज जीवित सभी प्रजातियां-चिंपैंजी से लेकर बैक्टीरिया तक-एक-दूसरे की संबंधी हैं, जिनकी विकास-रेखाएं समान रूप से लंबी हैं; वे किसी की पूर्वज या उत्तराधिकारी नहीं हैं। इसके बावजूद आदिम जैसी अवधारणाएं वैज्ञानिक पत्रिकाओं और विज्ञान पत्रकारिता में अब भी दिखाई देती हैं। मैंने अपनी नयी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग द ट्री ऑफ लाइफ में लिखा है कि किसी भी वर्तमान प्रजाति को आदिम, प्राचीन या सरल कहना मूलतः भ्रामक है और विकास का इतिहास जटिल, गैर-पदानुक्रमित और परस्पर जुड़ा हुआ है। अंडे देने वाले स्तनधारी मोनोट्रीम कहलाते हैं।

भारत बंद का देशभर में मिलाजुला रहा असर

कई राज्यों में कर्मचारियों, श्रमिकों और वामपंथी दलों ने किया प्रदर्शन

देश के कुछ राज्यों में भारत बंद का असर दिखाई दिया। कोलकाता में कुलियों ने काम बंद रखा और सोते रहे। पंजाब में केवल ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया।

एजेंसी ⏭ कोलकाता

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने और कई सरकारी नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बीच कोलकाता में कुली अपनी गाड़ियों पर सोते रहे।

प्रयागराज और देहरादून में भी ट्रेड यूनियनों के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन

गाड़ियों में सोते रहे कुली

पंजाब में उठी नीतियां वापस लेने की मांग

अमृतसर। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने और कई सरकारी नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान अमृतसर में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया।

श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए

प्रयागराज। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा श्रम संहिताओं को निरस्त करने और नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर बुलाई गई हड़ताल के दौरान गुरुवार को प्रयागराज में कर्मचारियों, श्रमिकों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया।

पुलिस ने यूनियनों को सचिवालय जाने से रोका

देहरादून। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने श्रम संहिताओं को निरस्त करने और कई सरकारी नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान पुलिसने देहरादून में यूनियनों के सदस्यों को उत्तराखंड सचिवालय की ओर मार्च करने से रोका।

सरकारी नीतियों वापस लेने की मांग दोहराई

हैदराबाद। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा चार श्रम कानूनों को निरस्त करने और कई सरकारी नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान कर्मचारियों, श्रमिकों और वामपंथी दलों के सदस्यों ने हैदराबाद में गुरुवार को प्रदर्शन किया।

खबर संक्षेप

शिवम को 20 हजार के मुचलके पर जमानत

कानपुर। यहां के हाई-प्रोफाइल लैंबॉर्गिनी हादसे के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को बुधवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। वकीलों की हड़ताल और अदालती कामकाज के बहिष्कार के बीच विशेष सुनवाई में कोर्ट ने न केवल शिवम की जमानत मंजूर की, बल्कि पुलिस द्वारा मांगी गई रिमांड अर्जी को भी खारिज कर दिया।

प्रसन्ना कुमार बने आईसीएआई के अध्यक्ष

नई दिल्ली। देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने गुरुवार को नए नेतृत्व का ऐलान किया है। आईसीएआई की काउंसिल ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए प्रसन्ना कुमार डी को अपना नया अध्यक्ष चुना है।74वें अध्यक्ष के तौर पर वे अपना कार्यभार संभालेंगे।

पंचोली को राहत नहीं मिली, नोटिस जारी

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली की एक याचिका पर सुनवाई की। इसमें 2019 में मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज दुष्कर्म मामले की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने राहत न देते हुए नोटिस जारी किया है।

संसद की कार्यवाही हंगामे के कारण फिर नहीं चल सकी

विपक्ष ने की नारेबाजी व सदन के बीचोंबीच आकर किया हंगामा... तख्तियां भी दिखाई

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने प्रश्नकाल के लिए एक सदस्य का नाम पुकारा तभी विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा और नारेबाजी करने लगे और सदन के बीचोंबीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की और बिजली राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाईक ने एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के कारण बिजली के क्षेत्र में देश संपन्न हुआ है।

हंगामा बढ़ने पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में तख्तियां लेकर आना नियम के विरुद्ध है इसलिए सदस्य तख्तियों को नीचे रख दें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए सभी अपने अपने स्थान पर जाएं। पीठासीन अधिकारी के आग्रह का कोई असर नहीं हुआ और हंगामा तेज हो गया जिसके कारण सदन को बारह बजे तक स्थगित करना पड़ा।

पीठासीन अधिकारी की समझाइश को भी नकारा

संसद में फिर दिखी सत्तापक्ष विपक्ष के बीच तकरार, आरोप-प्रत्यारोप

संसद में नारेबाजी करता विपक्ष

हंगामे पर चिराग ने बताई आंखों देखी

संसद में उस दिन कुछ भी हो सकता था...

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि 4 फरवरी को लोकसभा में जो कुछ भी हुआ और जो माहौल था, उसमें कुछ अप्रिय घटना घट सकती थी। पीएम मोदी का संबोधन टालने के स्पीकर के फैसले का समर्थन किया। पासवान ने राहुल गांधीपर खुलकर बात की। पासवान ने कहा कि मैं भी उस वक्त संसद में मौजूद था, जब विपक्ष की कुछ महिला सांसद आक्रामक तरीके से बैनर लेकर प्रधानमंत्री की सीट की तरफ बढ़ीं।

विपक्ष को लिया आड़े हाथ

पासवान ने कहा कि विपक्ष का एक पैटर्न है, खासकर कांग्रेस एक मुद्दा पकड़ती है और उस मुद्दे को लेकर सदन को नहीं चलने देती। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल एक ही मुद्दा उठाते रहते हैं और सदन में न वे बोलते हैं और न ही किसी को बोलने देते हैं।

सिर्फ प्रामाणिक मुद्दों पर करें चर्चा

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पासवान ने कहा कि ये गलत है, नेता प्रतिपक्ष को बोलने के बहुत मौके मिले हैं, लेकिन वे सिर्फ एक मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, इसके चलते वे अन्य मुद्दों पर नहीं बोल पाते। संसद के नियम साफ हैं कि सिर्फ प्रामाणिक मुद्दों को ही संसद में उठाया जा सकता है।

राहुल पर भड़के गिरिराज

गेहूं और जौ के पौधे में जरा अंतर बता दें?

नरेंद्र मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता के लिए झूठा, लूच्चा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राहुल पर किसानों का नकली हितैषी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह गेहूं और जौ के पौधे या गाय की बाछा और बाछी की पहचान नहीं कर पाएंगे। मंत्री ने उन पर विदेशों में भारत की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इनकी भी फाइल खुलने वाली है।

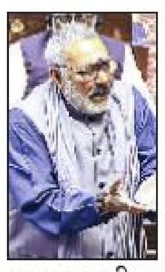

राहुल किसानों के नकली हितैषी

गिरिराज ने कहा कि राहुल जैसा झूठा नेता नहीं देखा। वे किसानों के नकली हितैषी हैं। मेरे साथ खेत में चलकर गेहूं और जौ के पौधे में जरा अंतर बता दें। वे गाय की बाछी और बछड़े को भी पहचान पाएंगे कि कौन किस लिंग का है?

राकांपा की चतुर्वेदी बोलीं

किताब पढ़ना अब आपराधिक कृत्य माना जा रहा, कार्रवाई हो रही

पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब पर सियासी हंगामा मचा है। किताब के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख की किताब पढ़ना अब राजद्रोह, राष्ट्र-विरोधी और आपराधिक कृत्य माना जा रहा है।

डांकुनी-सूरत समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर के क्रियान्वयन के निर्देश रेलवे ने शुरू की फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय बजट 2026 में घोषित डांकुनी–सूरत समर्पित माल ढुलाई कॉरिडो (डीएफसी) के त्वरित क्रियान्वयन के लिए भारतीय रेल ने फास्ट-ट्रैक कार्रवाई शुरू कर दी है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

करीब 2,100 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित यह नया डीएफसी पश्चिम बंगाल के डांकुनी से गुजरात के सूरत तक बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण से पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल परिवहन को नई गति मिलेगी, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था अधिक तेज और दक्ष बनेगी, मालगाड़ियों के आवागमन का समय घटेगा तथा मौजूदा रेल मार्गों पर भीड़भाड़ कम होगी।

अत्याधुनिक तकनीकी मानकों पर जोर

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आधुनिक माल ढुलाई तंत्र को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम तकनीकी मानकों को तुरंत अंतिम रूप दें। प्रस्तावित विशेषताओं में उच्च क्षमता वाली विद्युतीकरण प्रणाली, शून्य लेवल क्रॉसिंग तथा 'कवच' जैसी उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली शामिल हैं। इनसे सुरक्षा में वृद्धि और माल ढुलाई क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है।

डीपीआर का अद्यतन और चरणबद्ध क्रियान्वयन

कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को नवीनतम लागत अनुमान और संशोधित समयसीमा के साथ अपडेट किया जाएगा। इससे परियोजना की बेहतर योजना, बजट प्रबंधन और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

पूर्व-निर्माण गतिविधियों में तेजी

रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि सभी पूर्व-निर्माण गतिविधियों की व्यापक पहचान कर उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जाए। साथ ही, अनुबंध दस्तावेजों की तैयारी भी समानांतर रूप से शुरू करने को कहा गया है, ताकि परियोजना की शुरुआत में किसी प्रकार की देरी न हो। कॉरिडोर के लिए आवश्यक मानव संसाधन (मैनपावर) का आकलन भी किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड को साप्ताहिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट, की गई कार्रवाई और आवश्यक सहयोग के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिससे परियोजना का सुचारु और शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। डांकुनी–सूरत डीएफसी को देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ाने, औद्योगिक विकास को गति देने और 'मेक इन इंडिया' को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारतनेट भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज में बदल रहा हैः सिंधिया

कहा, भारतनेट के तहत 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें जुड़ीं

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि इससे नागरिकों को कई सुविधाएं मिल रही हैं। अब पूरे देश में डिजिटल पहुंच का विस्तार हो रहा है, जो लाभकारी होगा

ब्रॉडबैंड अवसंरचना के विस्तार की वजह से भारत ने एक अरब इंटरनेट ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है, यह बात संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को संसद में कही। उन्होंने बताया कि भारतनेट, दुनिया के सबसे बड़े सरकारी नेतृत्व वाले कनेक्टिविटी कार्यक्रमों में से एक, डिजिटल विभाजन को पाटने और ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहा है।

राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि भारतनेट भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। सिंधिया ने कहा 'पिछले ग्यारह वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार देखा है, जो ऐतिहासिक डिजिटल परिवर्तन को गति दे रहा है।

मंत्री ने उल्लेख किया कि मोबाइल ग्राहकों की संख्या 2014 में 930 मिलियन से बढ़कर आज 1.2 अरब हो गई है, जबकि मोबाइल पहुंच 75 प्रतिशत से बढ़कर 92 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 2014 में 250 मिलियन से बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गई है, जबकि पहुंच 20 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 71.8 प्रतिशत हो गई है। ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या भी 61

मिलियन से बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गई है, जबकि औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड अब लगभग 61.55 एमबीपीएस है।

भारतनेटः भारत के ग्राम पंचायतों को जोड़ना

भारतनेट ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाकर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। देश की 2,56,000 ग्राम पंचायतों में से लगभग 2,14,000 को भारतनेट चरण I और II के तहत ऑनलाइन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 42,000 करोड़ रुपये है। तमिलनाडु में, राज्य ने बीएसएनएल के बजाय अपनी विशेष प्रयोजन वाहन तनफिनेट के माध्यम से परियोजना को लागू करने का विकल्प चुना। राज्य की 12,525 ग्राम पंचायतों में से 10,869 जुड़ चुकी हैं। शेष ग्राम पंचायतें और 4,767 गैर-ग्राम पंचायत गांव संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत कवर किए जाएंगे, जो 16.9 अरब डॉलर लागत की पहल है और वैश्विक रूप से सबसे बड़ा सरकारी नेतृत्व वाला कनेक्टिविटी कार्यक्रम है।

मंत्री ने सदन को आगे सूचित किया कि 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च किए गए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) 2.0 ने 2030 के लिए सात प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैंः दिसंबर 2025 तक 42,000 गांवों में 95 प्रतिशत अपटाइम के साथ ओएफसी कनेक्टिविटी हासिल की गई है, 2030 तक 2.7 लाख गांवों का लक्ष्य। स्कूलों, आंगनवाड़ियों और पंचायत कार्यालयों जैसी एंकर संस्थानों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 68.8 प्रतिशत पहुंच गई है, 2030 तक 90 प्रतिशत का लक्ष्य। राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 61.55 एमबीपीएस है, 2030 तक 100 एमबीपीएस का लक्ष्य। औसत राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) आवेदन निस्तारण समय 455 दिनों से घटकर 30.4 दिन हो गया है, जो 2030 के लक्ष्य से पहले हासिल हो गया

केंद्र ने हरियाणा, हिमाचल, यूपी में निकायों के लिए 3,324 करोड़ जारी किए

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त स्वीकृत एवं जारी की है ताकि जमीनी स्तर पर शासन को और ज्यादा सशक्त एवं आवश्यकता आधारित स्थानीय विकास को सक्षम बनाया जा सके। इस किश्त के अंतर्गत, बिहार को 802.40 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे सभी 38 जिला पंचायतों (डीपी), 533 ब्लॉक पंचायतों (बीपी) और 8,053 ग्राम पंचायतों (जीपी) को लाभ हुआ है, साथ ही 3 ब्लॉक पंचायतों और 7 ग्राम पंचायतों के लिए पहली किश्त के रोके गए हिस्से से 1.39 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई है, जो अब इसका पात्र बन चुकी हैं। इसी प्रकार, हरियाणा में पात्र 19 डीपी, 138 बीपी और 6,194 जीपी को कवर करते हुए 197.627 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, साथ ही पहले रोकी गई राशि से अतिरिक्त पात्र 1 डीपी, 4 बीपी और 30 जीपी को 249.80 लाख रुपए 2.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश के लिए, सभी 12 जिला पंचायतों, पात्र 80 ब्लॉक पंचायतों और 3,602 ग्राम पंचायतों के लिए 6,830.03 लाख रुपए (68.30 करोड़ रुपए) जारी किए गए, साथ ही 26 अतरिक्त पात्र ग्राम पंचायतों को 34.53 लाख रुपए (0.35 करोड़ रुपए) भी जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों और 57,694 ग्राम पंचायतों के लिए 1,55,940.00 लाख रुपए (1,559.40 करोड़) जारी किए गए, इसके अलावा, रोके गए हिस्से से 2 डीपी, 13 बीपी और 61 जीपी को 1,101.64 लाख रुपए (11.016 करोड़ रुपए) भी जारी किए गए, जो पात्रता प्राप्त कर चुके हैं।

पश्चिम बंगाल को इसी किस्त के अंतर्गत पात्र 21 डीपी, 335 बीपी और 3,225 ग्राम पंचायतों के लिए 680.86 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को पंद्रहवीं वित्त निधि अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है।

intec CAPITAL LIMITED
SAPNE AAPKE, BHAROSA APNO KA
इंटेक कैपिटल लिमिटेड
CIN: L74899DL1994PLC057410
पंजी. कार्यालय : 708, मंजूषा बिल्डिंग, 57 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019
T-+91-11-46522200/300; F-+91-1146522333 Website: www.inteccapital.com

31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु स्टैंडअलोन एवं समेकित अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(प्रति इक्विटी शेयर डेटा को छोड़कर रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन						समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वार्षिक	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वार्षिक
		31.12.2025 (अअंकेक्षित)	30.09.2025 (अअंकेक्षित)	31.12.2024 (अअंकेक्षित)	31.12.2025 (अअंकेक्षित)	31.12.2024 (अअंकेक्षित)	31.03.2025 (अंकेक्षित)	31.12.2025 (अअंकेक्षित)	30.09.2025 (अअंकेक्षित)	31.12.2024 (अअंकेक्षित)	31.12.2025 (अअंकेक्षित)	31.12.2024 (अअंकेक्षित)	31.03.2025 (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	220.66	83.43	41.48	927.18	56.40	436.53	220.85	83.63	43.93	927.77	63.65	445.59
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	8.67	(19.92)	(48.00)	508.99	(247.78)	124.00	4.61	(23.96)	(49.69)	496.85	(253.02)	115.88
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	8.67	(19.92)	(48.00)	384.61	(247.78)	124.00	4.61	(23.96)	(49.69)	327.47	(253.02)	115.88
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(35.09)	(55.93)	(63.69)	210.27	(282.58)	30.04	(39.15)	(59.97)	(65.38)	198.13	(287.82)	21.92
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(35.43)	(56.25)	(63.17)	209.27	(281.01)	28.70	(39.49)	(60.29)	(64.86)	197.13	(286.25)	20.58
6	भुगतान किया गया इक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63
7	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) (निरंतर और अनिरंतर प्रचालनों हेतु)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1. बेसिक (रु. में) :	(0.19)	(0.30)	(0.35)	1.14	(1.54)	0.16	(0.21)	(0.33)	(0.36)	1.08	(1.57)	0.12
	2. डायल्युटेड (रु. में) :	(0.19)	(0.30)	(0.35)	1.14	(1.54)	0.16	(0.21)	(0.33)	(0.36)	1.08	(1.57)	0.12

टिप्पणी :-
(1) उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये गये अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स यथा www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट यथा www.inteccapital.com पर उपलब्ध हैं।
(2) उपरोक्त फाइनैंशियल्स की समीक्षा कर ली गई है और ऑडिट कमेटी द्वारा अनुशंसित कर दिये गये तथा तदोपरांत 12 फरवरी 2026 को आयोजित उनकी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये और रिकार्ड पर लिये गये।

कृते इंटेक कैपिटल लिमिटेड
हस्ता/-
निहारिका गुप्ता
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एम. नं.-ए59325

दिनांक : 12.02.2026
स्थान : नई दिल्ली